

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



जुलाई 2019

खंड 73 अंक 7

संपादन समिति

राजीव रंजन
डी. पी. रथ
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
एस. गंगाधरन
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवडकर

संपादक

शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2019

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

केंद्रीय बैंकों की बढ़ती हुई भूमिका	1
शिकायत प्रबंधन प्रणाली के शुभारंभ पर गवर्नर महोदय का वक्तव्य	7
राज्यपाल का उद्घाटन समारोह - वार्षिक सांख्यिकी दिवस सम्मेलन	9
व्यवहार्य वित्तीय बाजार का विकास - भारतीय अनुभव	13

लेख

भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और उसका व्यापक आर्थिक प्रभाव	25
2011-12 से 2017-18 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय भण्डार और प्रवाह	41

वर्किंग पेपर और ओकेजनल के कागजात की प्रेस प्रकाशनियां

सीमा-पार व्यापार क्रेडिट : आर्थिक संकट के बाद भारत से संबंधित अनुभवजन्य विश्लेषण	59
क्या भारत में वित्तीय चक्र मौजूद है ?	61

वर्तमान सांख्यिकी 63

हाल के प्रकाशन 107

अनुपूरक

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2019

भाषण

केंद्रीय बैंकों की बढ़ती हुई भूमिका

शक्तिकान्त दास

शिकायत प्रबंधन प्रणाली के शुभारंभ पर गवर्नर महोदय का वक्तव्य

शक्तिकान्त दास

राज्यपाल का उद्घाटन समारोह - वार्षिक सांख्यिकी दिवस सम्मेलन

शक्तिकान्त दास

व्यवहार्य वित्तीय बाजार का विकास- भारतीय अनुभव

विरल वी. आचार्य

केंद्रीय बैंकों की बढ़ती हुई भूमिका*

शक्तिकान्त दास

आईएस अधिकारियों के लिए मिड करियर कार्यक्रम के पंचम चरण के उद्घाटन हेतु यहाँ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। इस महती प्रशिक्षण संस्था के साथ मेरी भी बहुत-सी सुखद यादें जुड़ी हुई हैं। मैं भी 1980 में आईएस का कार्यग्रहण करने के बाद यहाँ आया था। मैं इस अकादमी के निदेशक श्री संजीव चोपड़ा और संकाय सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस भव्य समारोह को संबोधित करने हेतु मुझे आमंत्रित किया।

मैं इस बारे में आश्चर्य हूँ कि आप में से प्रत्येक ने कठिन परिश्रम किया है और अपने लंबे करियर के मार्ग में कई मुकाम हासिल किए होंगे। आप इस समय जहाँ पर हैं, वह आपके करियर का एक महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि अब आप भारतीय प्रशासनिक संरचना में और भी उच्चतर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप में से अधिकांश ने लगभग 28 से 31 वर्ष इस सेवा में गुजार दिये होंगे। अब आप केंद्र और राज्य सरकारों के शीर्षस्थ पदों पर जाने वाले होंगे। इन स्तरों पर आप पर नीति-निर्माण के साथ-साथ, प्रमुख कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन को भी दिशा देने का दायित्व भी रहेगा। आपको विभिन्न नीतिगत विकल्पों के औचित्य को सावधानी से तौलते हुए और उनका आकलन करते हुए, सरकार को भावी दिशा पर सलाह देनी होगी। ऐसी उच्च पोजीशन में अपनी भूमिका निभाते हुए यह बहुत जरूरी है कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की दो बातों का हमेशा ध्यान रखें: (i) “वह परिवर्तन स्वयं बनो जो तुम देखना चाहते हो।” और (ii) “आपने जिस किसी भी निर्धनतम और सबसे ज्यादा असहाय व्यक्ति को देखा हो, उसका चेहरा याद कीजिये और स्वयं से पूछिए कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं, क्या उसके लिए यह किसी भी प्रकार से उपयोगी होंगे?”

नेतृत्व के वरिष्ठ ओहदे में आपके पास इस राष्ट्र के लोगों के जीवन में एक बदलाव लाने की शक्ति रहेगी। साथ ही उन लोगों के जीवन में भी बदलाव लाने की शक्ति आपके पास रहेगी जिनका आप नेतृत्व करेंगे। तय कर लीजिये कि आप उनके विश्वसनीय

सलाहकार बनें और अपनी टीम को मार्ग दिखाइये, प्रेरित कीजिये कि वे स्वयं को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करें। मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप विभिन्न स्तरों पर हमारी इस ब्यूरोक्रेसी के कार्यचालन में प्रणालीगत बदलावों का सूत्रपात करें ताकि लोक योजनाओं और नीतियों की डिलिवरी को और भी सुधारा जा सके। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का काम आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता बने।

किसी भी प्रकार का नीति-निरूपण एक प्रकार से सीखने की प्रक्रिया ही है, और नीति-निर्माता अतीत के अनुभवों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इसलिए आज मैंने बोलने के लिए जो विषय चुना है, वह है- “केंद्रीय बैंकों की बढ़ती हुई भूमिका”।

केंद्रीय बैंकों का आविर्भाव

केंद्रीय बैंकिंग की शुरुआत काफी पहले 17वीं शताब्दी में सन 1668 में स्वीडन के रिक्सबैंक की स्थापना के साथ हुई, और तब से मौद्रिक प्राधिकरणों की भूमिका और कार्यचालनों में बहुत से बदलाव हो चुके हैं। प्राचीनतम केंद्रीय बैंकों में से कुछेक की स्थापना तो सरकारों को युद्धकालीन वित्तपोषण प्रदान करने और उनकी देनदारियों का प्रबंधन करने के लिए हुई थी। तब से इनकी भूमिका समय के साथ-साथ क्रमिक रूप से विकसित होती गई है। अब ये आधुनिक काल के ऐसे केंद्रीय बैंकों में रूपांतरित हो गए हैं, जो कीमत और वित्तीय स्थायित्व हासिल करते हुए संधारणीय आर्थिक संवृद्धि में मदद करने के लक्ष्य को सामने रखते हुए कार्य करते हैं।

भारत के मामले में हिल्टन-यंग आयोग (1926) ने भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के लिए अपनी सिफ़ारिश की थी, और इस बैंक को विशुद्ध केंद्रीय बैंकिंग के कार्य सौंपे जाने थे। लेकिन इसका भी काफी पुराना इतिहास है क्योंकि सन 1773 से ही भारत में ऐसी बैंकिंग संस्था स्थापित करने के प्रयास शुरू हो गए थे, जिसमें केंद्रीय बैंक के भी कुछ तत्व विद्यमान हों। परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई और इसने अपना कार्य 01 अप्रैल, 1935 से आरंभ कर दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत इसके कार्यचालन को सांविधिक आधार प्रदान किया गया। मूल रूप में इसकी स्थापना शेयरधारकों के बैंक के रूप में हुई थी, तथा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद समय के साथ-साथ इसकी भूमिका में बदलाव होते रहे और यह अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध विकास में सहायता देने से लेकर पूर्ण सेवादाता केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है।

* 17 जून, 2019 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण

विश्वव्यापी वित्तीय संकट के दौरान केंद्रीय बैंकों की भूमिका

अब मैं संकट काल के दौरान केंद्रीय बैंकों की भूमिका पर विस्तार से कुछ कहना चाहूँगा। यद्यपि यह सत्य है कि संकट के कारण सुधार भी होते हैं, तथापि अनुभवों से तो यही दिखाई देता है कि अन्य बाहरी और जटिल कारक भावी वित्तीय संकटों की तरफ ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सन 1997 में हुए पूर्वी-एशियाई संकट के दौरान बहुत-सी उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में विनियमन और पर्यवेक्षण की अपर्याप्तताओं से सीख लेने के बावजूद, सन 2008 में उन्नत देशों से आरंभ हुए विश्वव्यापी संकट को टाला नहीं जा सका। यद्यपि इस संकट के सर्वाधिक समसमान लक्षणों में चालू खाते में बड़े घाटे, राजकोषीय असंतुलन, अत्यधिक लीवरेज से हुई समष्टि-आर्थिक कमजोरियाँ और वित्तीय संस्थानों का अपर्याप्त विनियमन और पर्यवेक्षण ही थे, लेकिन कहीं ज्यादा प्रखरता और गहराई लिए हुए यह सचमुच विश्वव्यापी प्रकार का ही था।

विश्वव्यापी वित्तीय संकट का प्रभाव कई देशों में जिस तेजी से संचरित हुआ, उस गति को देखते हुए नीतिगत प्रतिसाद करने के लिए एक बार फिर केंद्रीय बैंक ही सामने आए। हालांकि इस बार वित्तीय बाजारों में आयी खलबली को रोकने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा आदर्श मौद्रिक नीतिगत प्रतिसाद पर्याप्त नहीं थे। सन 2007 की गर्मियों में प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने पारंपरिक मौद्रिक नीति उपायों को अपनाते हुए ब्याज दरों को कम कर दिया। लेकिन आर्थिक स्थिति धराशायी होती गई और केंद्रीय बैंकों को अपने पारंपरिक नीतिगत उपायों की किट में इतनी गुंजाइश नहीं बची कि वे अपने देश के वित्तीय स्थायित्व का बचाव कर सकें। इस प्रकार केंद्रीय बैंकों ने प्रणालीगत जोखिमों को काबू में करने के लिए अपारंपरिक नीतिगत उपायों के माध्यम से मात्रात्मक सहजता (Quantitative easing) लाने का उपाय अपनाते हुए बैंकिंग प्रणाली में भरोसा बढ़ाया और आर्थिक मंदी को नियंत्रित किया। लिखतों और परिचालन लक्ष्यों की दृष्टि से ये नीतिगत उपाय अपारंपरिक थे।¹ निसंदेह, केंद्रीय बैंकों ने जो मात्रात्मक सहजता अपनाई, वह केंद्रीय बैंकिंग के आधुनिक इतिहास में सर्वाधिक निर्भीक नीतिगत उपायों में से एक था। एक और अपारंपरिक उपाय था- नीतिगत

ब्याज की ऋणात्मक दरों का प्रयोग, यद्यपि इसका प्रयोजन अलहदा उद्देश्यों को प्राप्त करना था। इन अपारंपरिक नीतिगत उपायों का प्रभाव अब सर्वविदित है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सृजित चलनिधि की बड़ी मात्रा उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में प्रतिलाभ की प्रत्याशा में लगाई गई, जिससे इन अर्थव्यवस्थाओं में उत्थान और पतन चक्रों का सृजन हुआ।

संकट के प्रति विनियामक प्रतिसाद

पर्यवेक्षी और विनियामक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस संकट ने प्रणाली में कुछ अहम कमजोरियों को उजागर कर दिया। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने इन दुर्बलताओं को सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया है: तुलनपत्र में शामिल और इससे इतर लीवरेज की अत्यधिक मात्रा और उसके साथ पूंजी-आधार के स्तर और गुणवत्ता में क्रमिक गिरावट; चलनिधि का अपर्याप्त बफर; चक्रीयता-समर्थक डिलीवरेजिंग प्रक्रिया; और जटिल लेनदेनों के व्यूह के माध्यम से प्रणालीबद्ध संस्थानों से अंतर्संबद्धता।² बासेल-III व्यवस्था के रूप में जिस विश्वव्यापी विनियमन प्रतिक्रिया ने आकार ग्रहण किया, उसका फोकस पूंजी के स्तर और गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने, बैंक लीवरेज पर काबू रखने, बैंक चलनिधि को सुधारने और चक्रीयता-समर्थक तत्वों को परिसीमित करने के साथ-साथ, विनियमों में समष्टि-विवेकपूर्ण तत्वों को जोड़ने पर रहा।

पारंपरिक रूप से विवेकपूर्ण मार्ग अपनाते हुए बासेल-III सुधारों के कार्यान्वयन में भारत की प्रक्रिया समयबद्धता और अपेक्षाओं की दृष्टि से कुछ कठोर रही है। वित्तीय क्षेत्र के विनियमन हेतु भारतीय दृष्टिकोण को स्वदेशीय कारकों और नीतिगत प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन बरकरार रहा। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी अपेक्षाओं, प्रति-चक्रीय पूंजी बफर, लीवरेज अनुपात, चलनिधि कवरेज अनुपात और निवल स्थायी निधियाँ अनुपात की एक व्यवस्था लागू की है।³ अभी हाल ही में बड़े जोखिमों के बारे में दिशानिर्देश जारी हुए, जो 01 अप्रैल, 2019 से लागू हो चुके हैं।

¹ उदाहरण के लिए वित्तीय संस्थानों को उधार देना, क्रेडिट बाजारों के लिए लक्ष्यबद्ध चलनिधि प्रावधान, लोक और निजी आस्तियों की एकमुश्त खरीद, सरकारी बॉन्ड की खरीद और फॉरवर्ड गाइडेन्स।

² बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (2010): 'बासेल-III : ए ग्लोबल रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रेजिलिएंट बैंक्स एन्ड बैंकिंग सिस्टम्स', दिसंबर।

³ पहली अप्रैल, 2020 से लागू किए जाने हैं।

भारत सहित सभी उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में दबाव का एक और सोपान 2013 के मध्य में टेपर-वार्ता अवधि के दौरान दिखाई दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय बहुत जर्जर थी क्योंकि लगभग 10 प्रतिशत की उच्च स्फीति दर थी और चालू खाते का बड़ा घाटा जीडीपी के 4.7 प्रतिशत पर था। रिज़र्व बैंक ने बहुत से नीतिगत उपायों का सहारा लिया जिसमें मौद्रिक कसाव, स्वर्ण आयात पर प्रतिबंध, सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए विशेष डॉलर स्वैप विन्डो, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) डिपॉजिट आकर्षित करने हेतु विशेष रियायती विन्डो, बैंकों द्वारा विदेशी उधार लेने की सीमा में बढ़ोतरी, और सरकारी ऋणों में विदेशी संस्थागत निवेश सीमाओं को बढ़ाना शामिल था।

हमने क्या सीखा ?

विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का सामना करने वाले इन नीतिगत मुद्दों के लिए कोई अद्वितीय समाधान नहीं है, तथापि हम तीन मोटे-मोटे निष्कर्ष निकाल सकते हैं:

- (i) प्रथम, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कि सामान्य समय के साथ-साथ संकट के समय केंद्रीय बैंकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि केंद्रीय बैंकों को सौंपे गए कार्य सामान्य और दबाव – दोनों ही अवधियों में मोटे तौर पर एक जैसे ही रहते हैं, तथापि संकट के काल में स्पर्धी उद्देश्यों और नीतिगत उपायों के चयन के साथ कुछ गुरुता जुड़ जाती है।
- (ii) दूसरे यह कि केंद्रीय बैंकों द्वारा संवाद करना अहम हो जाता है, हालांकि संकट काल और सामान्य काल में यह अलग-अलग हो सकता है। इससे न केवल निर्णयों को अधिक पारदर्शी तरीके से संप्रेषित करने में मदद मिलती है बल्कि इससे केंद्रीय बैंकों के वर्तमान और भावी नीतिगत रुख का संकेत भी मिल जाता है। वस्तुतः संकट काल के दौरान केंद्रीय बैंकों द्वारा जो अपारंपरिक मौद्रिक उपाय किए गए, उन्होंने मुख्यतया भरोसे और संकेतक चैनलों के माध्यम से काम किया। यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा 16 दिसंबर 2008 को जो वक्तव्य दिया गया, उसमें बाजारों के लिए स्पष्ट भावी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। दूसरी तरफ यूएस फेड (जो टेपर टैंट्रम के नाम से विख्यात है) ने मई 2013 में मौद्रिक नीति को सामान्य बनाने का संकेत मात्र दिया और कई उदीयमान बाजार

अर्थव्यवस्थाओं से पोर्टफोलियो का बहिर्वाह शुरू हो गया।⁴ इससे इक्विटी, ऋण और मुद्रा बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता आ गई। दरअसल, मौद्रिक नीति समायोजन को आंशिक रूप से हटाने के बारे में स्पष्ट अग्रिम संवाद के माध्यम से उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी अस्थिरताओं से बचा जा सकता था।

भारतीय संदर्भ में देखें तो वर्तमान और बदली हुई समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर 'नीतिगत रेपो दर' और 'रुख' में परिवर्तन की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक अपने मौद्रिक नीति निर्णयों पर संवाद करता है। मौद्रिक नीति पर अपने रुख को, 04 प्रतिशत \pm 02 प्रतिशत के मध्यावधिक स्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के अधिदेश के अनुरूप रखते हुए-निरपेक्ष, समायोजक अथवा अनुसंशोधित कसावट के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, और साथ ही संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। रिज़र्व बैंक अपने नीतिगत रुख को, इसका औचित्य बताते हुए, जानकारी देते हुए और विश्लेषण करते हुए स्पष्ट करता है ताकि बाजार के सहभागी और हितधारक बदलती हुई स्थिति के बारे में रिज़र्व बैंक के आकलन को और अधिक स्पष्ट ढंग से समझ सकें।

- (iii) तीसरे यह कि यह विश्वव्यापी आर्थिक संकट इस तथ्य का भी प्रमाण था कि समष्टि-आर्थिक स्थायित्व के लिए विश्वव्यापी और स्वदेशीय- दोनों स्तरों पर नीतियों का समन्वय महत्वपूर्ण होता है। केंद्रीय बैंकों के बीच और स्वदेशीय कार्यक्षेत्र में मौद्रिक और राजकोषीय प्राधिकरणों के बीच केवल बेहतर समन्वय ही है, जिससे अतिशयता और न्यूनता के प्रतिकूल परिणामों पर काबू किया जा सकता है। तथापि यह तथ्य तो रह ही जाता है कि अधिकांश नीति-निर्माताओं (मौद्रिक और राजकोषीय) को स्वदेशीय अधिदेश मिले होते हैं, ऐसे में यदि अंतरराष्ट्रीय परिणाम स्वदेशीय नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ संघर्षी प्रतीत हों तो अंतरराष्ट्रीय समन्वय को हासिल कर पाना कठिन

⁴ मुख्यतया पाँच उदीयमान बाजार देशों, यथा- ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की (जिन्हें 'पंच-भंगुर' (Fragile Five) का नाम दिया गया) से यह बहिर्वाह हुआ।

हो जाता है। इसलिए समन्वय की सफलता प्रमुख हितधारकों द्वारा नीतियों के निपुण अनुसंधान पर निर्भर करेगी।

वर्तमान संदर्भ में समस्याएँ

यहाँ तक कि विश्वव्यापी वित्तीय संकट का एक दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने और टेपर टैनट्रम (नीतियों को शिथिल बनाने की प्रक्रिया) के छह वर्ष के बाद भी विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था अभी तक सुस्थिर संवृद्धि-पथ पर नहीं है। सन 2017 में उठान के बाद तो यह प्रमाण मिल रहे हैं कि विश्वव्यापी संवृद्धि और व्यापार कमजोर पड़ते जा रहे हैं। व्यापार तनावों का कोई समाधान नहीं हो पाने और ब्रेक्सिट गतिविधियों से समूचे क्रियाव्यापार पर और भी गिरावट का जोखिम पड़ता दिखाई दे रहा है। यद्यपि सन 2019 के आरंभ में विश्व औद्योगिक उत्पादन और व्यापार की मात्रा में कमजोरी के संकेत दिखाई दिये, बहुत-से ओईसीडी देशों में अन्य कारोबारी अनुमान संकेतकों में भी नरमी रही है। इन कारकों को संज्ञान में लेते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और ओईसीडी ने अपने नवीनतम आकलनों में सन 2019 के लिए संवृद्धि अनुमानों में संशोधन किया है। इसी प्रकार यह भी अनुमान लगाया गया है कि विश्वव्यापी व्यापार अगले दो वर्षों में मामूली गति से बढ़ेगा। यह अनुमान कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में निवेश के धीमे परिदृश्य के अनुरूप ही है।

यद्यपि अभी विश्व की अर्थव्यवस्था को संकट-पूर्व के संवृद्धि-पथ पर अभी आना बाकी है, तथापि भारत ने विगत तीन वर्ष में उपभोग और निवेश मांग द्वारा संचालित प्रबल संवृद्धि का प्रदर्शन बरकरार रखा हुआ है। हालांकि अभी हाल ही की अवधि में 2018-19 की दूसरी छमाही में हमने गति में कुछ कमी देखी है, क्योंकि संवृद्धि के कुछ प्रेरकों, खासकर निवेश और निर्यातों में धीमापन आया। प्रत्याशा है कि चुनावी मौसम के साथ जुड़ी राजनैतिक अस्थिरता के समापन के साथ ही आर्थिक सुधारों की निरंतरता हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ संकेतकों में विद्यमान कमजोरी को दूर करने की तरफ ले जाएगी।

निवेश परिदृश्य को सुधारकर संवृद्धि में फिर से प्राण फूंकने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र एक अहम भूमिका निभाता है। इस परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक ने बैंकिंग और गैर-बैंकिंग दोनों ही क्षेत्रों में सुधार करने पर अत्यधिक नीतिगत ध्यान दिया है। बैंकिंग प्रणाली की आघात-सहनीयता को बढ़ाने के लिए

हमने विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं को मजबूत करने हेतु कई कदम उठाए हैं। दबावग्रस्त आस्तियों का निपटारा करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं जो क्रेडिट संस्कृति में सुधारों को कायम रखेंगे।

गैर-बैंकिंग क्षेत्र में रिजर्व बैंक हाल ही में दिशानिर्देशों के प्रारूप के साथ आया है, ताकि एनबीएफसी के लिए प्रबल चलनिधि व्यवस्था की जा सके। हम उनकी विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था को नए तरीके से देख रहे हैं। हमारा यह प्रयास है कि विनियमन और पर्यवेक्षण का इष्टतम स्तर बनाए रखें ताकि एनबीएफसी क्षेत्र को वित्तीय रूप से आघात-सहनीय और प्रबल बनाया जा सके। रिजर्व बैंक इस क्षेत्र के क्रियाकलापों और कार्यनिष्पादन की देखरेख जारी रखेगा, जिसमें प्रमुख संस्थाओं और अन्य क्षेत्रों के साथ उनके अंतः-संबंधों पर फोकस रखा गया है। वित्तीय स्थायित्व को बरकरार रखने के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने में रिजर्व बैंक संकोच नहीं करेगा।

हम शहरी सहकारी बैंकों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुधारने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इन उपायों में व्यापक स्तर पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए छत्र-संगठन (Umbrella Organisation) और केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सेंट्रलाइज्ड फ्रॉड रजिस्ट्री) की स्थापना और गवर्नेंस में सुधारों के प्रस्ताव हैं। हम इस क्षेत्र में स्वैच्छिक समामेलन (Voluntary Merger) और समेकन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि परिचालन लागतों को कम किया जा सके और जोखिमों का विविधीकरण हो सके और पूंजी में किफायत रहे।

मुद्रास्फीति और संवृद्धि के उद्देश्यों के बीच पारस्परिक क्रिया

अब अंत में मैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत दिये गए अधिदेश के संदर्भ में रिजर्व बैंक की भूमिका पर प्रकाश डालना चाहूँगा: “बैंक नोट निर्गमन को नियंत्रित करने और भारत में मौद्रिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतया देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली का इसके लाभ हेतु परिचालन”। इस अधिदेश की व्याख्या समय-समय पर कीमतों में स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व और आर्थिक संवृद्धि को बरकरार रखने के रूप में की जाती रही है, जिसमें विद्यमान समष्टि-आर्थिक स्थितियों के सापेक्षतया आर्थिक संवृद्धि को भी ध्यान में रखा गया है। रिजर्व बैंक की इस भूमिका का पुनर्कथन मई, 2016 में रिजर्व बैंक अधिनियम में किए गए

संशोधन के अनुसार इस प्रकार किया गया, यथा- “मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य संवृद्धि के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए कीमत में स्थिरता बनाए रखना है।” इसलिए रिज़र्व बैंक में हमारा यही प्रयास है कि स्फीति पर लोचशील नियंत्रण के विधान के तहत कीमत स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ, स्फीति को नियंत्रण में रखते हुए संवृद्धि पर फोकस करें।

स्फीति नियंत्रण की लोचशील व्यवस्था में मुद्रास्फीति और संवृद्धि उद्देश्यों के बीच एक सौम्य संतुलन रखने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति और संवृद्धि पर सापेक्षिक ज़ोर दिया जाना विद्यमान समष्टि-आर्थिक परिदृश्य, मुद्रास्फीति और संवृद्धि संबंधी दृष्टिकोण और प्राप्त हो रहे डेटा से मिलने वाले संकेतों पर निर्भर करता है। विश्वव्यापी वित्तीय संकट के बाद यह मान्यता बनी कि वित्तीय स्थायित्व के लिए केवल कीमतों की स्थिरता पर्याप्त नहीं हो सकती और इसलिए मौद्रिक नीति के लिए वित्तीय स्थायित्व एक अन्य अहम विचारधारा के रूप में सामने आया, हालांकि ज्यूरी गण अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि इसे मौद्रिक नीति के सुस्पष्ट उद्देश्य में शामिल किया जाए अथवा नहीं। यह तथ्य तो रहेगा ही

कि यद्यपि मौद्रिक नीति का फोकस मुख्यतया मुद्रास्फीति और संवृद्धि पर रहता है, तथापि इसकी आंतरिक विषयवस्तु हमेशा ही वित्तीय स्थायित्व ही रही है।

समापक निष्कर्ष

यद्यपि भारत इस विश्वव्यापी संकट से सापेक्षतया बचा ही रहा, लेकिन इसमें आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत-सी बहुपक्षीय संस्थाओं के सदस्य के रूप में भारत ने जी-20 और बासेल समिति के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था के तहत संकट उपरांत सुधारों में सक्रिय सहभागिता की है। अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम परिपाटियों को चरणबद्ध रूप से, और जहां भी जरूरी हो, अपनी स्वदेशीय स्थितियों के अनुसार इनमें अनुसंधान करके इनको अंगीकृत करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है।

रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण से देखें तो सभी हितधारकों के साथ प्रभावी संवाद और समन्वय पर हमारा फोकस निरंतर रहेगा ताकि कीमत स्थिरता, संवृद्धि और वित्तीय स्थायित्व के व्यापक समष्टि-आर्थिक उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।

शिकायत प्रबंधन प्रणाली के शुभारंभ पर गवर्नर महोदय का वक्तव्य*

शक्तिकांत दास

शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS), का आज शुभारंभ किया जा रहा है, जो रिजर्व बैंक में प्राप्त शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करते हुए शिकायत निवारण प्रक्रिया में ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए RBI की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं इस अवसर पर सभी आरबीआई विनियमित सार्वजनिक संस्थाओं जैसे वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आदि से ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और सार्थक तरीके से समाधान करने के लिए सहयोग की अपेक्षा करता हूँ ताकि वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ावा दिया जा सके। शिक्षा के माध्यम से ग्राहकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण के माध्यम से बैंकों और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) में ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना, बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

सीएमएस किसी भी विनियमित संस्था के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर एकल खिड़की प्रदान करने के साथ ग्राहक सुविधा में सुधार का उद्देश्य रखता है। शिकायत, लोकपाल / क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित कार्यालय को दी जाएगी। यह एप्लिकेशन ऑटो-जनरेट प्राप्त सूचना के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को सूचित करता है और उनकी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने तथा जहां लागू हो लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध ऑनलाइन अपील दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हुए पारदर्शिता में सुधार करता है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता निवारण प्राप्त करने के अपने अनुभव पर स्वेच्छा से अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं।

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, 24 जून, 2019 को।

सीएमएस डेस्कटॉप के साथ-साथ मोबाइल सेट पर भी उपलब्ध होगा। रिजर्व बैंक ने शिकायतों की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समर्पित इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) प्रणाली शुरू करने की भी योजना बनाई है। मुझे यकीन है, समय के साथ, सीएमएस को ग्राहक के अनुकूल बेहतर बनाया जाएगा।

जैसा कि पहले कहा गया है, ग्राहक जागरूकता ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक सक्षम उपकरण है। एक सतर्क और जागरूक ग्राहक गलत बिक्री, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और इस तरह के अन्य खतरों के जोखिमों के विरुद्ध प्रभावी रूप से अपनी रक्षा कर सकता है। जागरूकता प्रचार के हमारे प्रयास में, हमने सीएमएस पोर्टल पर, स्पोर्ट्सपर्सन सहित युवा रोल-मॉडल के साथ वीडियो, सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं पर और भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य महत्वपूर्ण ग्राहक-केंद्रित विनियामक पहलों को रखा है।

बैंकों / वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) के नोडल अधिकारियों को सीएमएस तक सहज पहुंच से ही वित्तीय प्रणाली को इसका लाभ होगा। सीएमएस प्रत्येक संस्था से संबंधित शिकायतों की निगरानी और प्रबंधन के लिए विभिन्न रिपोर्ट तैयार कर सकता है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि बैंक / एफएसपी सीएमएस डेटा का उपयोग न केवल शिकायतों के समाधान में अपने टर्न अराउंड समय को कम करने और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए करें, बल्कि अपने ग्राहकों का कष्ट जानने, व्यवहार और अपेक्षाओं को समझने के उद्देश्य से मूल कारण विश्लेषण करने के लिए भी करें ताकि ग्राहक निष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी सेवाओं में सुधार कर सकें।

सीएमएस से उपलब्ध आंकड़ों से मिली जानकारी, उदाहरण के लिए, बैंकों / एफएसपी द्वारा उन उत्पादों के डिजाइन के लिए उपयोग की जा सकती है जो उनके ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। जाहिर है, कि जो संस्थाएं डेटा का बेहतर विश्लेषण करते हैं और गुणग्राहक बनाने के लिए इसका उपयोग करती हैं, वे अधिक लाभ उठा सकती हैं तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उठा सकती हैं।

रिजर्व बैंक द्वारा एनालिटिक्स के लिए सीएमएस से डेटा का लाभ उठाया जा सकता है, जो आवश्यकता पड़ने पर विनियामक और पर्यवेक्षी हस्तक्षेप के लिए उपयोग किया जा सकता है। एप्लिकेशन में प्रदान किए गए विभिन्न डैशबोर्ड शिकायतों के

निवारण की प्रगति को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में रिजर्व बैंक की सहायता करेंगे।

सीएमएस के शुभारंभ से रिजर्व बैंक के लोकपाल कार्यालयों और उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्षों (सीईपीसी) में प्राप्त शिकायतों के प्रसंस्करण को डिजिटल कर दिया गया है।

मैं बैंकों / एफएसपी से आग्रह करता हूँ कि वे सीएमएस की क्षमता का पूरा उपयोग करें।

एप्लिकेशन को विकसित करने और लागू करने में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को मेरी हार्दिक बधाई।

राज्यपाल का उद्घाटन समारोह - वार्षिक सांख्यिकी दिवस सम्मेलन*

शक्तिकांत दास

प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योगदान के स्मरण में रिज़र्व बैंक द्वारा इस वर्ष आयोजित सांख्यिकी दिवस सम्मेलन तेरहवीं शृंखला का उद्घाटन करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, मैं इस अवसर पर सांख्यिकी के क्षेत्र में हाल की कुछ चुनौतियों की समीक्षा करना चाहूंगा और उस संदर्भ में हमारी भविष्य की योजनाओं पर विचार करना चाहूंगा।

सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर महालनोबिस की उपलब्धियां अग्रणी और व्यापक रूप से प्रशंसित हैं। कई मायनों में, उनके योगदान ने मानवीय समझ और प्रयास को आगे बढ़ाया है। इसलिए, उन्हें भारत के आधुनिक आंकड़ों का जनक माना जाता है जो एकदम उचित है। प्रोफेसर महालनोबिस एक महान संस्थान निर्माता भी थे। उन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना के लिए; देशव्यापी नमूना सर्वेक्षणों पर उनके पाथ-ब्रेकिंग कार्य के लिए; और स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों में राष्ट्र निर्माण में उनके कई ऐतिहासिक योगदानों के साथ-साथ, तेजी से औद्योगीकरण की दूसरी पंचवर्षीय योजना (FYP) मॉडल की रूपरेखा बनाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। प्रोफेसर महालनोबिस को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। जिसमें प्राकृतिक ज्ञान में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के मानद अध्यक्ष और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो सहित उन्हें अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त हुई है।

प्रोफेसर महालनोबिस इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स 'सांख्यिकी' के संस्थापक संपादक भी थे। अपने पहले अंक के संपादकीय में, प्रोफेसर महालनोबिस ने अनुशासन के लोकाचार

को संक्षेप में प्रस्तुत किया, और मैं उद्धृत करता हूँ: "... सांख्यिकी शब्द का इतिहास उस अंतरंग संबंध को दर्शाता है जो भारतीय मन में 3000 वर्षों से अधिक समय से पर्याप्त ज्ञान' और संख्या के बीच में मौजूद है। 'सांख्यिकी' जैसा कि हम इसकी व्याख्या करते हैं, आंकड़ों का मूल उद्देश्य संख्याओं और संख्यात्मक विश्लेषण की सहायता से वास्तविकता का निर्धारण और पर्याप्त ज्ञान देना है। "ये शब्द आज सम्मेलन की थीम 'भविष्य के लिए आँकड़े' पर हमारे विचार-विमर्श को प्रेरित करेंगे। यह माना जाता है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए सांख्यिकी एक 'प्रमुख प्रौद्योगिकी' है, जो दुनिया भर में गूँज रही है। मार्च 2019 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC) के 50 वें सत्र का मूल उद्देश्य 'बेहतर आंकड़े बेहतर जीवन' था।

उच्चतम गुणवत्ता के राष्ट्रीय स्तर के आँकड़ों की मांग और पब्लिक गुड के रूप में उनके प्रसार के लिए रिज़र्व बैंक की आँकड़ा और सूचना प्रबंधन प्रणाली कई दशकों में विकसित हुई है। कई वर्षों से, सार्वजनिक डोमेन में अधिक से अधिक जानकारी संकलित और जारी की जा रही है, जिसमें नीति-निर्माण में इनपुट देने वाला डेटा भी शामिल है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के बढ़ते एकीकरण और आर्थिक गतिविधि के परिष्कार और जटिलता के कारण सूचना की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गयी हैं। इसने व्यावसायिकों को विश्लेषणात्मक साधनों में नई खोज का अनुचित फायदा उठाने के लिए चुनौती दी है ताकि तेजी से बदलते गतिशील के साथ तालमेल बना रहे। उदाहरण के लिए, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, केंद्रीय बैंकों में सांख्यिकीय प्रणालियों ने एक प्रतिमान बदलाव किया है। वित्तीय क्षेत्र में जोखिमों की निगरानी, वैश्विक लिंकेज अतिसंवेदनशीलता के विश्लेषण के संदर्भ में सेक्टरल खाते, अंतर्संबंध और स्पिलओवर और पर ध्यान केंद्रीत किया जा रहा है। इसी समय, सूचना प्रबंधन और प्रसार तकनीकी रूप से अधिक उन्नत हो गया है, जिसमें उच्च आवृत्ति, बारीकता, बेहतर सत्यापन और बहु-उद्देश्य और संरचित डेटा उत्पादन प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है। रिज़र्व बैंक में भी, हम अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ग्रेनुलर डेटा एक्सेस लैब का समर्थन करने के लिए अपने नए डेटा वेअरहाउस का लाभ उठाने और विनियामक साधनों के मूल्यांकन के लिए एक सैंडबॉक्स वातावरण प्रस्ताव करते हैं।

* 28 जून, 2019 को मुंबई में वार्षिक सांख्यिकी दिवस सम्मेलन के अवसर पर गवर्नर का भाषण

रिज़र्व बैंक में और बैंक के बाहर भी व्यावसायिक सांख्यिकीविदों को वर्तमान में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है के बारे में मुझे कुछ कहना है। बिग डेटा आँकड़ों की दुनिया में एक नया बज़ है, और इसने पहले से ही दुनिया का नजरिया बदलना शुरू कर दिया है। डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में हुई प्रगति का फायदा उठाकर उपभोक्ताओं के व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए कॉर्पोरेट बड़े निवेश कर रहे हैं। इस सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने वर्गीकरण, एकत्रीकरण और विश्लेषण की कठोर प्रक्रियाओं की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए बहुत सारी समस्याएं पैदा की हैं। बड़ी संख्या में जानकारी को देखते हुए, विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं और नीतिगत निर्णय समर्थन के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उत्पादक उपयोग में 'संकेत' को देखना और 'शोर' को अनदेखा करना महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए जोखिम प्रोफाइल और तनाव परिदृश्य विकसित करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तकनीक के साथ मनोभाव विश्लेषण करने के लिए खाद्य मुद्रास्फीति का आकलन करने के प्रयोजन से बिग डेटा एनालिटिक्स का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

हाल के दिनों में, सांख्यिकीय विधियों की सटीकता पर जोशपूर्ण चर्चा हुई है। सिद्धांत - यहां तक कि वैज्ञानिक अनुसंधान में सांख्यिकीय महत्व की परंपरा की सत्यता पर बादल छाये हुए हैं और जर्नल अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन ने इस साल के शुरू में इस मुद्दे पर एक विशेष संस्करण प्रकाशित किया है। आलोचकों का आरोप है कि वांछित परिणामों को महत्वपूर्ण बनाने और अवांछित परिणामों को महत्व न देने के प्रयोजन से हेरफेर करने के लिए ये परीक्षण अतिसंवेदनशील हैं। इसके अलावा, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम संकल्पना स्तर पर ही त्याग दिए जा सकते हैं, क्योंकि वे अत्यधिक असंभाव्य हैं। इसी तरह, वेरिबल का चयन करने के लिए एक अवसर उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, सहसंबंधों को आसानी से नकली कारण स्थापित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस संदर्भ में, डूज और डोन्टस को उद्धृत किया गया है: 'यह नहीं कहना कि 'सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है' उनमें से एक है। फिर भी, वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात के जोखिम सच होते नजर आ रहे हैं, और विश्व की स्थिति पहले जैसे नहीं रही। ये सबक निरंतर आधार पर कॉर्पोरेट वित्तीय जोखिमों के बारे में हमारे मॉडलिंग को सावधान करते हैं। जैसा कि अमेरिकी सांख्यिकीविद् अनुशंसा करते हैं, "अनिश्चितता

स्वीकार करें। विचारशील, उदार और विनम्र बनो"; संक्षेप में, "एटीओएम।"

मेरे विचार में, इंटरनेट और सोशल मीडिया के व्यापक युग में, अनुभवजन्य नियमितताओं की स्थापना के लिए मजबूत सांख्यिकीय परीक्षण का कोई विकल्प नहीं है। आंकड़ों और परिणामों के प्रलय में, जो महत्वपूर्ण है वह यह नहीं जानता कि कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं, या किसको नजरअंदाज किया जाए, या किसका खंडन किया जाए। निष्कर्ष निकालने से पहले ठोस विश्लेषण, उपयोग किए गए डेटा की तुल्य समीक्षा के आधार पर शैलीगत तथ्यों और सामान्य ज्ञान से, विचलन की जांच की जानी चाहिए। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि समाधान पर पहुँचने के लिए कम आंकड़ों की आवश्यकता होगी बल्कि सही मायने में तो और अधिक आंकड़े खंगालने होंगे लेकिन उनका उपयोग इस प्रकार करना होगा जैसा किया जाना अपेक्षित है। अधिकांश देशों में आज निर्णय समर्थन हेतु बढ़ती हुई विश्लेषणात्मक मांगों को पूरा करने के लिए सांख्यिकी पेशे की आवश्यकता है। पेशे की बढ़ती मांग पर यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स द्वारा हाल ही में यह बताया गया है कि, सांख्यिकी, सांख्यिकीय विधियों और सांख्यिकीविद् की गुणवत्ता पर जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। रिज़र्व बैंक में, हम निरंतर आधार पर व्यापक आर्थिक विकास के पूर्वानुमान और आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणालियों को परिष्कृत करना जारी रखेंगे। अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए अनुसंधान और विश्लेषिकी को आगे बढ़ाया जाएगा और विशेष रूप से, विकास और मुद्रास्फीति की नाउकास्टिंग को और मजबूत किया जाएगा।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि प्रोफेसर टी.सी.ए. अनंत, प्रोफेसर टी.जे.राव और प्रोफेसर श्रीकांत अय्यर जैसे प्रख्यात सांख्यिकीविदों ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और सम्मेलन के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सहमती दर्शायी। जी 20 प्रक्रिया के लिए हमारी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र के धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संदर्भ में सांख्यिकीविदों की चुनौतियों पर प्रोफेसर अनंत के विचारों की प्रतीक्षा है। रिज़र्व बैंक नीतिगत उद्देश्यों से दुरंदेशी इनपुट प्रदान करने के लिए कई सर्वेक्षण कर रहा है। इस संदर्भ में, प्रोफेसर राव का मार्गदर्शन अत्यंत मूल्यवान होगा; इसके

अलावा, वे सर्वेक्षण पर तकनीकी सलाहकार समिति में बैंक के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। रैंडम कनेक्शन मॉडल पर प्रोफेसर अय्यर को सुनने के लिए भी हम उत्सुक हैं जो आयामों को कम करने, जानकारी संकुचित करने और बिग डेटा के युग में कुशल एल्गोरिदम को डिजाइन करने में सहायता करते हैं।

मुझे यह जानकर भी खुशी हुई कि दोपहर के सत्र में डॉ. सुब्रत सरकार, डॉ. डी. वी. शास्त्री, श्री डी.के. जोशी और डॉ. बोरनाली

भंडारी जैसे विशेषज्ञ शोध कार्य और भविष्य की शोध कार्यनीति पर चर्चा करेंगे। उनकी विशेषज्ञता हमारे युवा व्यवसायिकों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने में उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं सभी प्रतिभागियों को आज के सम्मेलन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे आशा है कि आपके विचार ज्ञान का दीपक जलाए रखेंगे जो मानव प्रयास को उजागर करेगा।

धन्यवाद !

व्यवहार्य वित्तीय बाजारों का विकास- भारतीय अनुभव*

विरल वी. आचार्य

प्रस्तावना

1.1 किसी भी देश के आर्थिक विकास में वित्तीय बाजार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक सतत विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करते हैं। इसलिए व्यवहार्य पूंजी बाजारों का विकास समष्टि वित्तीय नीतिगत उपायों में एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, जिसमें वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति के प्रसारण जैसे उद्देश्य शामिल हैं।

1.2 कमिटी ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम (सीजीएफएस)) जिसकी बैठक अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में होती है, ने पूंजी बाजार के विकास में वैश्विक रुझानों की जांच करने, विभिन्न कारकों (कानूनी, संस्थागत, संरचनात्मक और संयोजन्य), जो सुदृढ़ वित्तीय बाजार के विकास को प्रोत्साहित करते हैं की पहचान करने और विवेकपूर्ण उपायों सहित नीति की भूमिका पर विचार करने के लिए 2018-19 में एक कार्य दल का गठन किया। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी, डॉ. ली बो) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई, डॉ. विरल वी. आचार्य) की सह-अध्यक्षता वाले कार्य समूह ने मुख्य रूप से बांड और इक्विटी प्रतिभूति में बाजारों के विकास से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया¹। बेशक, ये मुद्दे उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक प्रासंगिक हैं, लेकिन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी ये काफी उपयोगी पाए गए।

* डॉ. विरल वी. आचार्य, उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद में 29 जून, 2019 को। इन टिप्पणियों को उनके द्वारा पूर्व में दिए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों जैसे व्यवहार्य कैपिटल मार्केट स्थापित करने पर दिनांक 29 मई 2019 को आयोजित आरबीआई संगोष्ठी; भारतीय आर्थिक अध्ययन संस्थान (IIES), टोक्यो, जापान, 10 जून 2019; विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के साथ बैठक, टोक्यो, जापान 11 जून 2019; नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) एशियन लीडर्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स (ALFI) प्रोग्राम, बेंगलुरु, 20 जून 2019, और फायरसाइड चैट पेट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद, 29 जून 2019 के सारांश रूप में समेकित किया गया है।

¹ यह रिपोर्ट 23 जनवरी 2019 को बीआईएस की बैठक में सीजीएफएस को दी गई थी और <https://www.bis.org/publ/cgfs62.pdf> पर उपलब्ध है।

1.3 सीजीएफएस रिपोर्ट में पूंजी बाजार विकास के संचालकों की पहचान की गई है और उन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- संचालक जो वित्तीय विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाते हैं, और
- संचालक जो विशेषतः कैपिटल मार्केट से अधिक जुड़े हैं।

1.4 संचालक जो सक्षम वातावरण का निर्माण करते हैं जैसा कि सीजीएफएस रिपोर्ट में चिन्हित किया गया है, उनमें शामिल हैं:

- समष्टि आर्थिक स्थायित्व,
- बाजार स्वायत्तता के लिए व्यापक सम्मान,
- निष्पक्ष व कुशल कानूनी और न्यायिक प्रणाली, और
- एक कुशल नियामक शासन जो वित्तीय अनुबंधों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है।

1.5 संचालक जो विशेषतः कैपिटल मार्केट से जुड़े हैं जैसा कि सीजीएफएस रिपोर्ट में चिन्हित किया गया है:

- उच्च गुणवत्ता वाली महत्वपूर्ण जानकारी की आसान उपलब्धता,
- निवेशक आधार में विविधता,
- व्यापार और मजबूत बाजार बुनियादी ढांचे के लिए कुशल बाजार पारिस्थितिकी तंत्र,
- समष्टि आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के प्रति खुलापन, और
- हेजिंग और फंडिंग प्रतिभूतियों के वित्तपोषण के लिए बाजार.

1.6 सीजीएफएस रिपोर्ट ने छह व्यापक नीतिगत सिफारिशों की हैं :

- अधिक से अधिक बाजार स्वायत्तता को बढ़ावा देना;
- निवेशकों की सुरक्षा के लिए कानूनी और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना;
- नियामक स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को बढ़ाना;
- घरेलू संस्थागत निवेशक आधार की पहुंच और विविधता में वृद्धि;
- द्वि-दिशात्मक तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी बाजार खोलना; तथा
- डेरिवेटिव, रेपो लेनदेन और प्रतिभूति उधार के लिए पूरक बाजार विकसित करना।

1.7 भारत में नीतिगत पहल काफी हद तक सीजीएफएस रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों के समरूप हैं। मैं भारतीय पूंजी बाजारों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के बाद इन पर और भविष्य के नीति निर्देशों पर चर्चा करूंगा। हालांकि सीजीएफएस रिपोर्ट का दायरा संपूर्ण पूंजी बाजार है, मैं इस भाषण को मुख्यतः रिज़र्व बैंक, द्वारा विनियमित बाजारों यथा ब्याज दर बाजारों और (अपेक्षाकृत कम) विदेशी मुद्रा बाजारों तक सीमित रखूंगा।

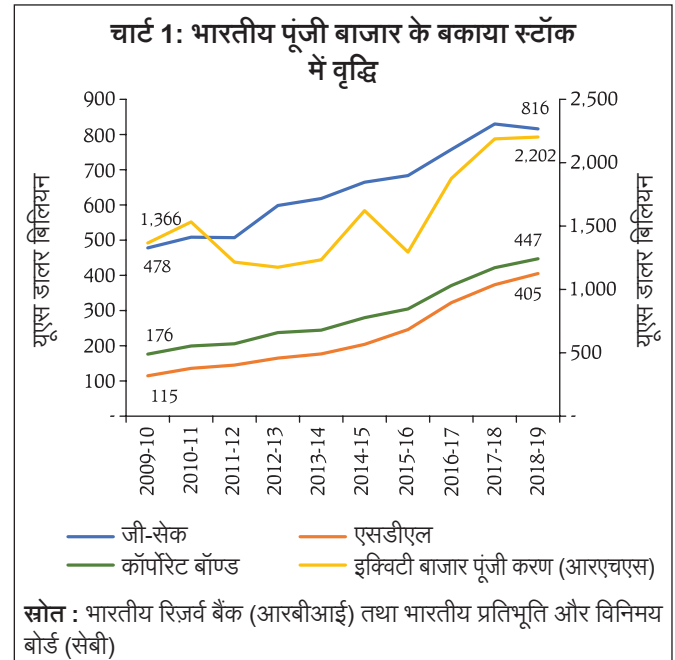
2. भारतीय पूंजी बाजारों का विहगावलोकन

2.1 भारतीय पूंजी बाजारों का एक सदी से अधिक का इतिहास रहा है। हालांकि, वे 1970 तक ज्यादातर निष्क्रिय रहे। 1980 के दशक के दौरान अर्थव्यवस्था के आंशिक उदारीकरण और पूंजी बाजार समर्थक नीतियों ने बाजार में कुछ सक्रियता का संचार किया, लेकिन 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद ही इसे वास्तविक गति मिली। आज, भारत के पूंजी बाजारों के विभिन्न वर्ग दक्षता (मूल्य खोज), व्यापार योग्यता (कम प्रभाव लागत), सुदृढ़ता (सभी उत्पाद वर्गों और आय वक्र में दरों की सहगति), और स्थिरता के संदर्भ में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से कई में समकक्षों के साथ तुलनीय हैं। विशेष रूप से, कई बार दबाव का सामना करने की क्षमता उनकी बढ़ती परिपक्वता का संकेत है, जिसमें 1997-98 में एशियाई वित्तीय संकट, 2007-09 में वैश्विक वित्तीय संकट और 2013 में टेंपर टैट्रम 'प्रकरण उल्लेखनीय हैं।

2.2 आकार के संदर्भ में, पूंजी बाजार के सभी प्रमुख खंड, अर्थात्, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां (जी-सेक) बाजार, राज्य विकास ऋण के लिए बाजार (एसडीएल), कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार और इक्विटी बाजार - तथाकथित 'नकदी बाजार' - ने प्राइमरी इश्यूअन्स, बाजार पूंजीकरण (इक्विटी बाजार के लिए) और द्वितीयक बाजार में व्यापार मात्रा के संदर्भ में पिछले कुछ दशकों के दौरान लगातार वृद्धि की है। यद्यपि जी-सेक, एसडीएल और कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में तेजी से वृद्धि हुई है, इक्विटी बाजार सबसे बड़ा वर्ग बना हुआ है (चार्ट 1)।

2.3 सरकारी प्रतिभूति बाजार का विकास:

एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और बाजार-आधारित प्राइमरी इश्यूअन्स प्रक्रिया से सरकारी प्रतिभूति बाजारों, केंद्र सरकार

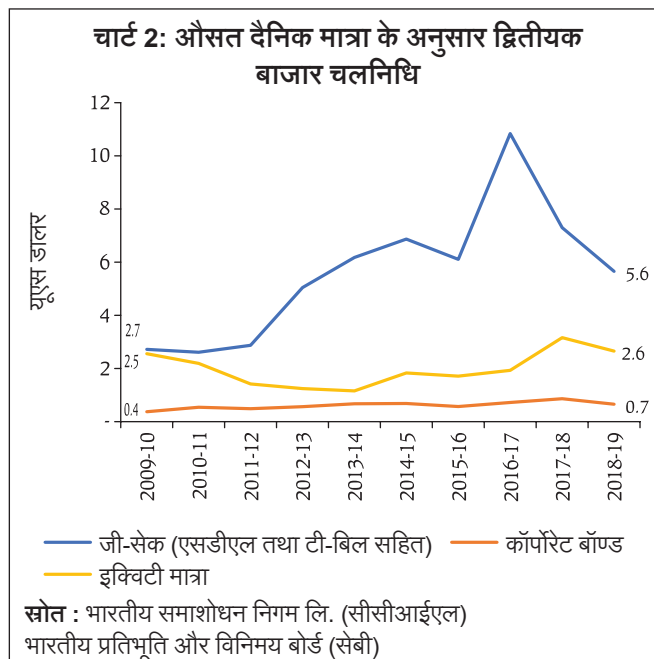


प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य सरकार प्रतिभूतियों (एसडीएल) दोनों के विकास को सहायता पहुँचाई है। प्राथमिक जी-सेक बाजार में निर्गम (इश्यूअन्स) अर्ध-वार्षिक पूर्व घोषित कैलेंडर के अनुसार किए जाते हैं। कैलेंडर में राशि, परिपक्वता काल और जारी करने की तारीख निर्दिष्ट होती है। जी-सेक का परिपक्वता काल 40 साल तक होता है। जी-सेक ज्यादातर फिक्स्ड-कूपन बॉन्ड होते हैं, हालांकि मुद्रास्फीति से जुड़े बॉन्ड, कैपिटल-इंडेक्स बॉन्ड, फ्लोटिंग-रेट बॉन्ड और एम्बेडेड विकल्प वाले बॉन्ड भी जारी किए जाते हैं। वर्तमान में, सभी निर्गम (इश्यूअन्स) साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से किए जाते हैं। निर्गम प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) द्वारा समर्थित होते हैं जो इस इश्यूअन्स को पूरी तरह से हामीदारी देते हैं। बाजार-समाशोधन मूल्य निर्धारित करने वाली प्रतिस्पर्धी बोली (सभी निवासियों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए) और आबंटित प्रतिभूतियां बाजार-समाशोधन मूल्य पर प्राप्त करने वाली गैर-प्रतिस्पर्धी बोली (ज्यादातर खुदरा निवेशकों के लिए) दोनों के माध्यम से नीलामी आयोजित की जाती है। 90 प्रतिशत से अधिक निर्गम मौजूदा प्रतिभूतियों को पुनः प्रारम्भ करके किया जाता है जिसने बड़ी संख्या में निवेशकों के स्वामित्व को विस्तार देकर बाजार की तरलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रिज़र्व

बैंक ने 2006 से जी-सेक बाजार के लिए 'जब-जारी' खंड भी शुरू किया है।²

स्टॉक और फ्लो विशेषताओं के संदर्भ में जी-सेक और एसडीएल दोनों का स्वरूप सारणी 1 और 2 में दिखाया गया है। जी-सेक पर भारित औसत कूपन सभी ब्याज दर चक्रों में स्थिर बना हुआ है, जो औसत परिपक्वता के रूप में डेट स्वरूप को स्थिरता प्रदान करता है क्योंकि निर्गमन (10 वर्ष से अधिक) वैश्विक रूप से सबसे लंबे निर्गमनों में से एक है, जो केंद्र सरकार के लिए रोलओवर जोखिम को सीमित करने में मदद करता है। एसडीएल निर्गमन बढ़ते-बढ़ते जी-सेक के सापेक्ष निर्गमन का एक बड़ा हिस्सा बन गया है, जो 2013-14 में निर्गमन के लगभग 25 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में लगभग 45 प्रतिशत हो गया है।

2.4 जी-सेक बाजार में चलनिधि (तरलता/लिक्विडिटी) : सरकारी प्रतिभूतियों के लिए द्वितीयक बाजार में तरलता में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है (चार्ट 2)। जी-सेक और एसडीएल बाजारों में औसत दैनिक मात्रा कॉर्पोरेट बॉन्ड और इक्विटी नकदी बाजारों की तुलना में अधिक रही है। हालांकि, जी-सेक की तरलता, मुख्य रूप से कुछ बेंचमार्क प्रतिभूतियों में केंद्रित है, विशेषतः 10-वर्षीय बेंचमार्क, और एसडीएल जी-सेक की तुलना में अपेक्षाकृत कम तरल हैं, जो 10-वर्ष की परिपक्वता अवधि पर जी-सेक की तुलना में आमतौर पर 50-75 आधार



अंक अधिक प्रतिफल प्रदान करता है। जी-सेक बाजार में तरल प्रतिभूतियों के लिए बोली-प्रस्तावित दर के दायरे का औसत पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक आधार अंक से कम रह गया है (चार्ट 3)। आश्चर्यजनक रूप से, बोली-प्रस्तावित दर का दायरा और इसके साथ-साथ 10 साल के भारतीय जी-सेक बेंचमार्क का व्यापार का मूल्य प्रभाव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित

सारणी 1: केंद्र सरकार के उधार (जी-सेक) का स्वरूप

वर्ष	वर्ष के दौरान जारी		लंबित स्टॉक	
	प्रतिफल का भारित औसत (प्रतिशत)	परिपक्वता का भारित औसत (वर्ष)	ब्याज का भारित औसत (प्रतिशत)	परिपक्वता का भारित औसत (वर्ष)
2013-14	8.4	14.2	8.0	10.0
2014-15	8.5	14.7	8.1	10.2
2015-16	7.9	16.0	8.1	10.5
2016-17	7.2	14.8	8.0	10.7
2017-18	7.0	15.0	8.0	10.7
2018-19	7.8	14.7	7.8	10.4

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (2017-18) और भारतीय अर्थव्यवस्था का डेटाबेस (डीबीआईई), भारतीय रिजर्व बैंक।

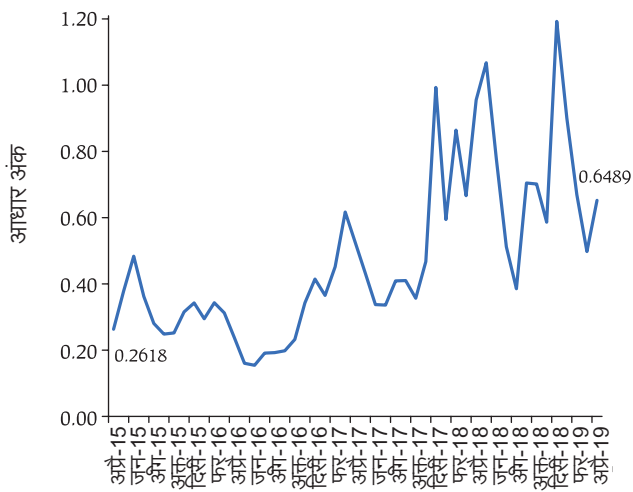
सारणी 2: सरकारी उधारियों (यूएस डॉलर बिलियन में) के निर्गम का स्वरूप

वर्ष	केंद्र सरकार (जी-सेक)		राज्य सरकार (एसडीएल)	
	सकल निर्गमन	लंबित स्टॉक (मार्च के अंत तक)	सकल निर्गमन	लंबित स्टॉक (मार्च के अंत तक)
2013-14	90	609	31	174
2014-15	91	648	36	199
2015-16	85	674	41	243
2016-17	80	754	56	321
2017-18	91	795	63	346
2018-19	83	837	70	404

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था का डेटाबेस (डीबीआईई), भारतीय रिजर्व बैंक।

² 'हेन, एज एंड इफ़ ईश्यूड' का एक संक्षिप्त रूप 'हेन इश्यूड' किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) में सशर्त लेन-देन को सूचित करता है जो जारी होने (इश्यूंस) को प्राधिकृत है पर अभी तक वास्तविक रूप में हुई नहीं है। सभी 'हेन इश्यूड' लेन-देन 'यदि' (इफ़) आधार पर होते हैं जो तभी सेटल होंगे यदि व जब (इफ़ एंड हेन) वास्तविक प्रतिभूति जारी होगी। प्रत्येक ईश्यू के लिए वितरण अवधि को बढ़ाकर और बाजार को बिना हलचल, बड़े निर्गमों (ईश्यूस) को पचाने के लिए अधिक समय देकर लिए ऐसी ट्रेडिंग वितरण को सुगम बनाती है।

चार्ट 3: तरल सरकारी प्रतिभूतियों के लिए औसत बोली-प्रस्तावित दर दायरा (बिड-आस्क स्प्रेड)



स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल)

दुनिया की अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से तुलनीय हैं या कम हैं (चार्ट 4)।

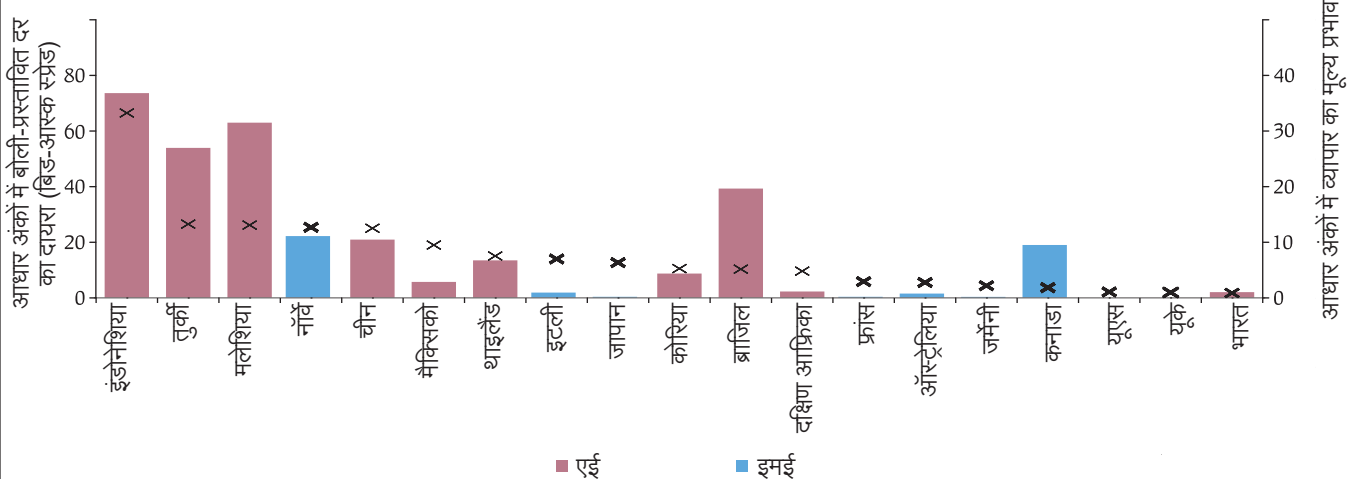
इस भारतीय सरकारी प्रतिभूति बाजार (जी सेक) की चलनिधि में कई निकटस्थ संचालक हैं :

- 10 वर्षीय बेंचमार्क के नियमित निर्गम ने प्रतिफल वक्र के इस खंड में ट्रेडिंग रुचि (इंटरेस्ट) को केंद्रित

कर दिया है। अब लघुतर परिपक्वता (2 और 5 वर्ष) की बेंचमार्क प्रतिभूतियों के निर्गम को नियमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- द्वितीयक बाजार के लेनदेनों को मुख्यतः (लगभग 80%) अनाम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग प्रणाली (एनडीएस-ओएम) के माध्यम से संचालित किया जाता है जो ऋण ट्रेडिंग में विश्व में अद्वितीय है। जबकि शेष लेनदेन एनडीएस-ओएम³ से बाहर काउंटर पर किए जाते हैं, तथापि, उनको एनडीएस-ओएम प्लेटफार्म पर भी रिपोर्ट किया जाता है।
- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ट्रेड सूचना के लगभग वास्तविक समय में प्रसार से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- भुगतान सीसीआईएल द्वारा गारंटीड होता है और डिलीवरी बनाम भुगतान (डीवीपी) प्रणाली के माध्यम से टी+1 आधार पर होता है। गारंटी वाले निपटान का अर्थ है कि निवेशकों को एक दूसरे से सुपर्दगी के विफल होने का जोखिम नहीं है।

चार्ट 4: विभिन्न देशों में 10 वर्षीय बेंचमार्क जी-सेक चलनिधि

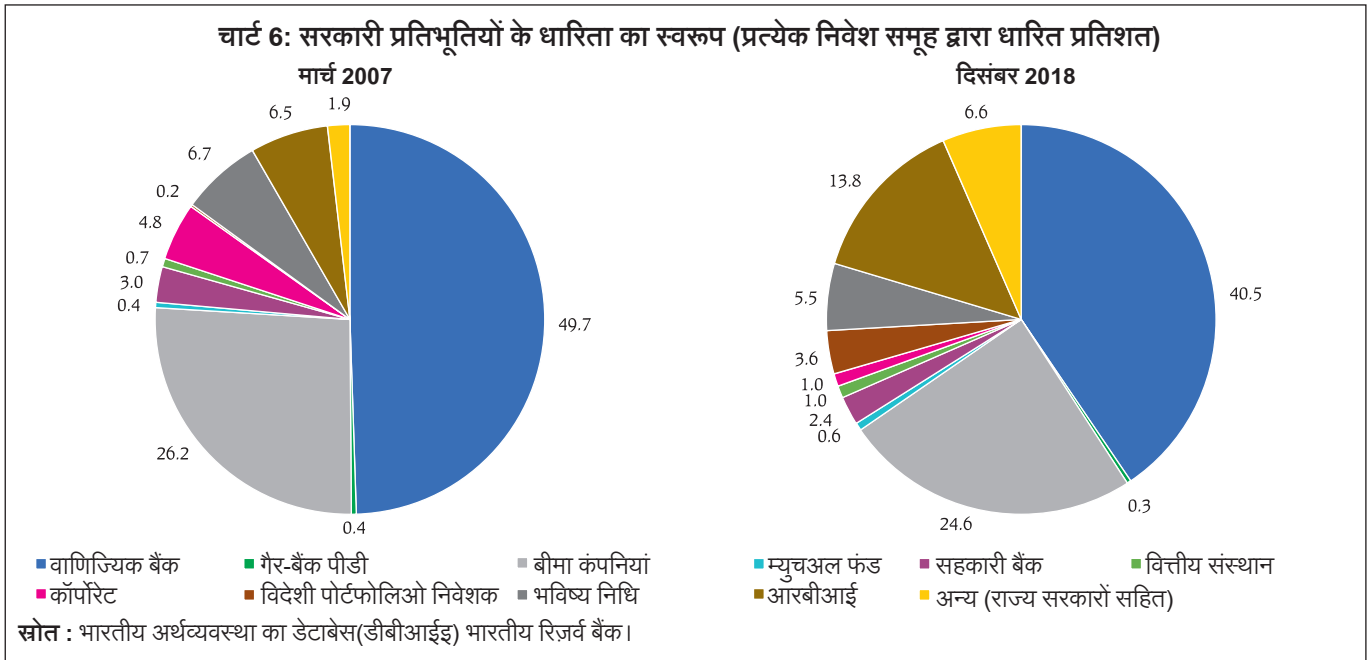


¹ मई 2018 में दैनिक बोली-प्रस्तावित दर दायरे (बिड-आस्क स्प्रेड) का औसत, ((आस्क प्राइस-बिड प्राइस)/ बिड प्राइस) X 100 के रूप में परिभाषित अर्थात् बॉण्ड में राउंड ट्रीप लेन देन के लिए रिटर्न लागत।

² ब्लूमबर्ग लिक्विडिटी एसेसमेंट(एलक्यूए) फंक्शन के आकलन का उपयोग करते हुए यूएस डालर 10 मिलियन लेनदेन राशि के आधार पर। जून 2018।

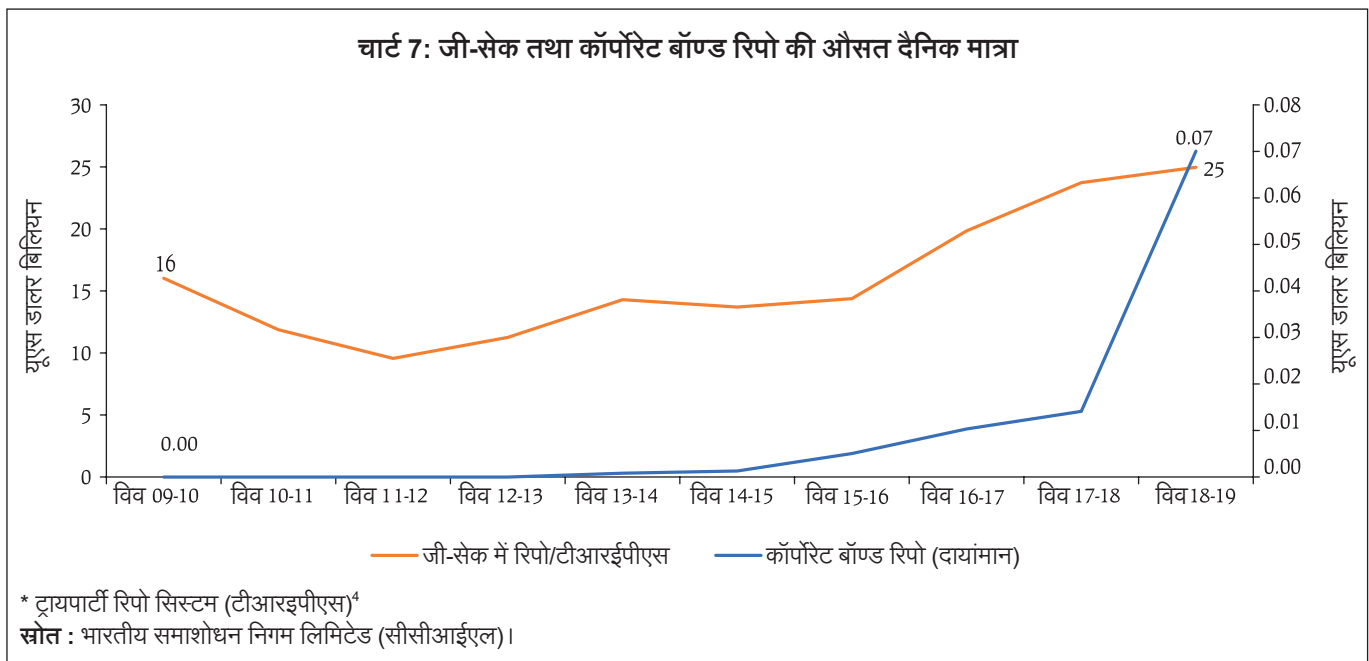
स्रोत : एस्टेबलिशिंग वायेबल कैपिटल मार्केट. सीजीएफएस पेपर नं 62।

³ तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान (एनडीएसओएम)।



2.8 फंडिंग (निधियन) एवं डेरिवेटिव बाजार : पूंजी बाजार के विकास के लिए निधियन और प्रतिभूति उधार बाजारों के साथ-साथ जोखिम अंतरण के लिए डेरिवेटिव बाजार का होना एक अनिवार्य शर्त है। भारतीय सरकारी प्रतिभूति बाजार में रेपो

फंडिंग में अच्छी गहराई जिसकी दैनिक औसत मात्रा अमेरिकी डॉलर \$20 बिलियन है। ब्याज दर डेरिवेटिव के मामले में, ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) और ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) बाजारों⁵ में भी समुचित तरलता है। गतिविधियों में



⁴ सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में त्रिपक्षीय रिपो की शुरुआत 05 नवंबर 2018 से हुई। त्रिपक्षीय रिपो में किसी रिपो लेन-देन के दो मूल पक्षों के बीच कोई तीसरा पक्ष केंद्रीय प्रतिपक्षकार का काम करता है। वर्तमान में जी-सेक के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) और कॉर्पोरेट बॉण्डों के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) 'त्रिपक्षीय' (ट्राइपार्टी) एजेंट का काम करते हैं।

⁵ ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) एक ब्याज दर अदला-बदली करार है जहाँ एक नियत दर को सहमति से तय अवधि के लिए दैनिक एकदिवसीय संदर्भ दर के एक पूर्व-निर्धारित प्रकाशित सूचकांक से स्वैप किया जाता है।

हालिया वृद्धि मुख्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर निवासियों को ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार में बचाव व्यवस्था और ट्रेडिंग दोनों उद्देश्यों से भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के कारण है।

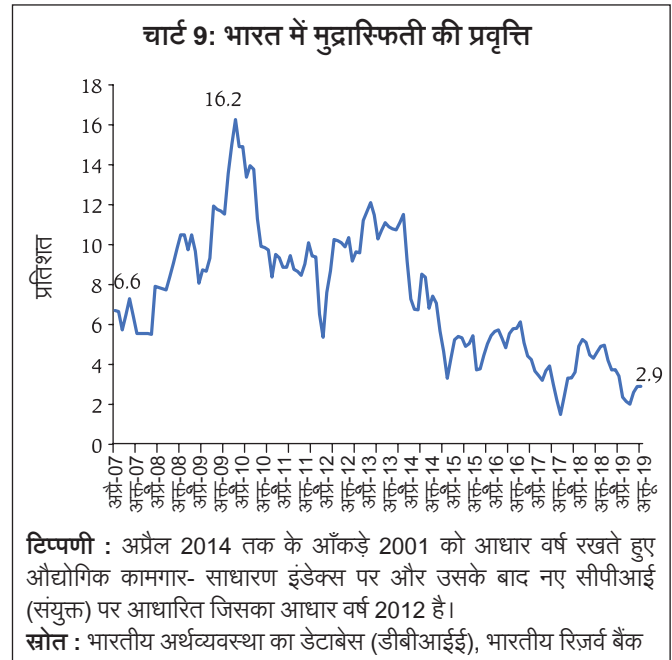
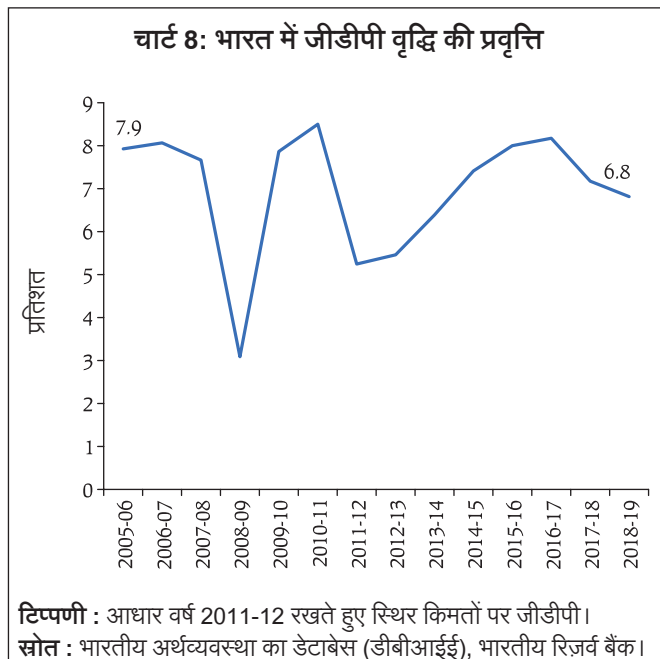
3 भारत में नीतिगत पहल :

भारतीय पूंजी बाजार वृद्धि के इस स्तर तक पहुंचने में कैसे सक्षम हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं भारत में किए गए नीतिगत उपायों के साथ-साथ सीजीएफएस रिपोर्ट के निष्कर्ष और सिफारिशों पर भी चर्चा करूंगा।

3.1 अनुकूल माहौल

3.1.1 समष्टि-आर्थिक स्थिरता

पिछले डेढ़ दशक में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक में से एक रही है (चार्ट 8)। 'टैपर-टर्म' से पहले के कुछ वर्षों में दोहरे अंकों वाली मुद्रा-स्फीति के दौर को नियंत्रित किया गया जिसमें वर्ष 2016 में रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के लिए 4 प्रतिशत (+/-2 प्रतिशत) के हेडलाइन लक्ष्य के साथ लचीले मुद्रा-स्फीति लक्ष्य प्रति शिफ्ट से सहायता मिली। मुद्रा-स्फीति दर का उच्च स्तर वित्तीय आस्तियों की होल्डिंग को गैर वित्तीय आस्तियों जैसे कि हाउसिंग और सोने की तुलना में आर्थिक रूप से अनाकर्षक बनाता है। कम तेल मूल्य और खाद्य आपूर्ति प्रबंधन की सहायता से लचीले मुद्रा-स्फीति लक्ष्य



संबंधी महत्वपूर्ण सुधार ने पिछले पांच वर्षों में एमपीसी को दिए गए लक्ष्य की तुलना में हेडलाइन मुद्रा-स्फीति को नियंत्रणाधीन रखा है (चार्ट 9)। इस प्रकार समष्टि-आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक दो पूर्व-निर्धारित शर्तों – सुस्थिर वृद्धि और कम मुद्रा-स्फीति – से बचत का वित्तीयकरण और पूंजी बाजार का विकास भारत में उपलब्ध है।

3.1.2 बाजार की स्वायत्तता को बढ़ावा देना

ए. विनियामकीय दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना

सरकार और अन्य वित्तीय बाजार विनियामकों के साथ सक्रिय समन्वय करके, रिज़र्व बैंक ने मौजूदा नीतियों में सुधार करने और उसके युक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों के माध्यम से वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ाने की कोशिश भी की गई है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार हैं:

- नए उत्पादों की नवाचार प्रक्रिया को उदार बनाना;
- निर्देशात्मक दृष्टिकोण से हटकर सिद्धांत-आधारित विनियामकीय दृष्टिकोण को अपनाना;
- तदर्थ 'अनुमोदन' से बचकर बाजार प्रक्रिया में हस्तक्षेप को कम करना; तथा,

- iv. कमियों को दूर करके, विशेष रूप से बाजार के दुरुपयोग संबंधी विनियमों और बेंचमार्क विनियमों को जारी करने के साथ-साथ व्यापारिक प्लेटफॉर्मों को विनियमित करके, व्यापक बाजार विनियमों को हासिल करने का प्रयास करना।

बी. वित्तीय बाजार संस्थाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

सुविकसित और विश्वसनीय इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तीय बाजारों के सुरक्षित और कुशल कामकाज के लिए पहली आवश्यकता है। इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए, रिजर्व बैंक ने उन बाजारों में एक प्रभावी इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसे वो नियंत्रित करता है। प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

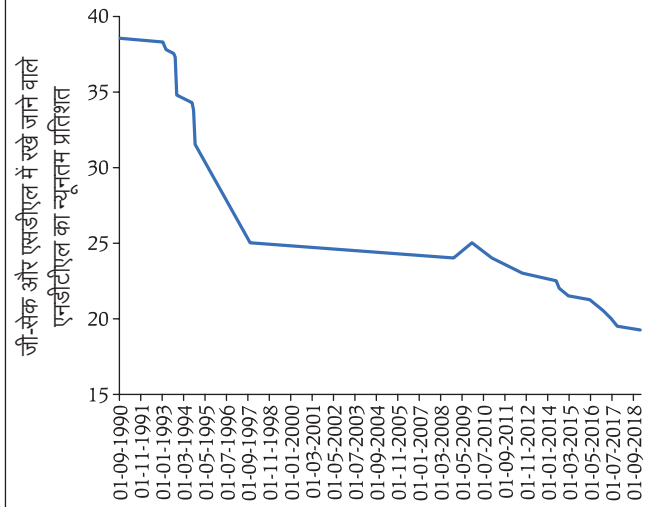
- जी-सेक के लिए एक अनाम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत जिसे नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) कहा जाता है;
- ओटीसी व्युत्पन्नी बाजारों के साथ-साथ गैर-व्युत्पन्नी बाजारों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता कोड(एलईआई) की शुरुआत;
- खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए लेन-देन की लागत को कम करने के उद्देश्य से एक विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म (एफएक्स-रिटेल) का विकास (अगस्त 2019); तथा,
- एक स्वतंत्र वित्तीय बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर, अर्थात् भारतीय वित्तीय बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) का गठन।

सी. घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए निवेश प्रतिबंधों का समष्टि-विवेकपूर्ण प्रबंधन

रिजर्व बैंक का यह लगातार प्रयास रहा है कि बाजार सहभागियों पर लगाए गए निवेश सीमा के रूप में प्रतिबंधों को युक्तिसंगत बनाया जाए, तथा जहां कहीं समष्टि-विवेकपूर्ण उद्देश्यों के अनुरूप हो, उसे शिथिल किया जाए:

- रिजर्व बैंक ने जी-सेक और एसडीएल में बैंकों द्वारा नपे-तुले तरीके से (चार्ट 10) 1990 में करीब 40 प्रतिशत से वर्तमान में 20 प्रतिशत से नीचे धारित

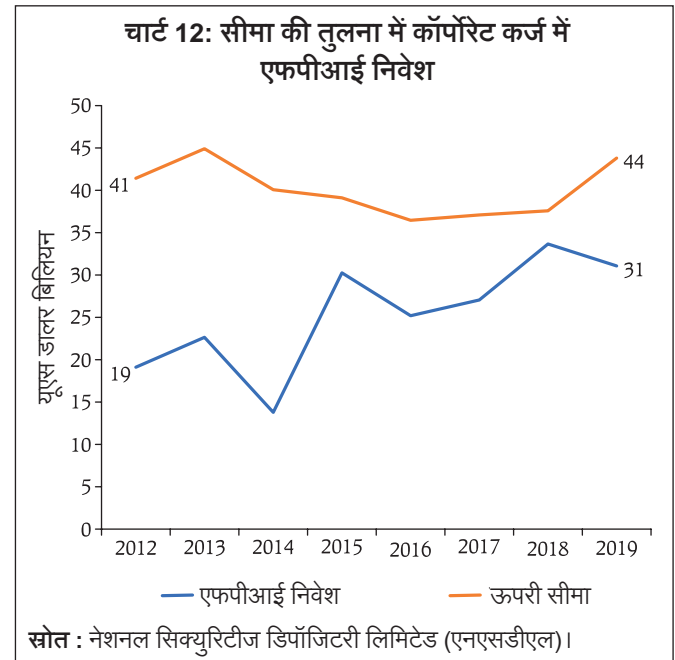
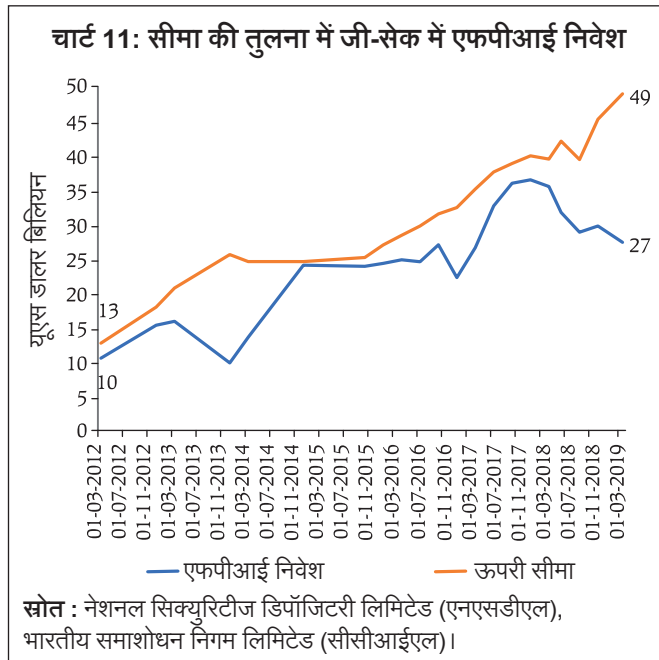
चार्ट 10: बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश में छूट



स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था का डेटाबेस (डीबीआईई), भारतीय रिजर्व बैंक

की जाने वाली निवल मांग और मियादी देयताएँ (एनडीटीएल) के न्यूनतम प्रतिशत पर सांविधिक चलनिधि अपेक्षा (एसएलआर) की शर्त को कम कर दिया है। इस महत्वपूर्ण छूट से बैंकों के लिए उनके निवेश निर्णयों में अधिक लचीलापन आया है और जी-सेक और एसडीएल में निवेशक आधार की विविधता को जोड़ा गया है (चार्ट 6) - जिससे बदले में, इन बॉण्ड्स के कुशल मूल्य निर्धारण में मदद मिली है।

- एफपीआई की निवेश सीमा (चार्ट 11 और 12) के साथ-साथ एफपीआई निवेश के लिखतों और परिपक्वता अवधि की पात्रता को विस्तार देकर पोर्टफोलियो प्रबंधन में उनको अधिक स्वतंत्रता देते हुए रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए कर्ज बाजार को नपे-तुले तरीके से उपलब्ध कराया है।
- हाल ही में, रिजर्व बैंक ने एफपीआई के लिए समष्टि-विवेकपूर्ण प्रतिबंधों में ढील देने के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना शुरू की है, जो देश में अपने निवेश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को न्यूनतम प्रतिधारण अवधि (वर्तमान में तीन साल) के लिए बनाए रखने के लिए तैयार हैं।



3.1.3 निवेशक संरक्षा के लिए विधिक और विनियामकीय ढांचे को मजबूत करना

बाजार के बुनियादी ढांचे के सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत अंगों में से एक उचित विधिक फ्रेमवर्क है जो बाजार के दुरुपयोग और गलत तौर-तरीकों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करके निवेशकों की संरक्षा सुनिश्चित करता है। भारत में, लोक ऋण अधिनियम (1944), प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम (1956) और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम (2006) प्रतिभूतियों के निर्गमन और हस्तांतरण की औपचारिकता को नियंत्रित करते हैं। समानांतर में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (1934) मुद्रा, व्युत्पन्नी, रेपो और सरकारी प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करने के लिए रिज़र्व बैंक को अधिकार प्रदान करता है। ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) (दिसंबर 2016) के आने से, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के संदर्भ में भी वित्तीय विनियमन का विधिक फ्रेमवर्क व्यापक और प्रभावी होने की ओर अग्रसर है। तथापि, गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान फ्रेमवर्क की कमी एक गंभीर ख़ाई है जिस पर प्राधिकारियों को शीघ्र ध्यान देने की जरूरत है।

3.2 पूँजी बाजार से जुड़े वाहक

अब मैं भारत में बाजार विकास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाहकों की ओर मुड़ता हूँ और इसमें सुधार के कुछ जरूरी क्षेत्रों के बारे में भी बताता हूँ।

3.2.1 प्रकटीकरण व्यवस्था

सीजीएसएफ रिपोर्ट की विभिन्न देशों के सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट में समुचित और समय से प्रकटीकरण निवेशकों का विश्वास पाने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर, पर्याप्त प्रकटीकरण का अभाव कॉर्पोरेटों की वित्तपोषण लागत बढ़ा देता है, विशेषतः निवेश के बारे में जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं है, और पूँजी बाजार के दायरे को छोटा कर देता है। इसे देखते हुए, भारत में विनियामकों ने जारीकर्ताओं द्वारा उच्च गुणवत्ता और समय से प्रकटीकरण पर बल दिया और इसे आवश्यक बनाया है। तथापि, वाणिज्य पत्र व कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटों में हाल में हुई चूक की कुछ घटनाओं से प्रकटीकरण की गुणवत्ता को लेकर चिंता हुई है, निवेश – ग्रेड (जिनकी रेटिंग अच्छी है) फर्मों के लिए भी। यह अपेक्षित है कि इन चिंताओं पर ध्यान दिया जाए और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आलोक में इनका आकलन हो ताकि कॉर्पोरेटों द्वारा चूक संबंधी सूचना के समय से प्रकटीकरण संबंधी मानकों को चुस्त-दुरुस्त करने में मदद मिल सके।

3.2.2 घरेलू संस्थागत आधार का गहनीकरण

निवेशक आधार के विस्तार से बाजार में विविधता बढ़ती है (देखें खंड 2.7)। घरेलू संस्थागत निवेशक आधार पर विशेष जोर के साथ इस दिशा में कोशिशें बनाए रखनी हैं। घरेलू इकाइयों के लिए पेंशन और इंश्योरेंस कवरेज का विस्तार एक प्राथमिकता

हो सकती है क्योंकि यह न केवल सामाजिक कल्याण, बल्कि पूँजी बाजारों के लिए एक दृढ़तर व अधिक स्थिर आधार की ओर भी ले जाता है। घरेलू बचत का बेहतर वित्तीयकरण बाजारों में खुदरा भागीदारी का उत्प्रेरक हो सकता है जहाँ से सामूहिक निवेश वाहनों जैसे म्यूचुअल फंडों और वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) को बढ़ावा मिलेगा।

3.2.3 अंतरराष्ट्रीय सहभागिता के लिए दोनों ओर से बाजारों को खोलना

सीजीएफएस रिपोर्ट में बाजार विकास को लेकर जिन प्रमुख उत्प्रेरकों को मान्यता मिली है उनमें से एक है विदेशी सहभागियों के लिए बाजार खोलना, हालांकि इसमें वैश्विक घटनाओं के प्रभाव के जोखिम को नियंत्रण में करना शामिल है। रिजर्व बैंक ने, पहले की गई चर्चानुसार, विदेशी सहभागियों के लिए अपने विनियमित बाजारों को खोलने के लिए सोच विचार कर कदम उठाया है और साथ ही घरेलू सहभागियों को विदेशी बाजारों में भाग लेने की अनुमति दी है :

- i. सरकार के परामर्श से, रिजर्व बैंक ने उन अनिवासियों के लिए, अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (आईसीएसडी) के माध्यम से जी-सेक की अपतटीय ट्रेडिंग और निपटान की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जो घरेलू एफपीआई पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते हैं।
- ii. मुद्रा जोखिम को हेज करने संबंधी विनियमों को लेकर हाल में जारी किए गए ड्राफ्ट में सीजीएफएस रिपोर्ट द्वारा पहचाने गए कई वाहक शामिल हैं – उत्पाद नवोन्मेषण, अनिवासियों के लिए बाजार खोलना और उपयोगकर्ताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करने वाले सरल हेजिंग दिशानिर्देश।
- iii. इसी तरह, मार्च 2018 में, रिजर्व बैंक ने विदेशों में पण्य मूल्य जोखिम और माल ढुलाई जोखिम की हेजिंग से निवासियों को मुक्त कर दिया। निवासियों को निर्दिष्ट साधनों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पण्य जोखिम दोनों को हेज करने की अनुमति दी गई थी। प्रत्यक्ष जोखिम के लिए, सभी वस्तुओं पर सभी मूल्य जोखिम को अब विदेशों में हेज करने की अनुमति है, जबकि अप्रत्यक्ष जोखिम के लिए, निवासी केवल औद्योगिक धातुओं पर मूल्य जोखिम

को विदेशों में हेज कर सकते हैं। इसके अलावा, संशोधित निर्देशों में घरेलू और सीमा पार लेन-देन से होने वाले जोखिमों को बराबर माना गया है।

इस तरह के सुधार से उत्पन्न होने वाले वैश्विक प्रभावों के जोखिम नियंत्रण के लिए, इनमें से अधिकांश सुधारों के साथ-साथ विवेकसम्मत सीमाएं लागू की जा चुकी हैं ताकि भारत के लिए पूँजी खाता उदारीकरण की समग्र स्थिति में सुसंगति सुनिश्चित की जा सके और समष्टि-विवेकपूर्ण जोखिमों को संभालने योग्य स्तर पर रखा जा सके।

3.2.4 पूरक बाजारों का विकास

रेपो और डेरिवेटिव जैसे गहरे और तरल पूरक बाजार नकदी बाजारों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे निवेशकों को धन उपलब्ध कराने और हेजिंग में मदद करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड दोनों के लिए रेपो बाजारों को विकसित करने के लिए उपाय किए हैं। त्रि-पक्षीय रिपो (अगस्त 2017) का प्रारंभ जी-सेक बाजार के लिए एक सफलता है; हालांकि, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में त्रि-पक्षीय रेपो ने अभी जोर नहीं पकड़ा है। इसी तरह, प्रतिभूति उधार ('बाजार रेपो') जी-सेक के लिए अच्छी तरह से काम करता है, हालांकि उधार लेने की लागत में अत्यधिक अस्थिरता की सामयिक वारदातों से बचने के लिए व्यापक भागीदारी (विशेष रूप से जी-सेक के बड़े धारकों द्वारा, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड) जरूरी है। इन सभी विनियामकीय उपायों के परिणामस्वरूप रेपो बाजारों में चलनिधि में लगातार वृद्धि हुई है।

डेरिवेटिव बाजारों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू संस्थाओं, विशेष रूप से बैंकों द्वारा बेहतर जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिहाज से प्रयास किए जाने की जरूरत है। बैंकों और गैर-बैंकों की जोखिम प्रबंधन गतिविधि में ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार के जोर पकड़ने के साथ ही, जिनका अभी तक दोहन नहीं किया गया है, आने वाले वर्षों में पूरक बाजारों की भूमिका मजबूत होगी।

3.3 हाल में की गई अन्य पहल

मैं, भारतीय पूँजी बाजारों को और विकसित करने के लिए चल रही चार महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र करके अपनी बात को विराम दूंगा :

ए. अपतटीय रुपया बाजार पर कार्य बल

रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2019 में अपतटीय रुपया बाजारों से संबंधित मुद्दों की बारीकी से जाँच करने और अनिवासियों के लिए प्रोत्साहन में अनुरूपता लाने के लिए उचित नीतिगत उपायों की सिफारिश करने, ताकि वे अपनी हेजिंग आवश्यकताओं के लिए धीरे-धीरे घरेलू बाजार की ओर बढ़ें और साथ ही रुपये के बाह्य मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक कार्य बल का गठन किया है। कार्य बल की रिपोर्ट जुलाई 2019 के मध्य तक तैयार हो जाएगी।

बी. बाजार के समय निर्धारण (टाइमिंग) पर आंतरिक कार्य दल

रिज़र्व बैंक ने बाजार के समय निर्धारण (टाइमिंग) को लेकर एक आंतरिक कार्य दल की स्थापना की है जो रिज़र्व बैंक के दायरे में आने वाले विभिन्न बाजारों के टाइमिंग की व्यापक समीक्षा करेगा, और आवश्यक भुगतान और निपटान इन्फ्रास्ट्रक्चर का आकलन करेगा, जो इन बाजारों में समन्वित समय में सहयोग कर सकता है। कार्य दल की रिपोर्ट, प्रस्तुत करने के बाद, सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी की जाएगी।

सी. कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर कार्य बल

रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर एक कार्यबल का गठन किया है। यह कॉर्पोरेट ऋणों में द्वितीयक बाजार के विकास में सहायक आवश्यक नीतियां सुझाएगा, जिसमें दबावग्रस्त आस्तियों के लिए ऋण लेनदेन हेतु एक प्लैटफॉर्म, ऋण अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) रजिस्ट्री का निर्माण, इसकी स्वामित्व संरचना और संबंधित प्रोटोकॉल जैसे ऋण सूचना का मानकीकरण,

स्वतंत्र सत्यापन और डेटा एक्सेस शामिल हैं। कार्य बल की रिपोर्ट अगस्त 2019 के अंत तक तैयार हो जाएगी।

डी. आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार विकास समिति

रिज़र्व बैंक ने भारत में आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजारों के आकलन; सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं व वैश्विक वित्तीय संकट के सबकों के अध्ययन के लिए भी तथा अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित मानकों के अनुरूप बंधकों की परिभाषा, बंधक दस्तावेजीकरण मानकों, समुचित सावधानी व निवेशकों द्वारा सत्यापन में सुगमता के लिए डिजिटल रजिस्ट्री, प्रतिभूतिकृत आस्तियों में ट्रेडिंग के अवसर आदि जैसे अपेक्षित अहम कदमों की पहचान करने के लिए यह समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट अगस्त 2019 में आने वाली है।

सारांश यह कि, यह स्पष्ट हो कि भारतीय पूँजी बाजार जहाँ लगातार बढ़ते हुए दीर्घावधि व्यवहार्यता की अवस्था तक पहुँचे हैं, आगे और अधिक विकास व सुदृढीकरण की उनकी संभावना अनंत है...

‘तो फिर आइए कोशिशों में लग जाएं,
किसी भी परिणाम के लिए हों तैयार;

श्रम व धैर्य का पाठ पढ़ते हुए;

हासिल करते चलें मुकाम

और बढ़ते चलें मंजिलों की ओर’

(‘लेट अस, देन बी अप एंड डूइंग,

विद ए हर्ट फॉर एनी फेट;

स्टिल एचिविंग, स्टिल पर्स्यूइंग

लर्न टू लेबर एंड डू वेट।’)

- ए सैल्म ऑफ़ लाइफ
हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफैलो
(1807 – 1882)

लेख

भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और उसका व्यापक आर्थिक प्रभाव

2011-12 से 2017-18 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का
वित्तीय भण्डार और प्रवाह

भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और उसका व्यापक आर्थिक प्रभाव*

इस अध्ययन में जेनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स का उपयोग करके भारत में व्यापक आर्थिक परिणामों पर जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रभाव की जांच की गयी है। अनुमान के परिणामों से पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि और आयु निर्भरता अनुपात का वास्तविक जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ प्रतिकूल संबंध है, और मुद्रास्फीति के साथ सकारात्मक संबंध है। दूसरी ओर, काम करने की उम्र वाली जनसंख्या में वृद्धि से उच्चतर आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। यद्यपि वृद्ध आबादी को अपस्फीति माना जाता है, तथापि यह चालू खाता संतुलन में सुधार करता है। जहां घटती आयु निर्भरता अनुपात भारत के लिए एक जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करता है, वहीं उसे हासिल करने के लिए एक ऐसे माहौल की आवश्यकता होगी जो सही कौशल के साथ श्रम बल को सशक्त बनाए और उत्पादक उपयोगों में उनके लाभकारी रोजगार को सक्षम बनाए।

परिचय

वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होती आबादी वाली दुनिया में भारत की अनुकूल जनसांख्यिकी ने इसे एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा है, जिसका कारण मुख्य रूप से संभावित व्यापक आर्थिक लाभांश है जो युवा को प्राप्त होता है: जहां कामकाजी आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि को आम तौर पर प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि के तौर पर देखा जाता है, वहीं बुजुर्गों/आश्रितों की श्रेणियों में वृद्धि को प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि को कम करने वाला माना जाता है (आईएमएफ, 2004; किम; 2016)। जनसांख्यिकी, हालांकि, नियति नहीं है; स्वचालन और तकनीकी विकास ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्ध होती जनसंख्या के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर दिया है। यहां तक कि स्वयं अनुकूल जनसांख्यिकी भी सिर्फ अत्यधिक समृद्धि के लिए एक आवश्यक शर्त हो सकती है। उनकी क्षमता का दोहन ही महत्वपूर्ण पर्याप्त शर्त है।

* यह लेख भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के अत्रि मुखर्जी, प्रियंका बजाज और सार्थक गुलाटी द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

भारत की 1.3 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या 2025 तक 1.4 बिलियन, 2030 तक 1.5 बिलियन और 2050 तक 1.6 बिलियन होने का अनुमान है। साथ ही बढ़ती जीवन प्रत्याशा और गिरती प्रजनन क्षमता के परिणामस्वरूप लोगों की उम्र प्रोफ़ाइल के मामले में भी बड़े जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं (यूएन, 2019)। क्या ये अनुमानित जनसांख्यिकी भविष्य के व्यापक आर्थिक परिणामों को प्रभावित करेगी? इस अस्तित्वगत प्रश्न से प्रेरित होकर, यह लेख इस बात की पड़ताल करता है कि समय के साथ और विशेष रूप से जनसांख्यिकीय कारक कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे वे प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक चर के साथ सह-स्थानांतरित हुए हैं और वे दशकों से जो संबंध जताते आए हैं वो अब बहुत दूर नहीं है।

इस आलेख के बाकी हिस्सों को पांच खंडों में बांटा गया है: खंड II में विभिन्न चैनलों का विस्तारपूर्वक किए गए विभिन्न अध्ययनों पाठों और निष्कर्षों के अवलोकन के साथ एक संक्षिप्त सैद्धांतिक पृष्ठभूमि दिया गया है जिसके माध्यम से जनसांख्यिकीय परिवर्तन समष्टि आर्थिक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत में वर्तमान जनसांख्यिकीय संरचना और समय के साथ हुए परिवर्तन से संबंधित कुछ अस्वाभाविक तथ्य खंड III में दिए गए हैं। खंड IV में भारत में समष्टि आर्थिक विकास में जनसांख्यिकीय कारकों की भूमिका की अनुभवजन्य जांच में प्रयुक्त डेटा और कार्यप्रणाली की व्याख्या की गयी है। निष्कर्ष टिप्पणियां खंड V में दी गई हैं।

II. सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और अनुभवसिद्ध साहित्य की समीक्षा

किसी भी देश में जनसांख्यिकी मोटे तौर पर पांच चरणों से गुजरती है (ब्लैकर, 1947)। पहले चरण में, कोई देश उच्च जीवन दर और मृत्यु दर का अनुभव करता है जिसका परिणाम यह होता है कि निम्न जीवन प्रत्याशा के साथ आबादी स्थिर हो जाती है। जैसे-जैसे देश की रुग्णता का बोझ कम होता है, वैसे-वैसे गिरती हुई अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) और उच्च अशोधित जन्म दर (सीबीआर)¹ से जनसांख्यिकीय संक्रमण के दूसरे चरण की शुरुआत होती है, जो 0-14 वर्ष के आयु वर्ग में

¹ अशोधित जन्म दर = देश की मध्य-वर्ष की जनसंख्या द्वारा विभाजित वर्ष के दौरान जीवित जन्मों की संख्या। दर को आमतौर पर "प्रति 1000 जनसंख्या" के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर = देश की मध्य वर्ष की जनसंख्या द्वारा विभाजित वर्ष के दौरान हुई मृत्यु की संख्या। दर को आमतौर पर "प्रति 1000 जनसंख्या" के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है।

चार्ट 1: जनसांख्यिकीय संक्रमण के पांच चरण

चरण 1 उच्च स्थिरता	चरण 2 शीघ्र विस्तार	चरण 3 देर से विस्तार	चरण 4 कम स्थिरता	चरण 5 गिरावट
उच्च जन्म और मृत्यु दर से जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो जाती है	मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होने से जनसंख्या विस्फोट हो जाता है	मृत्यु दर के तेजी से गिरने के साथ जन्म दर गिरने लगती है तो जनसंख्या घटती दर से बढ़ती है।	मृत्यु दर के समान जन्म दर में कमी आती है तो जनसंख्या का वृद्धि दर स्थिर हो जाता है	मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि में गिरावट होने लगती है
→	→	→	→	→

स्रोत : ब्लैकर, 1947।

बच्चों के एक आश्रित आबादी के रूप में अभिलक्षित होता है। धीरे-धीरे, बेहतर शिक्षा के साथ प्रजनन दर में गिरावट होती है और तीसरे चरण में देश में आर्थिक रूप से सक्रिय वयस्क आबादी के समूह में विस्तार होता है। अगले चरण में, जनसंख्या की औसत दीर्घायु धीरे-धीरे बढ़ती जाती है और जन्म दर और मृत्यु दर लगभग एक बराबर हो जाने से जनसंख्या स्थिर हो जाती है। जन्म दर से मृत्यु दर अधिक हो जाने के कारण हुई जनसंख्या में आयी कमी जनसांख्यिकीय संक्रमण के अंतिम चरण को परिलक्षित करती है (चार्ट 1)।

जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के समष्टि-आर्थिक परिणामों पर सैद्धांतिक शोध 18वीं शताब्दी की है जब माल्थस (1798) ने सुझाव दिया था कि आर्थिक विकास दुनिया की आबादी में निरंतर तेज वृद्धि का मुकाबला करने में विफल होगा, जिससे अंततः संसाधनों की कमी हो जाएगी और एक प्रलय के दिन जैसा परिदृश्य होगा। हालांकि, जैसा कि तकनीकी नवाचारों ने उच्च कृषि उत्पादन और मजबूत आर्थिक विकास को सक्षम बनाया है उससे एक ऐसे जनसांख्यिकीय समूह का उदय हुआ जिसने इस विचार की वकालत की कि जनसंख्या वृद्धि एक अर्थव्यवस्था के लिए एक आस्ति हो सकती है। उनके अनुसार, बड़ी आबादी वाले देशों और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने की क्षमता बड़े घरेलू बाजार और श्रम विभाजन से लाभान्वित होगी, क्योंकि ये दोनों आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं (हैरोड, 1939; सोलो, 1956)।

कई ऐसे चैनल हैं जिनके माध्यम से जनसांख्यिकीय परिवर्तन व्यापक आर्थिक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले, आयु प्रोफाइल और जनसंख्या की वृद्धि दर सीधे श्रम की उपलब्धता को प्रभावित करती है जो कि उत्पादन प्रक्रिया में एक प्रमुख कारक इनपुट है। जैसे ही कोई देश जनसांख्यिकीय विकास के दूसरे चरण से तीसरे और चौथे चरण में प्रवेश करता है, वैसे ही उल्लेखनीय रूप से आश्रितों की संख्या से अधिक काम करने वाली आबादी के साथ जनसांख्यिकीय लाभांश सामने आता है। इसके अलावा, कम प्रजनन दर और उच्च शिक्षा तक बढ़ती पहुंच ने अधिक से अधिक महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने में सक्षम बनाया है, जिससे श्रम आपूर्ति, उच्च आर्थिक विकास और सरकार के लिए उच्च कर संग्रह हुआ और वृद्धि हुई। आयु प्रोफाइल भी कर की दरों और काम करने के प्रोत्साहन को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अधिक कामकाजी उम्र वाली आबादी कर संग्रह में उछाल ला सकती है और कर दरों को कम करने की सुविधा प्रदान कर सकती है, जिससे काम करने के लिए प्रोत्साहन को बढ़ावा मिल सकता है।

दूसरा, जीवन-चक्र की परिकल्पना से पता चलता है कि बचत-निवेश चैनल के माध्यम से जनसंख्या की आयु संरचना संचालित होती है। लोग अपनी जवानी के दौरान शुद्ध उधारकर्ताओं के रूप में शुरुआत करते हैं, काम के वर्षों के दौरान शुद्ध बचतकर्ता बन जाते हैं, और अंततः सेवानिवृत्ति के बाद अधिव्ययकर्ता बन जाते हैं। इस प्रकार, कार्यशील जनसंख्या

में वृद्धि अर्थव्यवस्था में सकल बचत के स्तर को बढ़ा सकती है, जिससे विकास के लिए घरेलू वित्तपोषण की उपलब्धता का विस्तार होगा। नियोक्लासिकल सिद्धांत बताता है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दूसरे चरण से आर्थिक वृद्धि तेज हो जाती है क्योंकि श्रम बल में शामिल होने वाले नए लोगों को रोजगार और आवास प्रदान करने के लिए जनसंख्या संवेदनशील निवेश (जैसे निर्माण और आवास) गति पकड़ लेती है (कुज्नेट्स, 1958)।

तीसरा, जनसांख्यिकीय परिवर्तन कुल मांग चैनल के माध्यम से वृद्धि (और मुद्रास्फीति) को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरे चरण में युवा आबादी की वृद्धि और जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण में आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी से कुल मांग में वृद्धि हो जाती है। सुदीर्घकालिक गतिहीनता परिकल्पना (हैनसेन, 1938) भी जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आने पर जनसांख्यिकीय संक्रमण के चौथे और पांचवें चरण में निम्न मुद्रास्फीति और निम्न वृद्धि की अवधि की व्याख्या करने के लिए मांग चैनल पर ही निर्भर रहती है।

चौथा, सरकार के वित्त के लिए जनसांख्यिकीय कारकों में महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। जीवन चक्र मॉडल बताता है कि उच्च कर राजस्व और बढ़ी हुई सार्वजनिक बचत से जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के मध्य अवस्था के दौरान राजकोषीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिलती है। दूसरी ओर, उसके बाद की अवस्था में बुजुर्ग आश्रित व्यक्तियों का एक बड़ा तबका स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन पर उच्च सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता पड़ती है, जिससे सरकार का वित्त बिगड़ता चला जाता है।

जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के समष्टि-आर्थिक प्रभाव के प्रयोगसिद्ध जांच का प्रसार हुआ है (परिशिष्ट सारणी 1)। एक आम सहमति इस बात की ओर अभिमुख होती है कि निर्भरता अनुपात जीडीपी / प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है (जो एंड अग्रवाल, 2015; यू, एवं अन्य, 2014 और संडमैन, 2011)। उच्च मानव पूंजी वाले देशों में प्रजनन दर कम होती है और प्रति व्यक्ति जीडीपी विकास दर अधिक होती है (बैरो, 1991, ली; एवं अन्य, 2016, मोहन, 2004)।

मुद्रास्फीति दर निर्धारित करने में आयु संरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हालांकि प्रभाव की दिशा और

परिमाण अलग-अलग देशों में और समय के साथ भिन्न होते हैं (हान, 2019; जुसेलियस एंड टाकाट्स, 2018; बोबिका एंड सन, 2017)।

बचत-निवेश चैनल के माध्यम से जनसंख्या उम्रवृद्धि से चालू खाता शेष प्रभावित हो सकता है (हिगिंस, 1998)। अपेक्षाकृत तेजी से वृद्ध होने वाला देश घरेलू निवेश की मांग में गिरावट के कारण अपने चालू खाते के संतुलन में सुधार का अनुभव करेगा जो राष्ट्रीय बचत में कटौती से अधिक है। इस प्रकार, जनसंख्या वृद्धत्व से वृद्ध होती जनसंख्या वाले देशों से अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह अपेक्षाकृत युवा आबादी वाले देशों में हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे नव औद्योगिक और विकासशील देशों में होता है (फौगेर एंड मेरेट, 1999)।

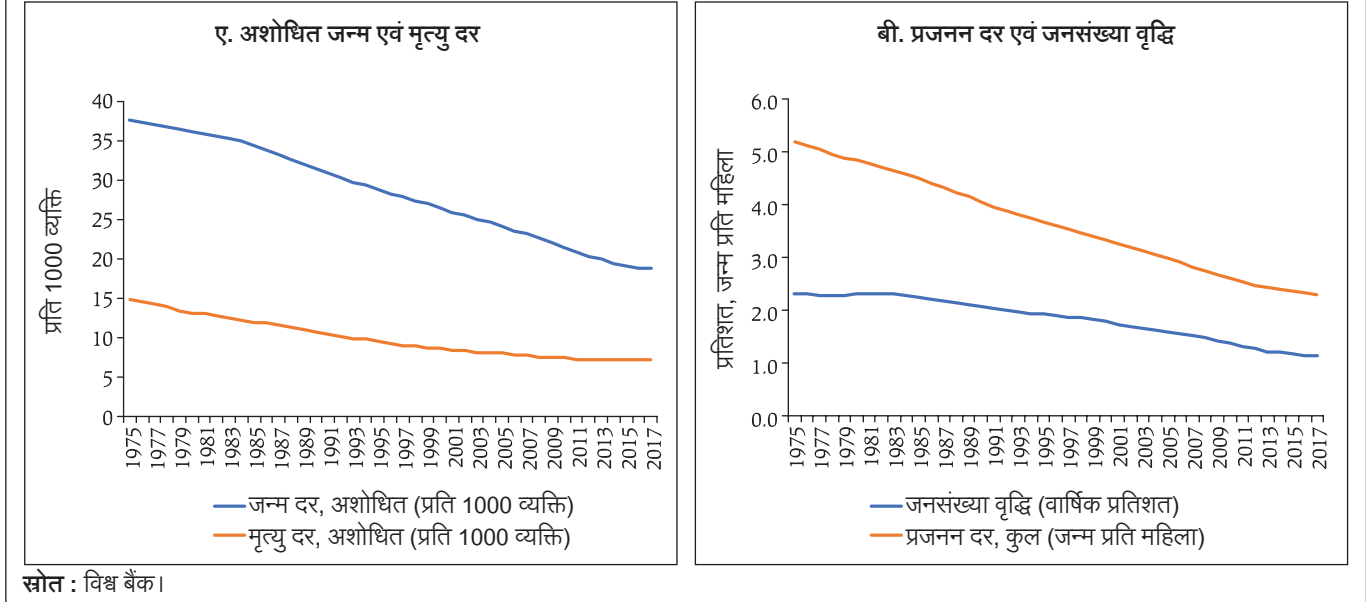
भारतीय संदर्भ में, कामकाजी आयु वाली जनसंख्या के स्तर और वृद्धि दर दोनों का आर्थिक विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है (अय्यर एंड मोदी, 2011)। राज्य-स्तरीय विश्लेषण से पता चलता है कि आने वाले वर्षों में बीमारू² (BIMARU) राज्यों में कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि होने की संभावना है (उत्सव कुमार, 2010)। इस प्रकार, भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश मुख्य रूप से बीमारू (BIMARU) राज्यों की कामकाजी आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि का फायदा उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। पहला जनसांख्यिकीय लाभांश 1980-2035 के दौरान कामकाजी उम्र की आबादी की अधिक उपलब्धता के रूप में है, जबकि सेवानिवृत्ति का समर्थन करने के लिए उच्च बचत के रूप में दूसरा जनसांख्यिकीय लाभांश वर्ष 2035 से प्रमुखता हासिल कर सकता है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश 2070 तक बना रह सकता है (लाडूसिंह एंड नारायण, 2011)।

III. शोधपरक तथ्य

विश्व बैंक (विश्व विकास संकेतक) के वार्षिक आंकड़ों से पता चलता है कि भारत इस समय तेजी से घट रहे अशोधित जन्म दर (सीबीआर) और अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) के साथ जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण में है, हालांकि सीडीआर की तुलना में सीबीआर अधिक है (चार्ट 2.ए)। 1975 से 2017 की अवधि के दौरान, प्रजनन दर प्रति महिला 5.2 से गिरकर 2.3 जन्म तक हो गई। नतीजतन, जनसंख्या वृद्धि दर

² बीमारू (BIMARU) बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दर्शाता है।

चार्ट 2: भारत में जनसंख्या संक्रमण

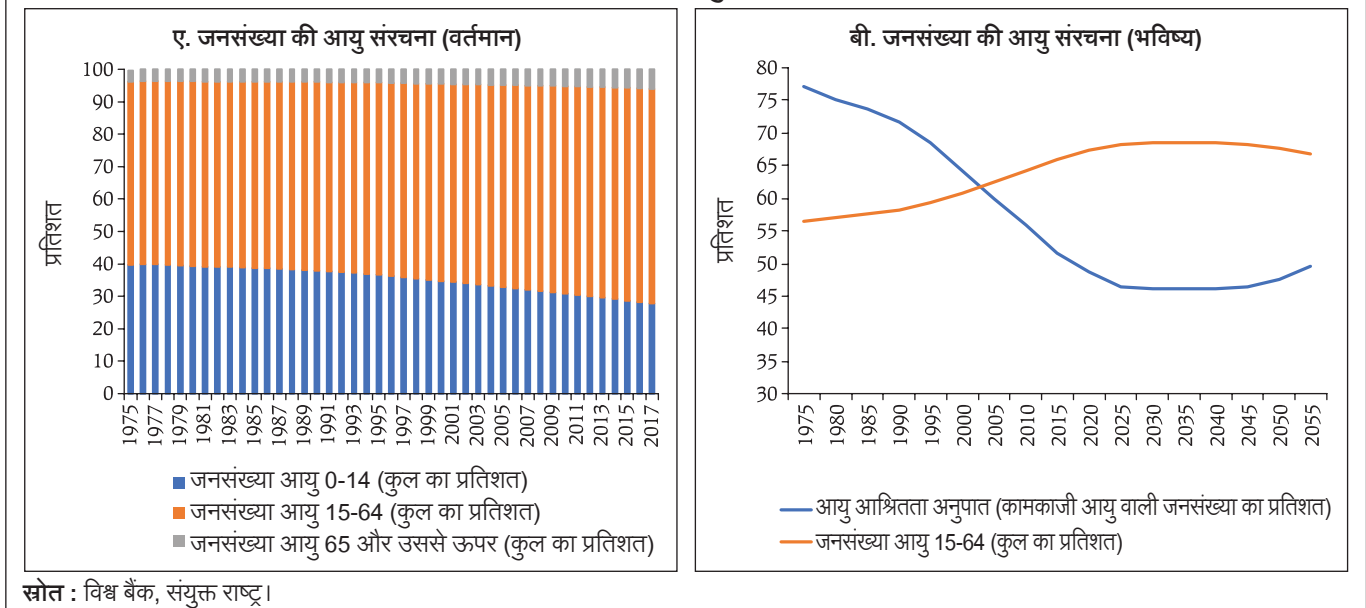


1975 में 2.3 प्रतिशत से घटकर 2017 में 1.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट 2. बी) और वर्ष 2055-60 तक इसे बढ़कर 0.03 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद यह नकारात्मक हो सकता है (यूएन, 2019³)।

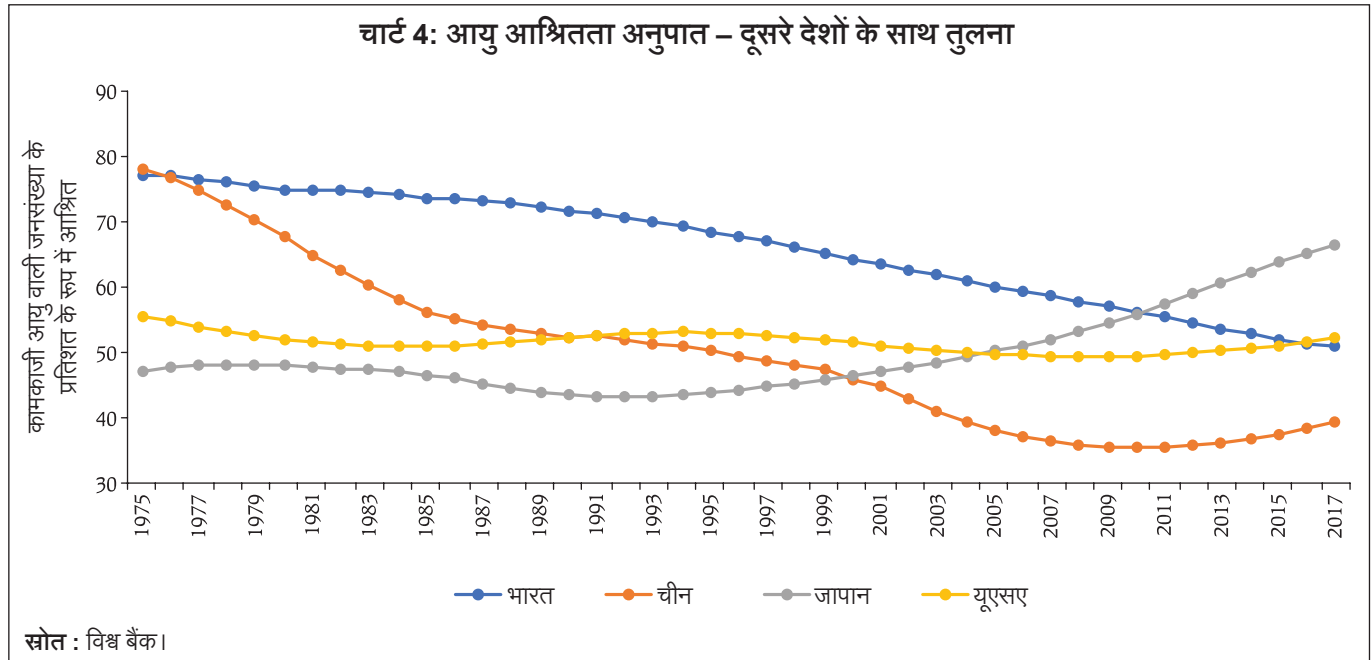
भारत की जनसंख्या की आयु संरचना में 1975-2017 की अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं - कुल जनसंख्या में

कामकाजी आयु (15-64 आयु वर्ग) की हिस्सेदारी 56.5 प्रतिशत से बढ़कर 66.2 प्रतिशत हो गई; युवा (0-14 वर्ष) की हिस्सेदारी में 40 प्रतिशत से घटकर 27.8 प्रतिशत हो गई; और बुजुर्गों की हिस्सेदारी (65 वर्ष और उससे अधिक) में 3.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई (चार्ट 3ए)।

चार्ट 3: जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन



³ संयुक्त राष्ट्र का 2019 विश्व जनसंख्या परिदृश्य का संशोधन।



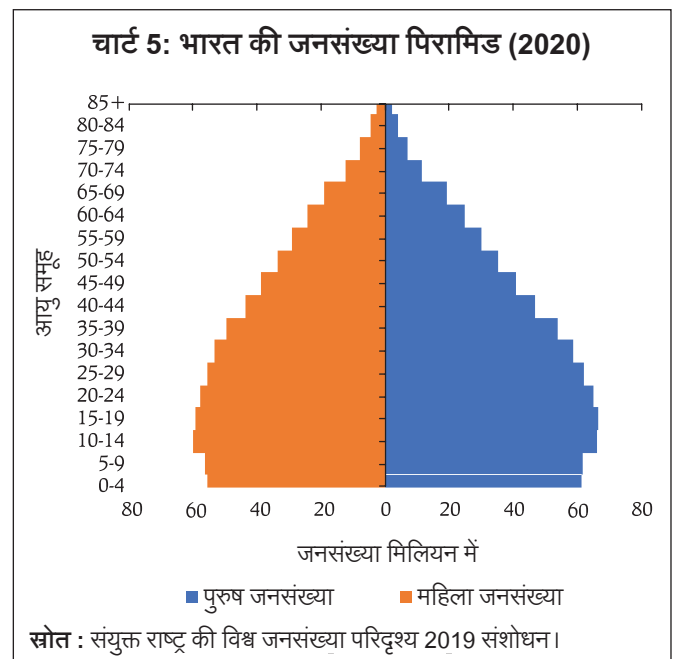
इस बदलती आयु संरचना को आयु निर्भरता अनुपात द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जा सकता है – कुल कामकाजी आयु वाली जनसंख्या की तुलना में कुल आश्रित जनसंख्या का अनुपात (0-14 वर्ष और 65+ वर्ष) कम है तो इसका आशय अधिक उत्पादकता वाली जनसंख्या से है। भारत का आयु निर्भरता अनुपात घट रहा है और इसे 2025 तक घटते रहने की संभावना है जिसके बाद यह 2040 तक स्थिर रह सकता है और इसके बाद बढ़ सकता है (यूएन, 2019) (चार्ट 3बी)। एक अलग स्तर पर, वृद्ध आश्रितता अनुपात (कामकाजी आयु वाली जनसंख्या की तुलना में आश्रित जनसंख्या का अनुपात) धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जबकि युवा आश्रितता अनुपात (कामकाजी आयु वाली जनसंख्या की तुलना में युवा आश्रित जनसंख्या का अनुपात) तेजी से घट रहा है। वर्ष 1975 और 2017 के बीच, वृद्ध आश्रितता अनुपात 6.2 प्रतिशत से बढ़कर 9.0 प्रतिशत हो गया और युवा आश्रितता अनुपात 71.0 प्रतिशत से गिरकर 41.9 प्रतिशत हो गया।

अन्य देशों, यथा चीन, अमेरिका और जापान के साथ भारत के आयु निर्भरता अनुपात की तुलना से पता चलता है कि भारत एक लाभप्रद स्थिति में है क्योंकि उन देशों के लिए आयु निर्भरता अनुपात बढ़ रहा है, जबकि भारत में यह कम हो रहा है (चार्ट 4)।

भारत के लिए जनसंख्या पिरामिड 10-24 आयु के जनसंख्या वर्ग के लोगों में एक अस्थायी वृद्धि को भी दिखाता है,

जिसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्ष भारत की श्रम शक्ति में निरंतर वृद्धि आने वाले कई वर्षों तक अहम रहेगी (चार्ट 5), जिससे अगले कुछ दशकों तक जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने का अवसर मिलेगा।

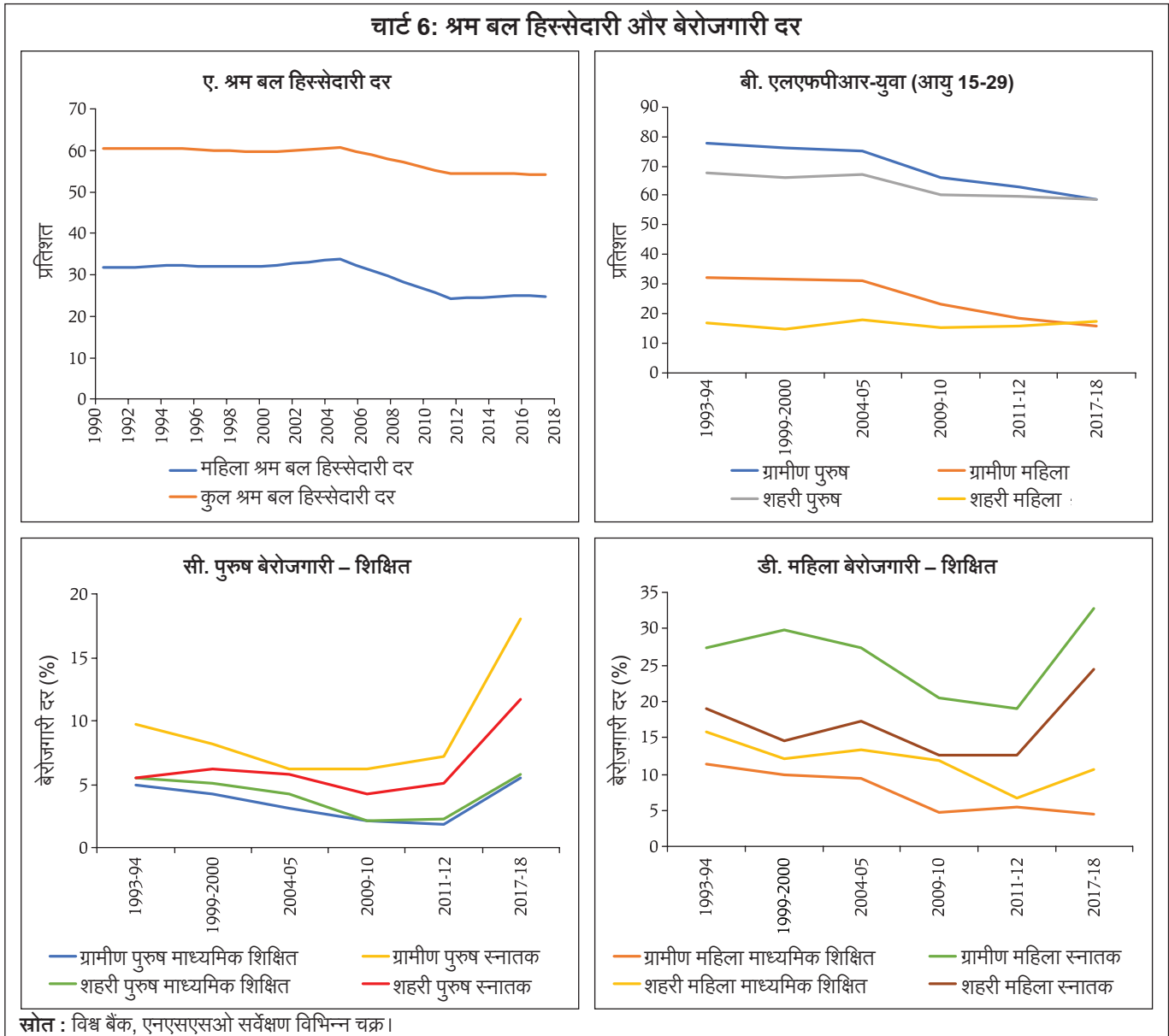
कामकाजी आयु वाली जनसंख्या की उल्लेखनीय और बढ़ती हिस्सेदारी के बावजूद भारत में श्रम बल की भागीदारी दर (एलएफपीआर) पिछले दशक से घट रही है और यह



आधी हो गयी है (चार्ट 6.ए)। भारत में महिला एलएफपीआर दुनिया में सबसे कम है (आईएलओ, 2013⁴)। वर्ष 2004-05 के बाद से युवा एलएफपीआर में तेज गिरावट आई है (चार्ट 6.बी)। घटते एलएफपीआर के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यथा शिक्षा में बढ़ता नामांकन; बढ़ती घरेलू आय; और पर्याप्त उत्पादक रोजगार के अवसरों की कमी है। पुरुष और महिला दोनों समूहों के लिए, बेरोजगारी की दर

अत्यधिक शिक्षितों के लिए ज्यादा है, जिसमें वर्ष 1993-1994 से 2017-18 की पूरी अवधि के दौरान उच्चतम बेरोजगारी दर वाले स्नातक शामिल हैं (चार्ट 6सी और 6डी)। तुलनात्मक रूप से, माध्यमिक शिक्षा वाले पुरुषों और महिलाओं की बेरोजगारी दर काफी कम है, जिसका अर्थ है कि भारत की श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा कुशल श्रम की संभावित कमी के कारण अनौपचारिक और अकुशल/अर्ध-कुशल काम में लगा हुआ है।

चार्ट 6: श्रम बल हिस्सेदारी और बेरोजगारी दर



⁴ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की वैश्विक रोजगार प्रवृत्ति रिपोर्ट, 2013।

IV. प्रयोगसिद्ध विश्लेषण

इस खंड में अनुभव के आधार पर यह परखने की कोशिश की गई है कि भारत की जनसंख्या के आकार एवं संरचना में बदलाव से समष्टिआर्थिक नतीजों पर क्या असर पड़ता है। इसमें 1975 से 2017 समयावधि का अध्ययन किया गया है जिस के लिए उन चरों हेतु नियमित डेटा उपलब्ध हैं, जो विचाराधीन हैं। जनसंख्या के आकार एवं उसमें हुए बदलाव को जनसंख्या की वृद्धि दर के जरिए पता लगाया जाता है, जबकि जनसंख्या की संरचना में हुए बदलाव को आयु निर्भरता अनुपात, कुल जनसंख्या में कामकाजी उम्र वाली आबादी एवं बढ़ती उम्र वाली आबादी में वृद्धि (अर्थात् 65 वर्ष की आयु के ऊपर वाली जनसंख्या) के जरिए पता लगाया जाता है। विश्लेषण में जिन समष्टिआर्थिक चरों पर विचार किया जा रहा है, वे हैं, वास्तविक जीडीपी वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, मुद्रास्फीति, राजकोषीय शेष एवं बाह्य चालू खाता शेष। जनसांख्यिकीय चर संबंधी डेटा का स्रोत वर्ल्ड बैंक का विश्व विकास संकेतक डेटाबेस है, जबकि समष्टिआर्थिक चर संबंधी डेटा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हस्तपुस्तिका से प्राप्त किए जाते हैं।

संभाव्य अंतः जनित समस्याओं के मद्देनजर, निम्नलिखित मॉडल के प्राक्कलन के लिए जेनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेन्ट्स (जीएमएम) कार्यप्रणाली का प्रयोग किया गया है :

$$Y_t = \alpha + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 X_t + \varepsilon_t \dots\dots\dots (1)$$

जिसमें Y एक आश्रित चर है, अर्थात्, ब्याज का समष्टिआर्थिक चर। X व्याख्यात्मक चर है, अर्थात्, प्रासंगिक जनसांख्यिकीय चर, जिसे मल्टीकोलीनिअरिटी से बचने के लिए एक समय में माना जाता है (अनुबंध सारणी 2)। यूनिट रूट टेस्ट दर्शाते हैं कि (0) प्रासंगिक आश्रित एवं व्याख्यात्मक चर हैं (अनुबंध सारणी 3)⁵।

जीएमएम प्राक्कलक की दक्षता लिखतों की वैधता पर निर्भर करती है। इस मामले में, जीएमएम के लिए लिखतों के रूप में आश्रित एवं व्याख्यात्मक चरों के अंतराल मूल्यों का उपयोग

⁵ कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी एवं बढ़ती उम्र वाली आबादी में वृद्धि, ये दो जनसांख्यिकीय चर केवल ट्रेंड स्टेशनरी के रूप में पाए गए थे। डी-ट्रेंडिंग के लिए, समय के रुझान को प्रासंगिक समीकरणों में एक स्वतंत्र चर के रूप में पेश किया गया है।

किया जाता है। सरगन-हेन्सन जे टेस्ट के माध्यम से इस मॉडल की मजबूती को परखा जाता है, जिसके लिए शून्य की स्वीकृति की आवश्यकता होती है और उस पर पाबंदियों को पहचानना वैध है ताकि लिखतों की वैधता स्थापित की जा सके।

नतीजे दर्शाते हैं कि भारत में उच्च जनसंख्या वृद्धि का उच्च वास्तविक जीडीपी वृद्धि के साथ कोई सरोकार नहीं है (सारणी 1)। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में उच्च जनसंख्या वृद्धि उच्च प्रजनन एवं जन्म दरों का नतीजा है। वैसे उच्च जन्म दरों से जनसंख्या में युवाओं की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन उच्च प्रजनन दर महिलाओं को उच्च शिक्षा के माध्यम से कार्यबल में शामिल होने से रोकता है और दोनों प्रभावी श्रम आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जनसंख्या वृद्धि के बजाय, यह कामकाजी उम्र वाली आबादी की वृद्धि के साथ-साथ श्रम बल की भागीदारी दर है जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

जैसा कि अपेक्षित था, भारत में आयु निर्भरता अनुपात का वास्तविक जीडीपी वृद्धि के साथ उलटा संबंध है जबकि कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी का सकारात्मक संबंध है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि निर्भरता अनुपात बढ़ता

सारणी 1: वास्तविक जीडीपी वृद्धि पर जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का प्रभाव

व्याख्यात्मक चर	आश्रित चर : वास्तविक जीडीपी वृद्धि			
	(1)	(2)	(3)	(4)
जनसंख्या वृद्धि	-2.82***			
आयु निर्भरता अनुपात		-0.15***		
कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी			0.09***	
बुजुर्ग आबादी में वृद्धि				-1.23
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (-1)	-0.10	-0.12	-0.11	-0.19*
कॉन्सटेंट	11.85***	16.50***		7.84**
टाइम ट्रेंड			0.07**	0.14***
अडजेस्टड आर-स्क्वयर्ड	0.12	0.13	0.13	0.15
सरगुन-हनसेन जे-टेस्ट	(0.70)	(0.90)	(0.89)	(0.50)

टिप्पणी : 1. ***, ** और * क्रमशः 1%, 5% एवं 10% स्तर पर पर्याप्त का द्योतक है।
2. कोष्ठकों में दिए हुए आंकड़े संबंधित पी-वैल्यू दर्शाते हैं।

सारणी 2: प्रति व्यक्ति आय वृद्धि पर जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का प्रभाव

व्याख्यात्मक चर	आश्रित चर : प्रति व्यक्ति आय वृद्धि			
	(1)	(2)	(3)	(4)
जनसंख्या वृद्धि	-3.92***			
आयु निर्भरता अनुपात		-0.20***		
कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी			0.03**	
बुजुर्ग आबादी में वृद्धि				-0.56
प्रति व्यक्ति आय वृद्धि (-1)	-0.10	-0.12	-0.12	-0.15
कॉन्सटेंट	11.75***	17.89***		3.51
टाइम ट्रेंड			0.13***	0.14***
अडजेस्टेड आर-स्क्वयर्ड	0.23	0.24	0.25	0.25
सरगुन-हनसेन जे-टेस्ट	(0.71)	(0.91)	(0.94)	(0.27)

टिप्पणी : 1. ***, ** और * क्रमशः 1%, 5% एवं 10% स्तर पर पर्याप्त का द्योतक है।

2. कोष्ठकों में दिए हुए आंकड़े संबंधित पी-वैल्यू दर्शाते हैं।

है, तो जीडीपी वृद्धि बढ़ती है। दूसरी ओर, कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी बढ़ने से श्रम आपूर्ति में वृद्धि होती है और इस प्रकार उच्च उत्पादन और वास्तविक जीडीपी वृद्धि⁶ होती है। जीडीपी पर बुजुर्ग आबादी में वृद्धि का प्रभाव नकारात्मक निकला, भले ही वह सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन है।

प्रति व्यक्ति आय वृद्धि पर जनसांख्यिकीय चर का प्रभाव काफी हद तक समग्र वास्तविक जीडीपी वृद्धि के समान है। अधिक आयु निर्भरता अनुपात का प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि कामकाजी उम्र वाली आबादी में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है (सारणी 2)।

मुद्रास्फीति पर जनसंख्या की गतिशीलता के प्रभाव को लेकर बहुत सीमित शोध हुआ है। अनुमान के नतीजे बताते हैं कि उच्च जनसंख्या वृद्धि और आयु निर्भरता अनुपात सीपीआई मुद्रास्फीति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते

सारणी 3: सीपीआई मुद्रास्फीति पर जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का प्रभाव

व्याख्यात्मक चर	आश्रित चर : सीपीआई मुद्रास्फीति			
	(1)	(2)	(3)	(4)
जनसंख्या वृद्धि	2.01*			
आयु निर्भरता अनुपात		0.10**		
कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी			-0.90	
बुजुर्ग आबादी में वृद्धि				-3.55*
सीपीआई मुद्रास्फीति (-1)	0.25**	0.26**	0.38***	0.45***
कॉन्सटेंट	2.30	-0.77	54.79	15.24***
टाइम ट्रेंड			0.19	0.01
अडजेस्टेड आर-स्क्वयर्ड	0.09	0.09	0.12	0.01
सरगुन-हनसेन जे-टेस्ट	(0.72)	(0.68)	(0.74)	(0.21)

टिप्पणी : 1. ***, ** और * क्रमशः 1%, 5% एवं 10% स्तर पर पर्याप्त का द्योतक है।

2. कोष्ठकों में दिए हुए आंकड़े संबंधित पी-वैल्यू दर्शाते हैं।

हैं, संभवतः आपूर्ति के सापेक्ष कुल मांग में वृद्धि से। मुद्रास्फीति पर कामकाजी उम्र वाली आबादी का प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं पाया गया। बुजुर्ग आबादी में वृद्धि के लिए गुणांक का नकारात्मक/ऋणात्मक संकेत यह दर्शाता है कि कुल मांग में कमी के चलते बढ़ती उम्र वाली आबादी में वृद्धि अपस्फीति का कारण बन सकती है, भले ही इस चरण में बचत कम हुई हो (सारणी 3)।

जीवन चक्र परिकल्पना के अनुसार, कामकाजी उम्र वाली आबादी के एक बड़े हिस्से को कर संग्रह के माध्यम से सरकार के लिए अधिक से अधिक राजस्व उत्पन्न करना चाहिए और इस प्रकार सरकारी वित्त में सुधार करना चाहिए। दूसरी ओर, बढ़ती उम्र वाली आबादी पर पेंशन और स्वास्थ्य सेवा को लेकर अधिक खर्च करने की आवश्यकता होगी जिससे सरकार के वित्त में और कमी आएगी।

जैसा कि अपेक्षित था, जनसंख्या वृद्धि राजकोषीय घाटे को बढ़ाती है (सारणी 4)। हालांकि, अन्य जनसांख्यिकीय चरों के गुणांक सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन निकले। इसके अलावा, बुजुर्ग आबादी में वृद्धि से राजकोषीय घाटे में वृद्धि नहीं होती है,

⁶ 1990-2017 की अवधि के लिए व्याख्यात्मक चर के रूप में कुल आबादी में श्रम बल की हिस्सेदारी के साथ एक समान विश्लेषण किया गया था क्योंकि श्रम बल के संबंध में 1990 से पहले के डेटा उपलब्ध नहीं है। जीएमएम के नतीजे दर्शाते हैं कि श्रम बल में वृद्धि वास्तविक जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में सकारात्मक प्रभाव डालती है। हालांकि, अन्य समष्टिआर्थिक चरों पर श्रम बल का प्रभाव सांख्यिकीय रूप से अधिक नहीं था।

सारणी 4: सामान्य सरकार के राजकोषीय घाटे पर जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का प्रभाव

व्याख्यात्मक चर	आश्रित चर : जीडीपी के प्रतिशत (जीएफडी-जीडीपी) के रूप में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
जनसंख्या वृद्धि	0.65*			
आयु निर्भरता अनुपात		0.01		
कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी			-0.49	
बुजुर्ग आबादी में वृद्धि				-1.32
जीएफडी - जीडीपी (-1)	0.76***	0.67***	0.60***	0.56***
कॉन्सटेंट	0.48	1.90	29.83	6.26*
टाइम ट्रेंड			0.12	0.05
अडजेस्टड आर-स्क्वयर्ड	0.38	0.47	0.49	0.31
सरगुन-हनसेन जे-टेस्ट	(0.20)	(0.66)	(0.72)	(0.17)

टिप्पणी : 1. ***, ** और * क्रमशः 1%, 5% एवं 10% स्तर पर पर्याप्त का द्योतक है।

2. कोष्ठकों में दिए हुए आंकड़े संबंधित पी-वैल्यू दर्शाते हैं।

जो असहज (काउंटर-इन्ट्यूशिव) है, लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था इतनी विकसित नहीं है।

बढ़ती उम्र वाली आबादी का बाह्य चालू खाता संतुलन पर बचत-निवेश चैनल (हिगिंस, 1998; फौगरे और मेरेट, 1999) के माध्यम से प्रभाव पड़ सकता है। नतीजे दर्शाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि, आयु निर्भरता अनुपात और कामकाजी उम्र वाली आबादी भारत में चालू खाता शेष पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालती हैं। हालांकि, बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि भारत में चालू खाता घाटे को कम करती है और यह घरेलू निवेश की मांग में कमी के कारण हो सकती है जो घरेलू बचत में आई गिरावट से अधिक है (सारणी 5)।

V. निष्कर्ष

भारत में समष्टिआर्थिक नतीजों पर जनसांख्यिकीय बदलावों के असर को परखने से पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि और आयु निर्भरता अनुपात का वास्तविक जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ विपरीत संबंध है, और मुद्रास्फीति के साथ सकारात्मक संबंध है। दूसरी ओर, कामकाजी उम्र वाली

सारणी 5: चालू खाता घाटे पर जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का प्रभाव

व्याख्यात्मक चर	आश्रित चर : जीडीपी के प्रतिशत (सीएडी-जीडीपी) के रूप में चालू खाता घाटा (सीएडी)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
जनसंख्या वृद्धि	-0.04			
आयु निर्भरता अनुपात		-0.004		
कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी			0.14	
बुजुर्ग आबादी में वृद्धि				-1.04*
सीएडी-जीडीपी (-1)	0.73***	0.70***	0.75***	0.63***
कॉन्सटेंट	0.45	0.70	-7.36	3.30*
टाइम ट्रेंड			-0.03	0.02*
अडजेस्टड आर-स्क्वयर्ड	0.57	0.57	0.56	0.63
सरगुन-हनसेन जे-टेस्ट	(0.75)	(0.34)	(0.39)	(0.32)

टिप्पणी : 1. ***, ** और * क्रमशः 1%, 5% एवं 10% स्तर पर पर्याप्त का द्योतक है।

2. कोष्ठकों में दिए हुए आंकड़े संबंधित पी-वैल्यू दर्शाते हैं।

आबादी के हिस्से में वृद्धि, उच्च आर्थिक विकास में योगदान करती है। बढ़ती उम्र वाली आबादी का स्वरूप अपस्फीति होता है, भले ही वह चालू खाता संतुलन में सुधार करती है।

भारत इस वक्त जनसांख्यिकीय बदलाव के कगार पर खड़ा है। जनसंख्या के रुझान बताते हैं कि आयु निर्भरता अनुपात में 2025 तक गिरावट आने और 2040 तक लगभग स्थिर बने रहने की उम्मीद है। इस प्रकार, भारत के लिए यह स्वर्ण युग है जिसमें उच्च वृद्धि के माध्यम से जनसांख्यिकीय लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि, एक अंधेरा पक्ष है - कुल आबादी में कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी में वृद्धि के बावजूद, भारत में श्रम बल की भागीदारी दर घट रही है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 15-29 वर्ष की आयु के बीच और महिला आबादी के बीच प्रमुख है। अनुकूल जनसांख्यिकी का लाभ उठाने के लिए, कौशल और लाभकारी रोजगार के साथ श्रम बल को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। आज के जॉब प्रोफाइल के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, भारत को अपने कार्यबल को कौशल प्रदान करने एवं उस कौशल को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कौशल विकास संस्थाएं वर्तमान में क्या करती हैं और उद्योग की क्या आवश्यकताएं हैं, इनके

बीच गंभीर अंतराल हैं। गुणवत्ता और पहुंच दोनों के संदर्भ में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार तथा सरकार, निजी क्षेत्र एवं शोधकर्ताओं द्वारा एक समन्वित तरीके से समय पर कार्रवाई जरूरी है ताकि अनुकूल जनसांख्यिकी द्वारा प्रदान किए गए अवसर का लाभ उठाया जा सके।

संदर्भ

- Aiyar, Shekhar and Mody, Ashoka (2011), 'The Demographic Dividend: Evidence from the Indian States', *IMF Working Paper No. 11/38*.
- Barro, R. (1991), 'Economic Growth in a Cross Section of Countries', *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 106, No. 2. (May, 1991), pp. 407-443.
- Blacker, C.P (1947), 'Stages in Population Growth', *The Eugenics Review*, 1947 Oct, 39(3): 88-101.
- Bloom, D. E., Canning, D., and Malaney, P. N. (1998), 'Demographic Change and Economic Growth in Asia', *Working Paper no. 15, Center for International Development at Harvard University*
- Bobeca, Elena, Lis, Eliza M., Nickel, Christiane and Sun, Yiqiao (2017), 'Demographics and Inflation', *ECB Working Paper No. 2006*.
- Brander, J. A., and Dowrick, S. (1994), 'The role of fertility and population in economic growth', *Journal of Population Economics*, February 1994, Volume 7, Issue 1, pp 1-25
- Han, Gaofeng (2019), 'Demographic Changes and Inflation Dynamics', *Hong Kong Institute for Monetary Research Working Paper No.02/2019*.
- Hansen, Alvin H. (1939), 'Economic Progress and Declining Population Growth', *The American Economic Review*, Vol. 29, No. 1 (March 1939), pp. 1-15.
- Harrod, Roy F. (1939). 'An Essay in Dynamic Theory', *The Economic Journal*, Vol. 49, No. 193 (March 1939), pp. 14-33
- Higgins, Matthew (1998), 'Demography, National Savings, and International Capital Flows', *International Economic Review*, 1998, vol. 39, issue 2, 343-69.
- International Labour Organisation (ILO) (2013), 'Global Employment Trend Report, 2013', Available at https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202326.pdf
- International Monetary Fund, 'World Economic Outlook 2004', Available at <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2004/02/>
- Joe, W., Dash, A. K., and Agrawal, P. (2015), 'Demographic Transition, Savings, and Economic Growth in China and India', *IEG Working Paper No. 351*
- Juselius, Mikael and Takáts, Előd (2018), 'The Enduring Link between Demography and Inflation', *BIS Working Paper No. 722*.
- Kim, Jinill (2016). 'The Effects of Demographic Change on GDP Growth in OECD Economies,' *IFDP Notes, Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, September 28, 2016*.
- Kumar, Utsav (2010), 'India's Demographic Transition: Boon or Bane? A State-Level Perspective,' *MPRA Paper 24922, University Library of Munich, Germany*.
- Ladusingh, L., and Narayana, M. R. (2011), 'Demographic Dividends for India: Evidence and Implications Based on National Transfer Accounts', *ADB Economics Working Paper Series No. 292*.
- LEE Sang-Hyop, KIM Jungsuk & PARK Donghyun (2016), 'Demographic Change and Fiscal Sustainability in Asia,' *Working Papers DP-2016-11, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)*.
- Malthus, Thomas Robert (1798), 'An Essay on The Principle of Population', Available at <http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf>
- Maxime Fougère and Marcel Mérette (1999), 'Population ageing and economic growth in seven OECD countries', *Economic Modelling*, 1999, vol. 16, issue 3, 411-427.
- Modigliani, Franco (1966), 'The Life Cycle Hypothesis of Saving, The Demand for Wealth And

The Supply Of Capital', *Social Research*, Vol. 33, No. 2, pp. 160-217.

Mohan, Rakesh (2004), 'Fiscal Challenges Of Population Ageing: The Asian Experience', Speech by Rakesh Mohan at the Global Demographic Change Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 26-28, 2004.

Solow, Robert M. (1956), 'A Contribution to the Theory of Economic Growth', *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 70, No. 1 (February 1956), pp. 65-94.

Sundman, Marie-Lor (2011), 'The effects of the Demographic Transition on Economic Growth: Implications for Japan', Thesis presented at Jönköping University, Jönköping International Business School.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (2019), 'World Population Prospects: The 2019 Revision', Available at <https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.html>

Yoon, Jong-Won and Kim, Jinill and Lee, Jungjin (2014), 'Impact of Demographic Changes on Inflation and the Macroeconomy', *IMF Working Paper No. 14/210*.

अनुबंध सारणी 1: अध्ययन की समीक्षा का सारांश

लेखक	समयावधि	परखे गए मुद्दे	अध्ययन के नतीजे/निष्कर्ष
संदमैन (2011)	1999-2009	कैसे जनसांख्यिकीय परिवर्तन आर्थिक विकास को प्रभावित करता है	जनसांख्यिकीय चरों, अर्थात्, जीवन प्रत्याशा और कुल निर्भरता अनुपात का प्रति व्यक्ति जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि श्रम शक्ति में उनका योगदान बहुत कम है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन का जापान पर सबसे बुरा असर पड़ा है।
जो, डैश और अग्रवाल (2015)	1970-2013	चीन और भारत में आर्थिक विकास पर बदलती जनसंख्या आयु संरचना का प्रभाव	चीन के मामले में, लंबे समय में, प्रति व्यक्ति जीडीपी बचत-जीडीपी अनुपात और निर्भरता अनुपात दोनों से प्रभावित है। हालांकि, भारत के मामले में, केवल निर्भरता अनुपात प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ एक महत्वपूर्ण नकारात्मक संबंध के संबंध को दर्शाता है।
ब्लूम, कैनिंग और मालने (1998)	1965-1990	1965-90 के दौरान एशिया में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और आर्थिक विकास के बीच संबंध	पूर्वी एशिया आय वृद्धि और प्रजनन क्षमता में कमी के "वर्चुअस स्पाइरल" (पुण्य) से लाभान्वित हुआ, जबकि दक्षिण एशिया कम-जनसंख्या-आय स्तर के जाल में फंसा रहा।
ब्रैंडर और डॉरिक (1994)	1960-1985	आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन क्षमता का प्रभाव	उच्च जन्म दर "पूँजी कमजोर पड़ने" के रूप में निवेश के प्रभाव के माध्यम से आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जन्म दर में गिरावट के कारण श्रम आपूर्ति या "निर्भरता" प्रभावों के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय पर मध्यमावधि में मजबूत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
बारो (1991)	1960-1985	मानव पूँजी और प्रति व्यक्ति जीडीपी के बीच संबंध	वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी की वृद्धि दर प्रारंभिक मानव पूँजी से सकारात्मक रूप से संबंधित है और वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी के प्रारंभिक स्तर से नकारात्मक रूप से संबंधित है।
जोंग-वोन यू, जिनील किम और जुंगजिन ली (2014)	1960-2013	प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी की वृद्धि पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन का प्रभाव; चालू खाता शेष; बचत; निवेश; सरकारी बजट संतुलन; और पैनल डेटासेट का उपयोग करके मुद्रास्फीति की दर जिसमें 30 ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है	जनसंख्या और बढ़ती उम्र का आकार, जैसा कि 65 और उससे अधिक के हिस्सों से पता लगता है, वास्तविक जीडीपी वृद्धि को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि चालू खाते, बचत, और निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, भले ही अल्प मात्रा में, जबकि बजट संतुलन पर इसका प्रभाव सकारात्मक और अत्यधिक है। बचत, निवेश, मुद्रास्फीति और बजट संतुलन पर बुजुर्गों की हिस्सेदारी का नकारात्मक प्रभाव अत्यधिक है।
हान (2019)	1991-2016	हांगकांग, सिंगापुर और मैनलैंड चीन में मुद्रास्फीति पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन का प्रभाव	युवा आबादी में वृद्धि स्फीतिकारी है, जबकि बढ़ती उम्र वाली आबादी में वृद्धि अवस्फीतिकारी है। मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को प्रभावित करके, जनसांख्यिकीय मुद्रास्फीति को सीधे या ब्याज दर चैनल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। आउटपुट गैप या वेज चैनल के माध्यम से इसका प्रभाव अनदेखा करने योग्य है।

लेखक	समयावधि	परखे गए मुद्दे	अध्ययन के नतीजे/निष्कर्ष
जुसेलियस एंड टाकाट्स (2018)	1870-2016	मुद्रास्फीति पर आयु संरचना का प्रभाव	अवधि के दौरान अलग-अलग पॉलिसी नियमों को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को समझाने में आयु संरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
बोबिका, लिस, निकल और सन (2017)	1975-2016	जनसांख्यिकीय परिवर्तन और मुद्रास्फीति के बीच संबंध	मुद्रास्फीति और यूरो क्षेत्र के साथ-साथ अमेरिका और जर्मनी में कुल आबादी में एक हिस्से के रूप में कामकाजी उम्र वाली आबादी में वृद्धि के बीच एक सकारात्मक दीर्घकालिक संबंध है।
ली, किम और पार्क (2016)	1995-2050	जनसांख्यिकीय बदलाव का सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य पर प्रभाव	जनसंख्या आयु संरचना राजकोषीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है क्योंकि वे सरकारी राजस्व और व्यय दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। एशिया की बढ़ती उम्र वाली आबादी (जापान, चीन और कोरिया गणराज्य) उसकी राजकोषीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
राकेश मोहन (2004)	1950-2050	एशिया में बढ़ती उम्र वाली आबादी की संभावित राजकोषीय चुनौतियां	पश्चिम में जो कुछ हो रहा है उसे देखने का फायदा एशियाई देशों को मिलता है और वे अत्यधिक सामाजिक कल्याणकारी राज्यों की गलतियों से बच सकते हैं। इन देशों को निजी कल्याणकारी प्रावधान से निकलकर जन कल्याणकारी प्रावधान को अपनाने में देरी करते हुए वित्त पोषित स्वास्थ्य और पेंशन योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है।
मैथ्यू हिगिंस (1998)	1950 - 1989	आयु वितरण, राष्ट्रीय बचत और चालू खाता शेष के बीच संबंध	बचत दरों में गिरावट से युवा और वृद्धावस्था दोनों के निर्भरता अनुपात में वृद्धि हुई। चालू खाता शेष पर अनुमानित जनसांख्यिकीय प्रभाव कई देशों के लिए पिछले तीन दशकों में जीडीपी के छह प्रतिशत से अधिक है।
मैक्सिम फौगे और मार्सेल मेरेट (1999)	1954-2082	वाइडिंग और मेरेट (1998) कम्प्यूटबल ओवरलैपिंग-जनरेशन (OLG) मॉडल में विस्तार करते हुए छोटे अर्थव्यवस्था वाले फ्रेमवर्क को इसकी परिधि में लाते हुए छः ओईसीडी देशों के चालू खाते पर बढ़ती उम्र वाली आबादी के संभावित प्रभाव	बढ़ती उम्र वाली आबादी का चालू खाता शेष पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जो एक देश में दूसरे के सापेक्ष बढ़ती उम्र की सीमा एवं विकास पर निर्भर करता है। अपेक्षाकृत रूप से तेज बढ़ती उम्र वाले देश घरेलू निवेश की मांग में गिरावट के चलते अपने चालू खाते शेष में सुधार का अनुभव करेंगे जो राष्ट्रीय बचत में कमी की अपेक्षा अधिक है। जनसंख्या की उम्र बढ़ने से बढ़ती उम्र की आबादी वाले देशों से उन देशों में अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह बढ़ सकता है जिनकी आबादी अपेक्षाकृत रूप से जवान है, जैसे कि नव औद्योगिक और विकासशील देश।
शेखर अय्यर और अशोक मोदी (2011)	1961-2001	भारतीय राज्यों में जनसंख्या की आयु संरचना में भिन्नता का उपयोग करके भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश से संभावित लाभ का आकार और परिस्थितियां	कामकाजी उम्र के अनुपात के स्तर और विकास दर दोनों ने भारत की आर्थिक वृद्धि पर एक बड़ा प्रभाव डाला है। अंतर-राज्य प्रवास, अंतः जनित समस्याओं और विभिन्न प्रकार के नियंत्रण चरों की शुरुआत को हिसाब में लेते हुए यह नतीजा मजबूत है।

लेखक	समयावधि	परखे गए मुद्दे	अध्ययन के नतीजे/निष्कर्ष
उत्सव कुमार (2010)	1971-2001	आर्थिक वृद्धि में जनसंख्या की बदलती आयु संरचना की भूमिका, जबकि राज्य-विशिष्ट चरों, जैसे कि संपूर्ण भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के स्तर के लिए नियंत्रण	भारत से राज्य-स्तरीय डेटा का उपयोग करके, पर्चा दर्शाता है कि जनसांख्यिकीय बदलाव की गति राज्यों में भिन्न होती है, और यह कि ये भिन्नताएं 2011-2026 की अवधि के दौरान बढ़ने की संभावनाएं हैं। बिमारू राज्यों में कुल आबादी में कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी निरंतर बढ़ने की संभावनाएं हैं। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश वरदान होगा या अभिशाप यह मुख्य रूप से बिमारू राज्यों द्वारा कामकाजी उम्र वाली आबादी में अत्यधिक बढ़ोत्तरी का फायदा उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है।
लादूसिंह और नारायण (2011)	2005-2070	नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स फ्रेमवर्क का उपयोग करके भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश की मात्रा का निर्धारण	यह पर्चा भारत में पहले और दूसरे दोनों जनसांख्यिकीय लाभांश के तहत आयु संरचना बदलाव के सकारात्मक समष्टि-आर्थिक निहितार्थ को मापता है। पहला जनसांख्यिकीय लाभांश (अधिक कामकाजी उम्र वाली आबादी के कारण) 1980-2035 में प्रभुत्व में रहा जबकि दूसरा जनसांख्यिकीय लाभांश (लंबी सेवानिवृत्ति को सहारा देने के लिए अधिक बचत के कारण) 2035 से। भारत के लिए कुल लाभांश 2070 तक स्थिर रह सकता है।

अनुबंध सारणी 2 : जनसांख्यिकीय चरों का सहसंबंध मैट्रिक्स

	जनसंख्या वृद्धि	आयु निर्भरता अनुपात	कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी	बुजुर्ग आबादी में वृद्धि
जनसंख्या वृद्धि	1 -----			
आयु निर्भरता अनुपात	0.995823*** (0.00)	1 -----		
कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी	-0.995328*** (0.00)	-0.999206*** (0.00)	1 -----	
बुजुर्ग आबादी में वृद्धि	-0.376661** (0.01)	-0.364754** (0.01)	0.369557** (0.01)	1 -----

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए हुए आंकड़े संबंधित पी-वैल्यू दर्शाते हैं ।

अनुबंध सारणी 3 : यूनिट रूट टेस्ट के नतीजे

मदें	चर	एडीएफ		एकीकरण क्रम
		बगैर रुझान	रुझान के साथ	
जनसांख्यिकीय/व्याख्यात्मक चर	जनसंख्या वृद्धि	-2.43**	-3.27*	I (0)
	आयु निर्भरता अनुपात	-1.93**	-3.58**	I (0)
	कामकाजी उम्र वाली आबादी की हिस्सेदारी	-1.86	-3.34*	I (0)
	बुजुर्ग आबादी में वृद्धि	1.04	-4.11***	I (0)
समष्टिआर्थिक/आश्रित चर	वास्तविक जीडीपी में वृद्धि	-6.30***	-7.81***	I (0)
	प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि	-5.52***	-7.85***	I (0)
	सीपीआई मुद्रास्फीति दर	-4.67***	-4.59***	I (0)
	जीडीपी अनुपात की तुलना में सामान्य सरकार का राजकोषीय घाटा	-3.18**	-2.93	I (0)
	जीडीपी अनुपात की तुलना में चालू खाता घाटा	-1.65*	-2.47	I (0)

टिप्पणी : ***, ** और * क्रमशः 1%, 5% एवं 10% स्तर पर पर्याप्त का द्योतक है।

2011-12 से 2017-18 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय भण्डार और प्रवाह*

वर्ष 2011-12 से 2017-18 की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय लेन-देन के क्षेत्रवार और मात्रावार पैटर्न में बदलाव स्पष्ट दिखने लगे थे। इस अवधि में भा.रि.बैंक की वित्तीय बैलेंस शीट का आकार कम हुआ, जो वित्तीय विकास की प्रक्रिया का परिचायक था। अन्य डिपॉजिटरी कॉरपोरेशन (ओडीसी) सेक्टर के तुलन-पत्र के आकार में वर्ष 2013-14 से संकुचन जारी है जिससे यह पता चलता है कि लोगों के प्राथमिकता में बदलाव हो रहा है और अब वे जमा से हटकर अन्य प्रतिस्पर्धी वित्तीय लिखतों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस अवधि में, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के गैर-वित्तीय निगमों की निवल उधारी में गिरावट आयी जो इस बात को इंगित करता है कि वित्तीय निवेश की तुलना में आंतरिक बचत को तरजीह दी जा रही है। हाउसहोल्ड क्षेत्र, जो अभी भी निधि का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, वह भी एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक परिवर्तन से गुजर रहा है। मुद्रा और जमा – जो ऐतिहासिक रूप से सबसे पसंदीदा वित्तीय लिखत रहे हैं, उनका महत्व भी इस दौरान घटा है और उनके स्थान पर इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बीमा और भविष्य निधि जैसे लिखत लोकप्रिय हुए हैं।

परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि-प्रवाह (एफओएफ) लेखा का संकलन सामान्यतया राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए, 2008) के अनुसार करता है। इस लेख में जिन संस्थागत क्षेत्रों को शामिल किया गया है, वे हैं: (i) वित्तीय निगम (एफसी); (ii) गैर-वित्तीय निगम (एनएफसी), सार्वजनिक और निजी; (iii) सामान्य सरकार (जीजी) जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शामिल हैं; (iv) हाउसहोल्ड और हाउसहोल्ड्स की सेवा में कार्यरत अलाभकारी संस्थाएँ (एचएच)¹; और (v)

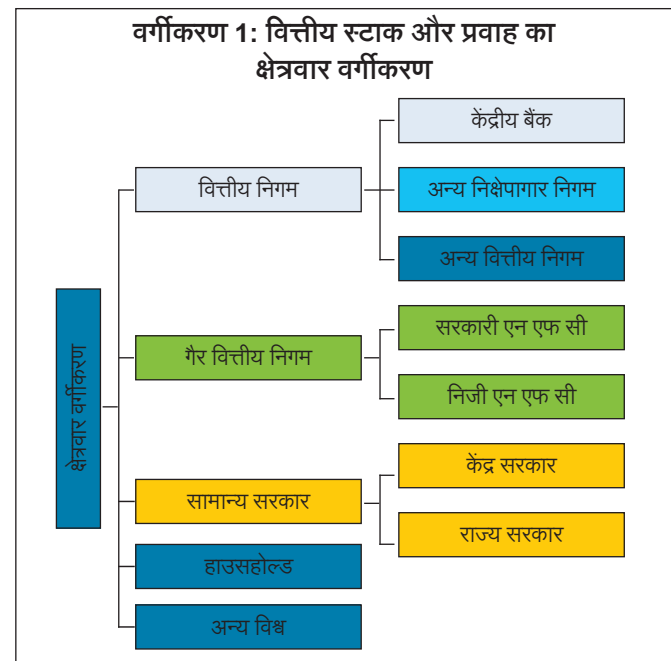
* भारतीय रिज़र्व बैंक, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राष्ट्रीय लेखा विश्लेषण प्रभाग में कार्यरत अनुपम प्रकाश, अवधेश कुमार शुक्ल, आनंद प्रकाश एक्का, कुणाल प्रियदर्शी और चैताली भौमिक। सुश्री वंदना टी आर और श्रीमती शालिनी जैन ने भी इसमें अपना योगदान दिया है।

वित्तीय स्टॉक और प्रवाह से संबंधित विस्तृत विवरण संख्या 1 से 9 बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर अलग से जारी किए गए हैं।

¹ हाउसहोल्ड्स के अंतर्गत ऐसी अलाभकारी संस्थाएँ (एनपीआईएसएच) भी शामिल हैं, जो घरेलू सेवाएँ देती हैं जैसे, धार्मिक सोसाइटी, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन से जुड़े स्पोर्ट्स क्लब, राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन आदि। आंकड़ों के अभाव के कारण इन संस्थाओं को हाउसहोल्ड्स क्षेत्र के साथ जोड़कर देखा जाता है।

शेष विश्व (आरओडब्ल्यू) (प्रदर्शनी 1)। इस प्रकार के लेखा में विभिन्न क्षेत्रों को किए जाने वाले अंतरणों के लिए वित्तीय लिखत शामिल होते हैं, किस-से-किस-को (एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू) आधार पर निधियों के स्रोत से निधियों के उपयोग तक, जिनके तहत मुद्रा, जमा, कर्ज प्रतिभूतियाँ, ऋण और उधार, इक्विटी, निवेश फंड (जैसे म्यूचुअल फण्ड), बीमा, पेंशन और भविष्य निधि, मौद्रिक स्वर्ण और अन्य लेखा (व्यापारिक कर्ज सहित) आते हैं।

एक नई शुरुआत के रूप में इस लेख में, निधियों का प्रवाह जानने के लिए वित्तीय लेखा के मानक प्रवाह वाले पहलू, अर्थात्, वित्तीय आस्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के साथ-साथ सेक्टर-वार बकाया का सहारा लिया गया है² वर्ष 2017-18 को इस अध्ययन की अवधि का अंतिम वर्ष निर्धारित किया गया क्योंकि कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग मानकों को भारतीय सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (आई-जीएपी) से भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एस)³ में बदले जाने के परिणामस्वरूप उक्त वर्ष के लिए निजी गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट सेक्टर के आंकड़े काफी देर से मई 2019 में प्राप्त हो सके।



² पिछले प्रकाशित लेख में 2015-16 तक के आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे (भारि. बैंक, 2017)।

³ गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2017-18, 06 मई 2019 को जारी किया गया; और गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2017-18, 31 मई 2019 को जारी किया गया।

भारत ने 2015 में लॉन्च किए गए जी-20 डेटा गैप्स इनिशिएटिव (डीजीआई-2) के दूसरे चरण को मान्यता दे दी है, जो कि क्षेत्रवार लेखा की बेहतर कवरेज, समयबद्धता, और आवधिकता से संबंधित है।⁴ तदनुसार, वित्तीय क्षेत्र सांख्यिकी समिति (सीएफएसएस)⁵ ने सिफारिश की है कि (i) उच्च आवृत्ति वाले डेटा - त्रैमासिक और साथ ही साथ वार्षिक- जारी किए जाएं और साथ ही इन्हें जारी करने के अंतराल को वर्तमान 15 महीने से अधिक के समय से घटाकर 9 महीने किया जाए; (ii) नए चरों को इसमें कवर किया जाए; और (iii) नए पहलुओं जैसे, प्रवाह बनाम स्टॉक तथा लेनदेन बनाम मूल्यन को इसमें शामिल किया जाए।

यह लेख 2021 तक क्षेत्रीय खातों पर डीआईजी-2 लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि, बीमा और भविष्य निधि को अन्य वित्तीय निगम (ओएफसी) क्षेत्र के भीतर एक उपक्षेत्र के रूप में अलग से दर्शाया गया है। म्यूचुअल फंडों, बीमा, पेंशन और भविष्य निधि, हाउसहोल्ड्स और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए वित्तीय प्रवाह को दो भागों- लेनदेन और मूल्यनगत परिवर्तनों में बांटकर दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब मनी मार्केट और नॉन-मनी मार्केट म्यूचुअल फंडों को भी अलग-अलग करके दिखाया जाता है। शेष विश्व क्षेत्र की बात करें तो, भुगतान संतुलन (बीओपी) डेटा और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) दोनों दर्शाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित वित्तीय स्टॉक और प्रवाह डेटा तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था के खातों के अनुक्रम (एसओए) का मिलान करने के प्रयास भी किए गए हैं।⁶

⁴ सिफारिश सं. 8: 'जी-20 अर्थव्यवस्थाओं को प्रत्येक तिमाही और वार्षिक आधार पर, आंकड़ों के क्षेत्रवार प्रवाह तथा तुलन-पत्र के आंकड़े समेकित करते हुए इन्हें प्रसारित करना है। ये आंकड़े अंतरराष्ट्रीय सहमति से तैयार टेम्पलेट में देने होंगे और इनमें अन्य (गैर-बैंक) वित्तीय निगम क्षेत्र के आंकड़े भी शामिल होंगे, और तुलन-पत्र विश्लेषण के समर्थन में लेनदेनों तथा स्टॉक्स दोनों के लिए किससे-किसको ढाँचा विकसित करना होगा।

⁵ इस लेख के लेखक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) (मई 2018) द्वारा गठित वित्तीय क्षेत्र सांख्यिकी समिति (अध्यक्ष प्रो. रवींद्र एच. ढोलकिया) की सिफारिशों से लाभान्वित हुए हैं। सीएफएसएस से लिए गए प्रमुख संदर्भों में शामिल थे- 'एफओएफ आंकड़ों के संग्रहण और उनकी संसाधन की समीक्षा करना...' और 'सुधार के ऐसे उपाय सुझाना जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों।

⁶ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मॉस्पी) ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) का विलय करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) बनाने का निर्णय लिया जो 23 मई 2019 से प्रभावी हुआ।

शेष आलेख को सात भागों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। दूसरे भाग में क्षेत्रीय वित्तीय संसाधन अंतराल का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। भाग III क्षेत्रवार वित्तीय रुझान प्रस्तुत करता है। लिखत-वार वित्तीय प्रवाह पर एक संक्षिप्त चर्चा भाग IV के अंतर्गत की गयी है। खंड V में वित्तीय विकास के चुनिंदा संकेतकों का विश्लेषण किया गया है। वित्तीय खातों के आवेदन और वित्तीय प्रवाहों के नेटवर्क का विश्लेषण भाग VI में प्रस्तुत किया गया है। भाग VII कुछ नीतिगत दृष्टिकोणों के साथ लेख का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

II. क्षेत्रीय वित्तीय संसाधन अंतराल

वर्ष 2011-12 से 2017-18 की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में हाउसहोल्ड्स, वित्तीय निगमों और निजी गैर-वित्तीय निगमों (पीवीएनएफसी) की निवल मालियत⁷ धनात्मक रही, जबकि सामान्य सरकार और सार्वजनिक गैर-वित्तीय निगमों (पीयूएनएफसी) की निवल मालियत ऋणात्मक रही। हाउसहोल्ड्स (एचएच) की निवल मालियत औसतन निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) के आसपास रही (सारणी 1)।

वित्तीय आस्तियों के निवल अधिग्रहण में से देयताओं में हुई निवल वृद्धि को घटाकर मापा जाने वाला समग्र वित्तीय संसाधन शेष वर्ष 2017-18 में लगातार तीसरे वर्ष अधिशेष की स्थिति में रहा और साथ ही, सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के एनएफसी की निवल उधारियों में कमी⁸ आयी जिससे ये अपने निवेशों के वित्तपोषण के लिए आंतरिक बचतों का सहारा लेती दिखायी पड़ीं। दूसरी ओर, जीजी सेक्टर के संसाधन अंतराल में वर्ष 2015-16 और 2016-17 में सुधार दिखायी दिया परंतु 2017-18 में यह पुनः अपने औसत स्तर पर आ गया। एचएच द्वारा दिए गए निवल ऋण में विगत वर्षों में रही गिरावट के बाद वर्ष 2015-16 में तीव्र गति से जो मजबूती आयी थी, उस पर 2016-17 में विमुद्रीकरण से विपरीत प्रभाव पड़ा और 2017-18 में इसमें और गिरावट आयी (सारणी 2)।

⁷ निवल मूल्य की गणना बकाया आस्तियों और देयताओं (शेयरधारकों की इक्विटी को छोड़कर) के अंतर के रूप में की जाती है।

⁸ राष्ट्रीय लेखा आंकड़े भी गैर-वित्तीय निगमों द्वारा लिए गए निवल उधार में गिरावट का समर्थन करते हैं जो निजी गैर-वित्तीय निगमों द्वारा उधार लेने की आवश्यकता में आयी कमी का परिचायक है।

सारणी 1: क्षेत्रवार वित्तीय निवल मालियत
(वर्तमान बाजार मूल्यों पर एनएनआई का प्रतिशत)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आस्तियां							
1. वित्तीय निगम	224	227	229	231	232	231	234
2. गैर वित्तीय निगम	133	125	125	125	119	113	108
क. सरकारी गैर वित्तीय निगम	18	17	16	15	12	12	12
ख. निजी गैर वित्तीय निगम	115	108	109	109	107	101	96
3. सामान्य सरकार	31	30	30	28	30	29	28
4. हाउसहोल्ड क्षेत्र	137	133	131	133	133	132	134
5. शेष विश्व	46	48	50	51	50	46	45
देयताएँ							
1. वित्तीय निगम	191	193	194	196	197	196	198
2. गैर वित्तीय निगम	112	107	108	109	105	99	95
क. सरकारी गैर वित्तीय निगम	20	20	21	22	21	22	23
ख. निजी गैर वित्तीय निगम	92	86	86	87	85	77	71
3. सामान्य सरकार	78	78	77	77	79	78	78
4. हाउसहोल्ड क्षेत्र	32	32	32	32	32	32	34
5. शेष विश्व	23	22	24	24	25	22	23
वित्तीय निवल मालियत							
1. वित्तीय निगम	33	35	35	35	35	35	37
2. गैर वित्तीय निगम	21	19	17	16	13	14	14
क. सरकारी गैर वित्तीय निगम	-2	-3	-5	-7	-9	-10	-11
ख. निजी गैर वित्तीय निगम	23	22	22	22	22	24	24
3. सामान्य सरकार	-47	-47	-47	-48	-49	-49	-50
4. हाउसहोल्ड क्षेत्र	105	101	99	100	100	100	100
5. शेष विश्व	23	26	26	26	25	23	23

III. क्षेत्रवार वित्तीय रुझान

III.1 वित्तीय निगम

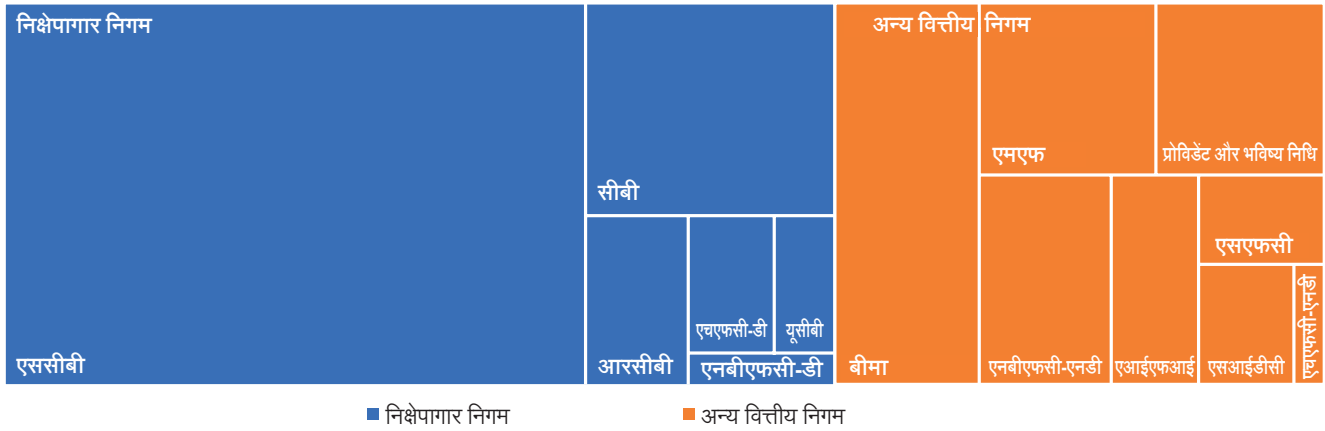
वित्तीय प्रणाली में निधि प्रवाह को वित्तीय अधिशेष की स्थिति वाली इकाइयों से वित्तीय अभाव वाली इकाइयों की ओर ले जाना संभव बनाने में वित्तीय निगम प्रभावी भूमिका निभाते

हैं। केंद्रीय बैंक एफसी के ही घटक होते हैं, लेकिन इस मायने में वे अलग होते हैं कि मौद्रिक नीति तैयार करने और अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करते हुए वे वित्तीय प्रणाली के प्रमुख पहलुओं पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरी ओर, अन्य डिपॉजिटरी कॉर्पोरेशन (ओडीसी) जिनमें

सारणी 2: क्षेत्रवार वित्तीय संसाधन का शेष
(वर्तमान बाजार मूल्यों पर एनएनआई का प्रतिशत)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1. वित्तीय निगम	3.0	2.6	2.5	1.8	2.3	1.6
2. गैर वित्तीय निगम	-8.0	-6.1	-5.7	-5.4	-3.3	-2.9
क. सरकारी गैर वित्तीय निगम	-2.8	-2.6	-2.8	-3.1	-2.4	-2.1
ख. निजी गैर वित्तीय निगम	-5.3	-3.5	-2.9	-2.3	-0.9	-0.8
3. सामान्य सरकार	-5.7	-5.8	-5.6	-5.4	-5.1	-5.5
4. हाउसहोल्ड क्षेत्र	8.7	8.5	8.3	9.5	8.5	7.8
5. कुल (1+2+3+4)	-2.1	-0.8	-0.5	0.5	2.3	1.0

चार्ट 1: वित्तीय निगम का संगठन (2017-18)



एस सी बी – अनुसूचित वाणिज्य बैंक, सीबी-केंद्रीय बैंक, आर सी बी – ग्रामीण सहकारी बैंक, एच एफ सी-डी-जमाराशियां लेनेवाली आवास वित्त कंपनियाँ, यूसीबी – शहरी सहकारी बैंक एन बी एफ सी-डी-जमाराशियां लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पी एफ-पेंशन निधि, एमएफ-म्यूच्युअल फंड, ए आई एफ आई – अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, एस एफ सी – राज्य वित्तीय निगम, एस आई डी सी-राज्य औद्योगिक वित्तीय निगम, एच एफ सी एन डी – जमाराशियां न लेनेवाली आवास वित्त कंपनियाँ, एन बी एफ सी-एन डी – जमाराशियां न लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

केंद्रीय बैंक को छोड़कर अन्य डिपॉजिटरी संस्थान और वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करने वाले अन्य वित्तीय निगम (ओएफसी) शामिल हैं⁹ अन्य इकाइयों से जमाराशि जुटाने वाले ओडीसी, भारत जैसी बैंक आधारित अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाते हैं (चार्ट 1)। इनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटियाँ, जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और जमाराशि स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियाँ शामिल हैं।

III.1.1 केंद्रीय बैंक

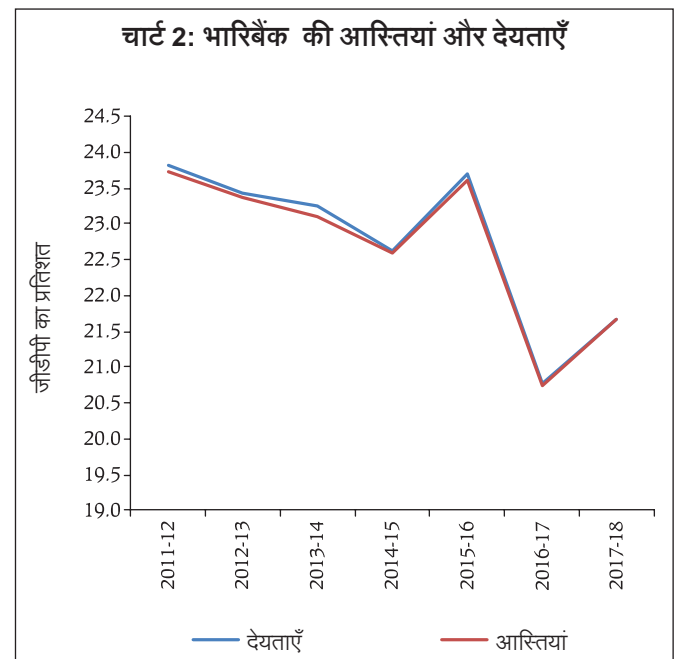
भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय तुलन पत्र का आकार 2011-12 से 2017-18 की अवधि में सिकुड़ गया जो वित्तीय विकास की प्रक्रिया का परिचायक है¹⁰ (चार्ट 2)। वर्ष 2016-17 के दौरान विमुद्रीकरण के कारण करेंसी के रूप में इसकी देयताओं में कमी आयी जिससे इसके तुलन-पत्र के आकार में तीव्र कमी आयी।

⁹ अन्य वित्तीय निगमों (ओएफसी) में प्रमुख इकाइयां इस प्रकार हैं, म्यूच्युअल फंड (एमएफ), भविष्य निधि एवं पेंशन फंड, जमाराशि नहीं लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी-एनडी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई), राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसी), राज्य वित्त निगम (एसएफसी) एवं जमाराशि नहीं लेने वाली आवास वित्त कंपनियाँ, जो अपने संगत शेयरों के क्रम में हैं।

¹⁰ सामान्य तौर पर, केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र के आकार और वित्तीय विकास के स्तर के बीच संबंध होता है (जाधव एवं अन्य, 2003)।

अर्थव्यवस्था में मुद्रा के जारीकर्ता के रूप में केंद्रीय बैंक की मुख्य देयता मुद्रा होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई लगभग 95 प्रतिशत मुद्रा हाउसहोल्ड्स के पास रहती है। केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण देयता जमाराशियाँ हैं जिनका अधिकांश हिस्सा ओडीसी क्षेत्र के पास होता है। लेकिन 2016-17 में, देयताओं की तरफ मुद्रा और जमाराशियों का संघटन बदल गया। मुद्रा के रूप में निधि प्रवाह नकारात्मक

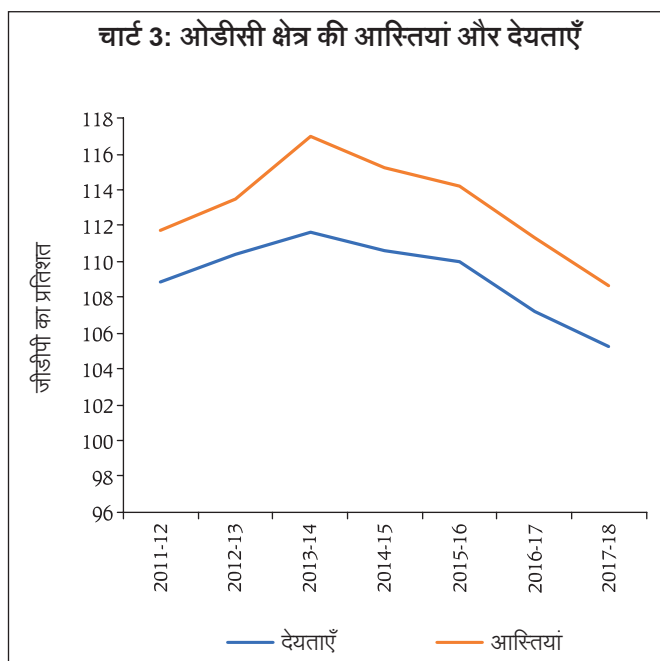
चार्ट 2: भारिबैंक की आस्तियाँ और देयताएँ



हो गया विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वापस आए, जिसमें बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जमा हुए नोट भी शामिल थे; जमाराशियों के रूप में देयताएं बढ़ीं क्योंकि ओडीसी ने अपनी अधिशेष चलनिधि को रिज़र्व बैंक के पास जमा किया। इससे भारतीय रिज़र्व बैंक की देयताओं का संघटन बदल गया और वे बिना ब्याज वाली मुद्रा देयताओं से बदल कर ब्याज वाली जमाराशियों में बदल गयीं। वर्ष 2017-18 में जैसे-जैसे पुनर्मुद्राकरण की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा मुद्रा फिर से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देयता वाली अपनी पुरानी स्थिति में आ गयी। आस्तियों की बात करें तो, आरओडब्लू द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां प्रमुख घटक हुआ करती हैं, इसके बाद ओडीसी सेक्टर को दिए गए ऋणों का स्थान आता है। वर्ष 2016-17 के दौरान इस संघटन में भी कुछ बदलाव आया क्योंकि विमुद्राकरण के बाद ओडीसी और ओएफसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक में अपने बकाया ऋण को चुकाने के लिए अधिशेष चलनिधि का उपयोग किया।

III.1.2 अन्य निक्षेपागार निगम

अन्य डिपॉजिटरी कॉरपोरेशन (ओडीसी) सेक्टर के तुलन-पत्र में 2013-14 से संकुचन देखा जा रहा है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि लोगों का रुझान जमा से हटकर अन्य प्रतिस्पर्धी वित्तीय साधनों जैसे म्यूचुअल फंड और छोटी बचतों की ओर हो रहा है (चार्ट 3)। बैंकिंग प्रणाली ने यह जान लिया है कि जमा संग्रहण में आय ही सबसे महत्वपूर्ण कारक



है (भा.रि.बैंक, 2019)। जमा के रूप में घरेलू वित्तीय बचत में लगातार आयी गिरावट से यह बात संपुष्ट होती है।¹¹ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वित्तीय साक्षरता के प्रसार के कारण भी लोग जमा जैसे पारंपरिक साधनों से दूर जा रहे होंगे (भा.रि.बैंक, 2016)। ओडीसी क्षेत्र के तुलन-पत्र में सर्वव्यापी संकुचन विमुद्राकरण के दौरान भी बना रहा, बैंकिंग प्रणाली में एसबीएन की आवक को i) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर(बी) खाते में मौजूद जमाराशि के मोचन; (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक को देय ऋणों की अदायगी (भा.रि.बैंक, 2017) से संतुलित कर लिया गया।

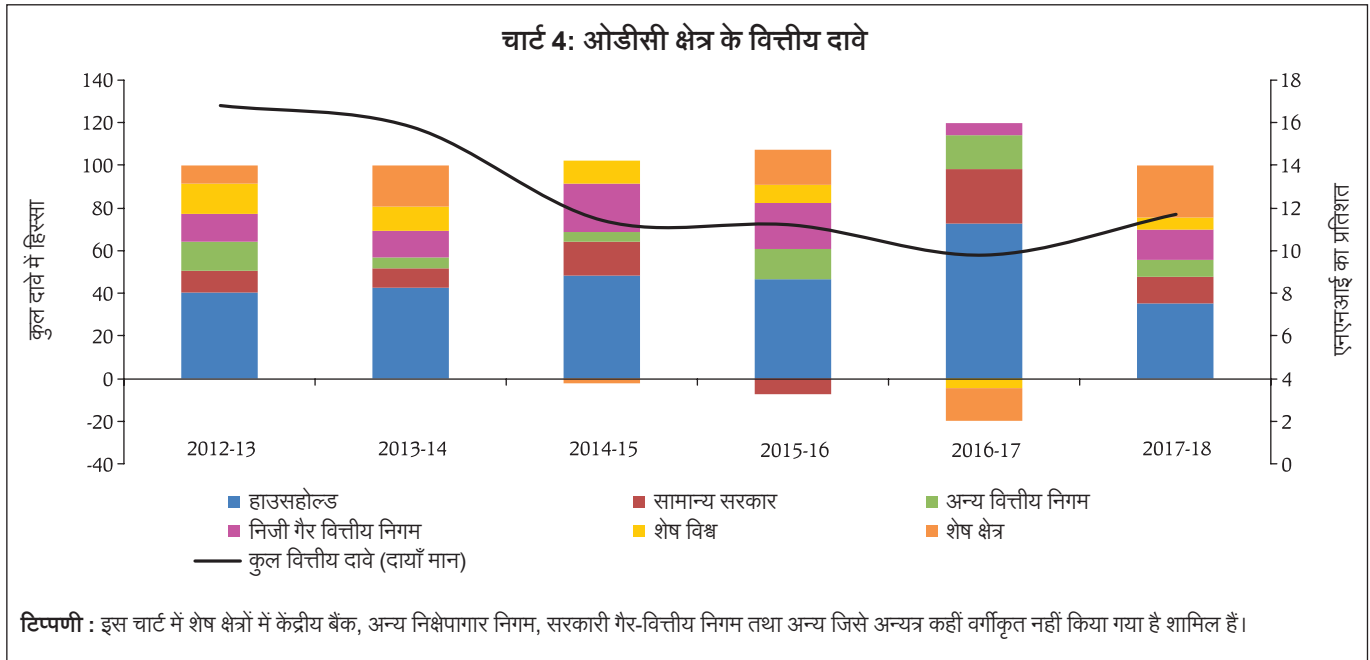
ओडीसी द्वारा देयताएं अर्जित करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखत जमा-संग्रहण, मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्र का जमा होता है जिसके बाद ऋणों का स्थान आता है, जिन्हें ज्यादातर ओएफसी से प्राप्त किया जाता है। आस्तियों की बात करें, तो गैर-वित्तीय निगमों और घरेलू क्षेत्र को दिए गए ऋण सबसे महत्वपूर्ण लिखत होते हैं और इनके बाद ऋण प्रतिभूतियों, मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का स्थान आता है।

विमुद्राकरण से ओडीसी के तुलन-पत्र का संघटन प्रभावित हुआ। इससे जमाराशियों के रूप में ओडीसी की बकाया देनदारियां बढ़ीं और ऋणों के रूप में उनकी आस्तियाँ घटीं (चार्ट 4 और 5)। ओडीसी क्षेत्र में आयी विशाल नकदी का उपयोग सरकारी ऋण प्रतिभूतियाँ अर्जित करने, अंतः-क्षेत्रीय जमा और 2016-17 के दौरान केंद्रीय बैंक में जमा प्राप्त करने के लिए किया गया। वर्ष 2017-18 में पुनः मुद्राकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही, यह नकदी प्रवाह विपरीत दिशा में होने लगा - जमा ऋणात्मक हो गया, जबकि ऋणों में वृद्धि होने लगी।

समग्र रूप से इस क्षेत्र की निवल वित्तीय मालियत धनात्मक बनी हुई थी, हालांकि, वर्ष 2013-14 से इसमें लगातार कमी होती रही है, जिसका मुख्य कारण रही है बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में हुई वृद्धि।

ओडीसी क्षेत्र के भीतर, वित्तीय मध्यस्थता की भूमिका में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) और जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) एक दूसरे की पूरक के रूप में दिखायी पड़ती हैं। इस अध्ययन की अवधि में भारत में व्यवसायगत एससीबी के तुलन-पत्र के आकार

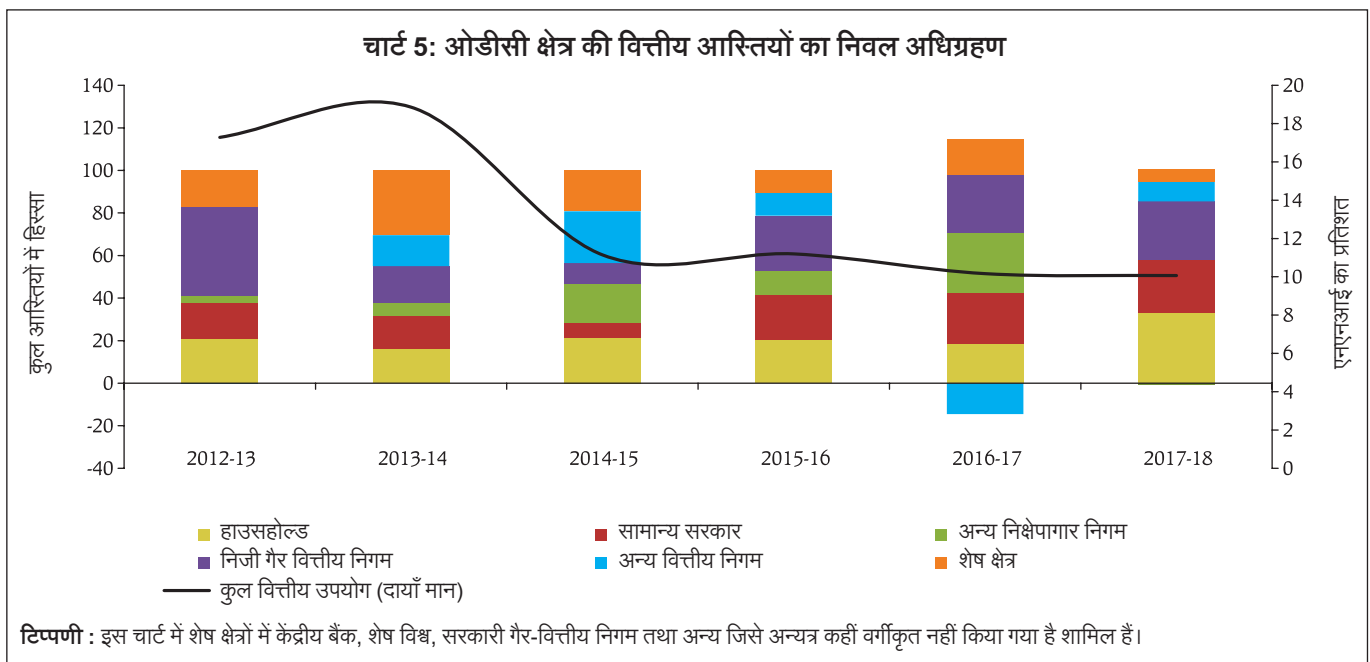
¹¹ वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान घरेलू बचत का कुल बचत में लगभग 61 प्रतिशत हिस्सा था।



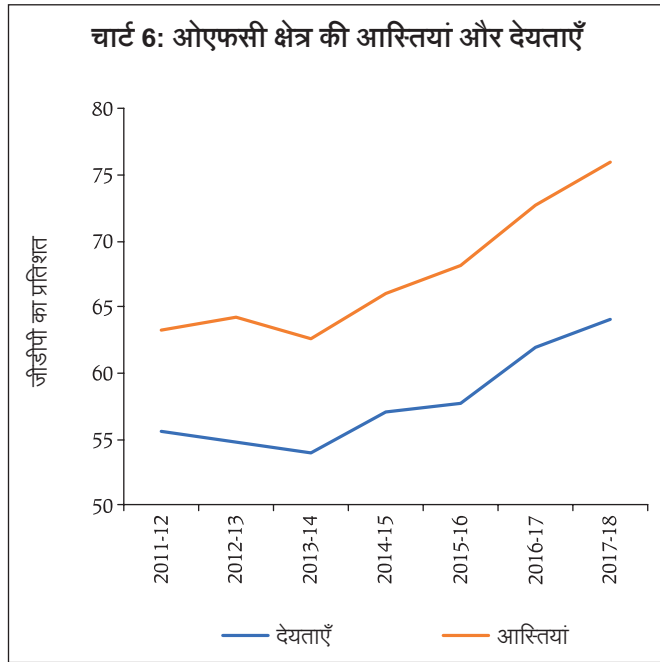
में वृद्धि की गति धीरे-धीरे कम होती रही है क्योंकि वे दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि, एनबीएफसी के समेकित तुलन-पत्र का आकार तेजी से बढ़ा है क्योंकि उनमें एनपीए का स्तर भी बैंकों की तुलना में कम रहा है और उनका पूंजी-बफर भी बेहतर रहा है (भा.रि.बैंक, 2018)।¹²

III.1.3 अन्य वित्तीय निगम

अन्य वित्तीय निगम (ओएफसी) क्षेत्र का आकार ओडीसी क्षेत्र की तुलना में भारत में बहुत छोटा रहा है, परंतु बैंक जमा जैसे पारंपरिक लिखतों की तुलना में बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन और भविष्य निधि जैसे उत्पादों के प्रति हाउसहोल्ड्स के बढ़ते



¹² 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं', भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2018।



रूझान के कारण वर्ष 2013-14 से इस क्षेत्र का विस्तार हो रहा है (चार्ट 6)।

ओएफसी की देयताएं मुख्य रूप से बीमा, पेंशन और भविष्य निधि के रूप में होती हैं, इनके बाद म्यूचुअल फंड यूनिटों और कर्ज प्रतिभूतियों का स्थान आता है (चार्ट 7)। विमुद्रीकरण के उपरांत, ओएफसी ने सरकारी और कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियों के साथ-साथ इक्विटी और म्यूचुअल फंड में अपना निवेश बढ़ा

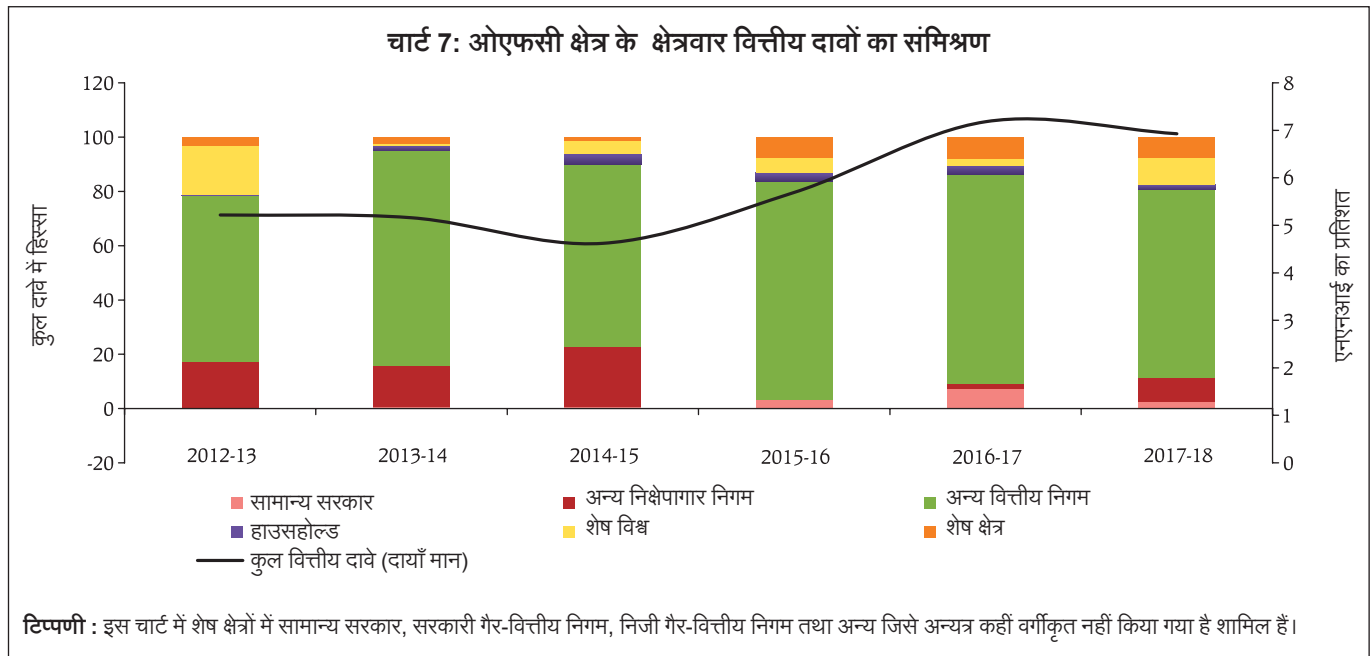
दिया है। ओएफसी की आस्तियाँ मुख्य रूप से सरकारी कर्ज प्रतिभूतियाँ होती हैं, जिनके बाद एनएफसी को दिए गए ऋणों और अपने ही क्षेत्र में उनकी इक्विटी होल्डिंग्स का स्थान आता है।

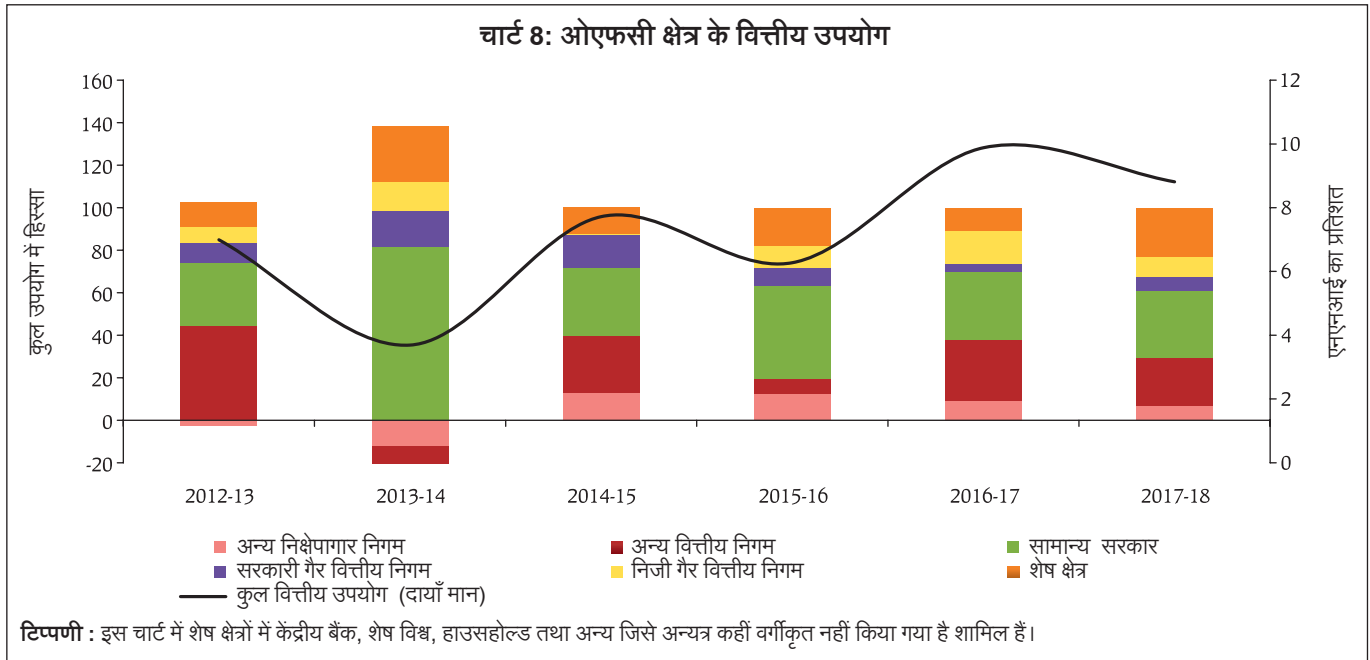
जहां तक ओएफसी वित्तीय देनदारियों के क्षेत्रीय संघटन का संबंध है, उनके द्वारा लिए गए अंतःक्षेत्रीय उधार की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है और उसके बाद ओडीसी से आए निधि प्रवाह का स्थान होता है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भारतीय बैंकों की आस्ति-गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) किए जाने के फलस्वरूप ओडीसी से आने वाले संसाधनों के प्रवाह में तेजी से कमी आयी परंतु 2017-18 में जैसे-जैसे बैंकों का एनपीए स्तर घटने लगा, वैसे-वैसे इसमें फिर से सुधार हुआ (चार्ट 7)।

कर्ज प्रतिभूतियों के रूप में आस्तियों के अधिग्रहण के कारण वर्ष 2014-15 के बाद से ओएफसी की निवल वित्तीय आस्तियाँ लगातार बढ़ रही हैं (चार्ट 8)। समग्र निधि-प्रवाह को दो भागों- लेनदेन तथा मूल्यन में हुए परिवर्तन- में बांटने से पता चलता है कि इस अध्ययन की अवधि के दौरान ओएफसी क्षेत्र की आस्तियों में आए लगभग एक तिहाई परिवर्तन का कारण आस्तियों की कीमतों का बढ़ जाना था।

III.2 गैर-वित्तीय निगम

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में गैर-वित्तीय निगमों की बड़ी भागीदारी होती है, और ये उत्पादक आस्तियों में





निवेश से जुड़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थव्यवस्था में मौजूद हाउसहोल्ड्स तथा वित्तीय निगम जैसे अधिशेष वाले क्षेत्रों से उधार लेते हैं।

स्वामित्व के लिहाज से, यह क्षेत्र दो में विभाजित है- सार्वजनिक स्वामित्व वाले गैर-वित्तीय निगमों (पीयूएनएफसी)¹³ (ऐसी संस्थाएँ जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी सरकार की होती है) और निजी गैर-वित्तीय निगमों (पीवीएनएफसी) जो संख्या और तुलन-पत्र के आकार दोनों दृष्टियों से बड़े हैं।

पीवीएनएफसी की बात करें तो, इनमें बाहरी वित्त का सबसे बड़ी स्रोत इक्विटी होती है, जिनके बाद ऋणों और उधारियों का स्थान आता है। पीवीएनएफसी की एक दूसरे में शेयरधारिताएं सबसे ज्यादा हैं। इसके विपरीत, सार्वजनिक एनएफसी बाहरी वित्त के लिए सबसे अधिक ऋणों और उधारियों को अधिक पसंद करती हैं।

पीवीएनएफसी की निवल मालियत की स्थिति घनात्मक है क्योंकि उनके तुलन-पत्र का बड़ा हिस्सा शेयरधारकों की निधि होती है। यह घटते निवेश और बढ़ती कॉर्पोरेट आय के कारण

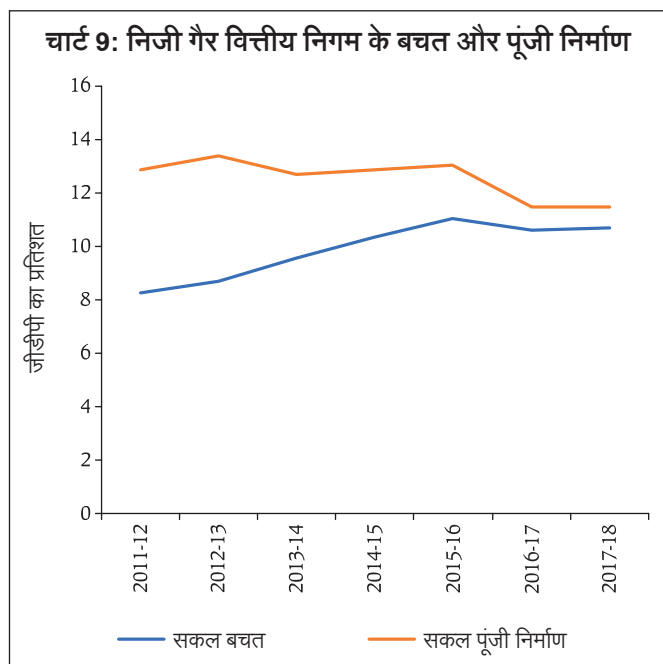
¹³ पीयूएनएफसी में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम, ऊर्जा एवं पत्तन न्यास शामिल हैं। (आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों के आंकड़ों को शामिल नहीं किया जा सका)।

बढ़ रहा है। दूसरी ओर, पीयूएनएफसी की निवल मालियत ऋणात्मक रही है और इसकी स्थिति समय के साथ और भी खराब होती जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार के घाटे में चल रहे उद्यमों (सीपीएसई) की संख्या बहुत बड़ी हो गयी है और सरकार बहुत तेजी से विनिवेश कर रही है।

एनएफसी और एफसी के बीच अंतर-संबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी क्षेत्रों से आने वाली निधियों में मध्यस्थता की भूमिका वित्तीय निगम ही निभाते हैं। बाकी विश्व से भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (इक्विटी और कर्ज प्रतिभूति) के रूप में आने वाला निवेश भी काफी बड़ा होता है।

पीवीएनएफसी का वित्तीय संसाधन अंतराल 2012-13 से 2017-18 के दौरान एनएनआई के 5.3 प्रतिशत के घाटे से घटकर 1.5 प्रतिशत हो गया। निवेश की मांग अपेक्षाकृत कम रहने, बचत में वृद्धि होने और मुद्रास्फीति के कम रहने से पीवीएनएफसी को लाभ हुआ है जैसा कि राष्ट्रीय लेखा में पीवीएनएफसी के बचत-निवेश अंतःसंबंध से देखा जा सकता है (चार्ट 9)।

वर्ष 2016-17 में पीवीएनएफसी की कुल देयताओं में उनके के दावों का हिस्सा लगभग दोगुना हो गया (चार्ट 10)। शेष विश्व क्षेत्र से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ने भी



हाल के वर्षों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ओएफसी की भूमिका भी काफी हद तक बढ़ी है जबकि ओडीसी से आने वाला निधि प्रवाह धीरे-धीरे कम हुआ है।

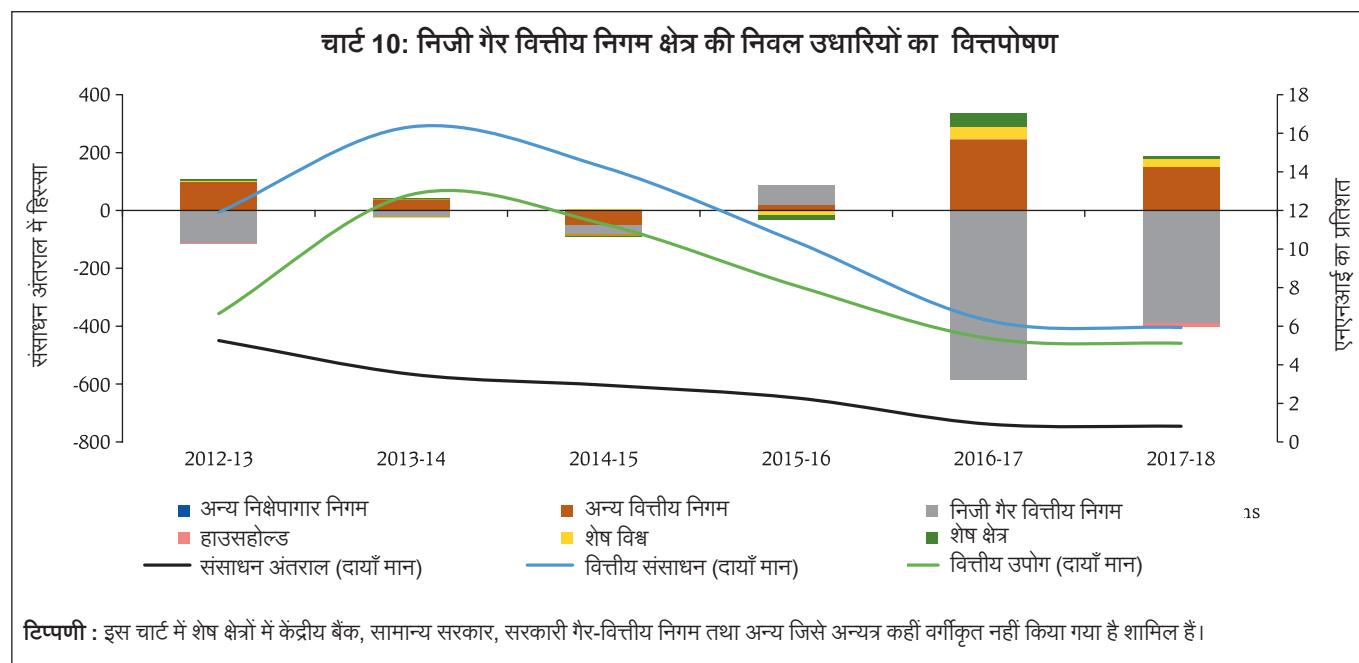
पीयूएनएफसी की बात करें तो, वर्ष 2012-13 से 2017-18 के बीच संसाधन अंतराल स्थिर बना रहा है(चार्ट 11)। अपेक्षाकृत अलाभप्रदता वाले वर्ष 2015-16 की तुलना में 2016-17 और 2017-18 में उनके शेष में कुछ सुधार आया।

III.3 सामान्य सरकार

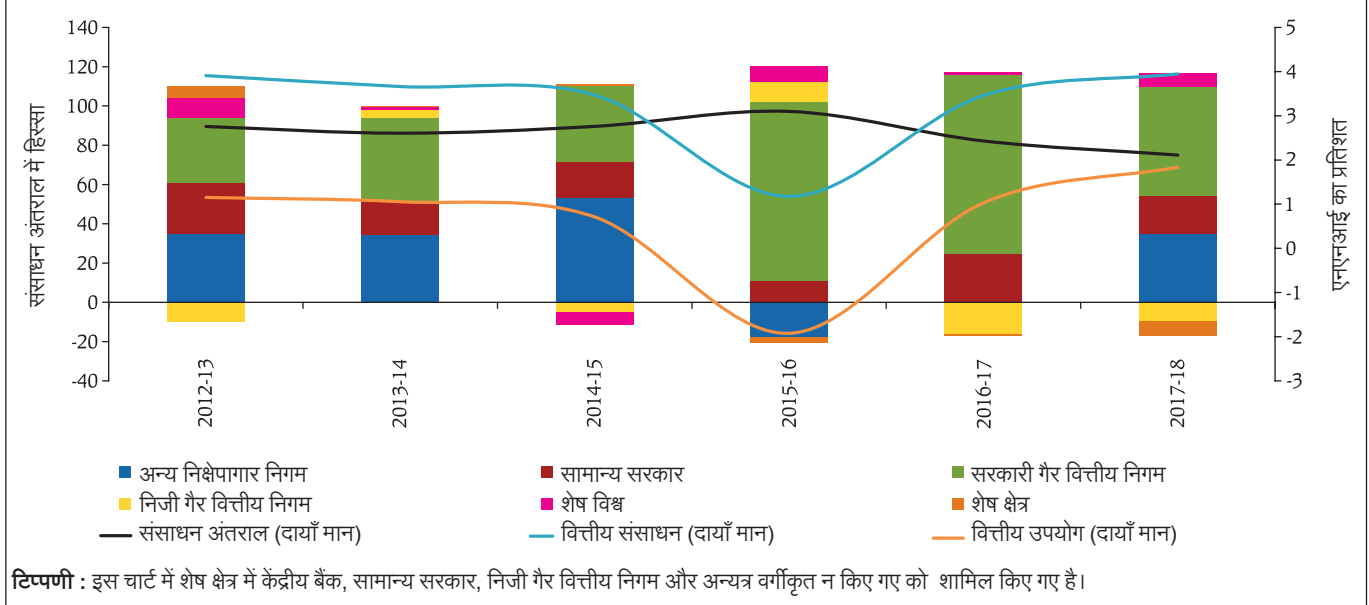
भारत में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों घाटे में चलती हैं, और इस प्रकार वे अर्थव्यवस्था में निवल उधारकर्ता बनी रहती हैं। आंकड़ों के अभाव में, स्थानीय निकायों के लिए आंकड़े संकलित नहीं किए जाते जबकि उन्हें तीसरी पंक्ति की शासन व्यवस्था माना जाता है।

परिसंपत्तियों के पक्ष में, इक्विटी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो निगमों में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों (चार्ट 12) में केंद्र सरकार की भागीदारी को दर्शाता है। इसके बाद ओडीसी के पास जमा धनराशि का स्थान आता है- जिसे राज्य सरकारों के मामले में अधिक स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है जिन्होंने बड़े नकदी शेष इकट्ठा कर लिए हैं जो कि उनके खराब नकदी प्रबंधन का परिचायक है।

जीजी क्षेत्र का वित्तीय संसाधन अंतराल 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान स्थिर रहा, और 2017-18 के दौरान थोड़ा बढ़ा। इस अंतराल का वित्तपोषण मुख्य रूप से ओएफसी और ओडीसी द्वारा किया गया था। हाउसहोल्ड्स से संसाधनों के प्रवाह, मुख्य रूप से कर्ज प्रतिभूतियों के माध्यम से, में वर्ष 2014-15 से तेजी आयी। कुल वित्तीय देयताओं का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा कर्ज प्रतिभूतियाँ होती हैं। ये कर्ज प्रतिभूतियाँ निवेशकों के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में कार्य करती हैं और न्यूनतम सांविधिक तरलता अनुपात



चार्ट 11: सरकारी गैर वित्तीय क्षेत्र में संसाधन अंतराल



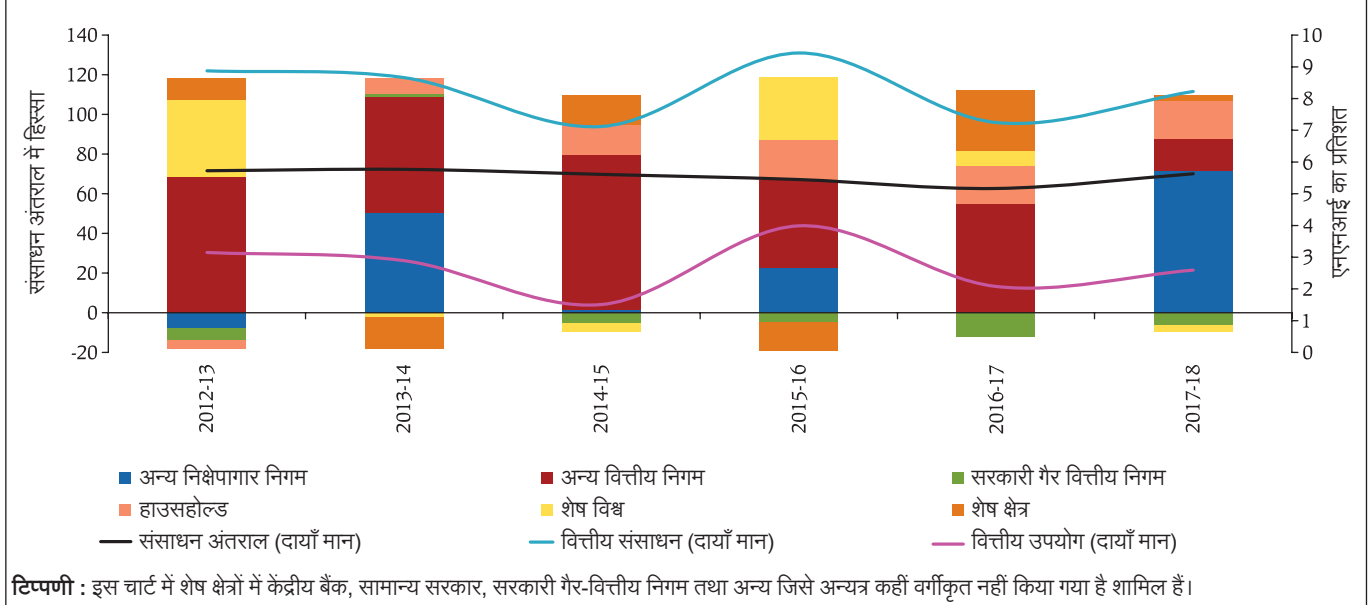
(एसएलआर) की आवश्यकता के अतिरिक्त तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) के तहत एससीबी के लिए इन्हें बनाए रखना अनिवार्य है।

III.4 हाउसहोल्ड्स और एनपीआईएसएच

हाउसहोल्ड्स बहुआयामी भूमिकाएं निभाते हैं- वे उपभोक्ता भी हैं, निवेशक भी और उद्यमी भी। जीडीपी का आधे से ज्यादा हिस्सा हाउसहोल्ड उपभोग के रूप में होता है और

लगभग दसवाँ हिस्सा हाउसहोल्ड निवेश का होता है। उद्यमियों की तरह कार्य करते हुए हाउसहोल्ड्स भवन, मशीनरी और ऐसे उपकरणों में निवेश करते हैं जो स्वरोजगार अथवा एकल स्वामित्व वाले श्रमिकों के रूप उनके व्यवसाय से संबंधित होते हैं। समग्र रूप से देखने पर हाउसहोल्ड्स आमतौर पर निवल बचतकर्ता और निवल ऋणदाता होते हैं, और उनकी निवल मालियत धनात्मक होती है। एनएनआई के प्रतिशत के रूप में

चार्ट 12: सरकारी क्षेत्र के संसाधन अंतराल को वित्तपोषण



वित्तीय अधिशेष में हाउसहोल्ड्स क्षेत्र की हिस्सेदारी 2011-12 से 2017-18 के बीच औसतन लगभग 8 प्रतिशत बनी रही। वर्तमान दशक में पहली बार 2015-16 के दौरान जीडीपी वृद्धि 8 प्रतिशत तक पहुंच गयी जिसके फलस्वरूप आय में उच्च वृद्धि दर्ज की गयी जिसने मुद्रा और जमाराशियों में बढ़ोतरी हुई और हाउसहोल्ड्स की वित्तीय आस्तियों और उनके अधिशेष में वृद्धि देखने को मिली। बाद के वर्षों में परिवारों के वित्तीय अधिशेष में संकुचन हुआ है। वर्ष 2017-18 में, हाउसहोल्ड्स की आस्तियों और देनदारियों दोनों में वृद्धि हुई लेकिन देनदारियों में वृद्धि की दर आस्तियों की तुलना में अधिक रही जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष में और अधिक कमी आयी (चार्ट 13)।

हाउसहोल्ड्स की आधे से अधिक आस्तियाँ नकदी और जमा के रूप में होती हैं; यद्यपि कुल आस्तियों में उनकी हिस्सेदारी समय के साथ घट रही है और उनका स्थान इक्विटी और कर्ज प्रतिभूतियाँ ले रही हैं। बीमा और पेंशन फंडों की हिस्सेदारी में भी धीरे-धीरे बढ़ रही है जो उनकी बेहतर होती जोखिम प्रबंधन क्षमता और पोर्टफोलियो विविधीकरण का संकेत देता है। हाउसहोल्ड्स के तुलन-पत्र में प्रमुख देनदारियाँ ऋण और उधारियाँ होती हैं जो मुख्य रूप से ओडीसी और ओएफसी से ली गयी होती हैं।

किससे-किसको आधार पर किए गए आकलन से पता चलता है कि हाउसहोल्ड्स ऐसे वित्तीय निगमों (ओडीसी और

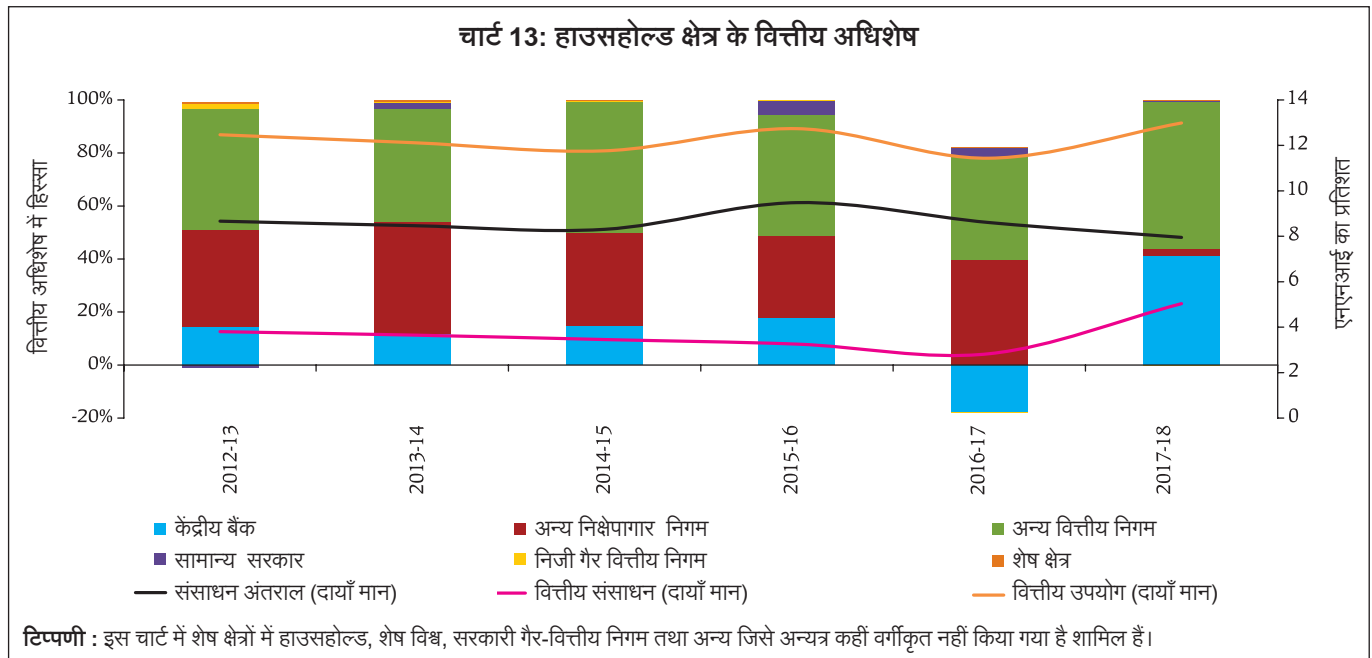
ओएफसी दोनों) से सर्वाधिक जुड़ाव महसूस करते हैं जो उनकी अधिशेष राशि को घाटे वाले क्षेत्रों में पहुंचाने का माध्यम बन सकें।

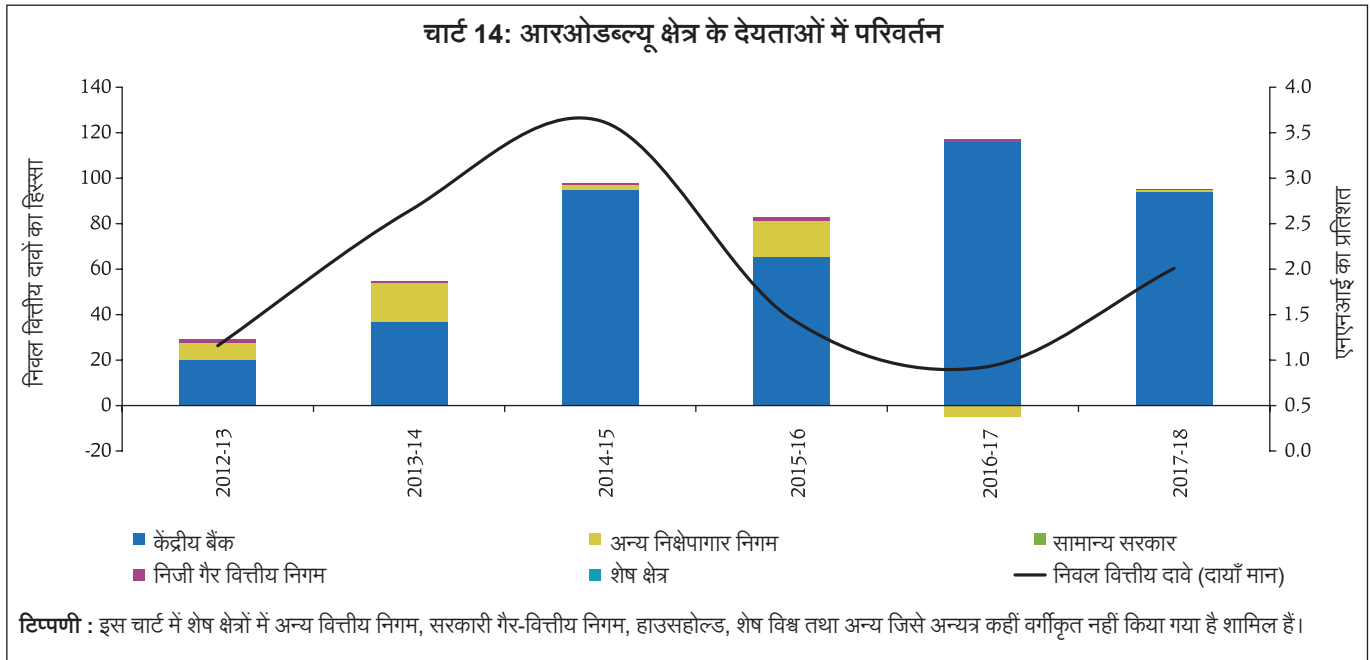
III.5 शेष विश्व

घरेलू अर्थव्यवस्था और अनिवासी संस्थागत इकाइयों के बीच वित्तीय संसाधनों के प्रवाह से शेष विश्व क्षेत्र की वित्तीय स्थिति और उसके लेनदेन का पता चलता है (भारतीय रिजर्व बैंक, 2015)। आरओडब्ल्यू (शेष विश्व) सेक्टर की निधियों का प्राथमिक श्रोत होते हैं- कर्ज प्रतिभूतियों का निर्गम जिनका अभिदान केंद्रीय बैंक और ओडीसी द्वारा किया जाता है, ओडीसी द्वारा किया गया जमा और एनएफसी द्वारा इक्विटी में निवेश (चार्ट 14)।

भारत में, आरओडब्ल्यू से निवेश इक्विटी और कर्ज प्रतिभूतियों रूप में प्राप्त होता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए प्रमुख रूप से गैर-वित्तीय निगमों की ओर से बढ़ती मांग के कारण ऋणों और उधार की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई। आस्तित्व पक्ष की बात करें तो जमाराशियों में आए उछाल से ओडीसी में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए जमा का पता चलता है। कर्ज आधारित लिखतों में आने वाले निधि-प्रवाह में मोटे तौर उतार-चढ़ाव बना रहा जबकि जबकि इक्विटी में आने वाला निधि-प्रवाह 2014-15 में तेजी से नीचे गिरा परंतु इसके

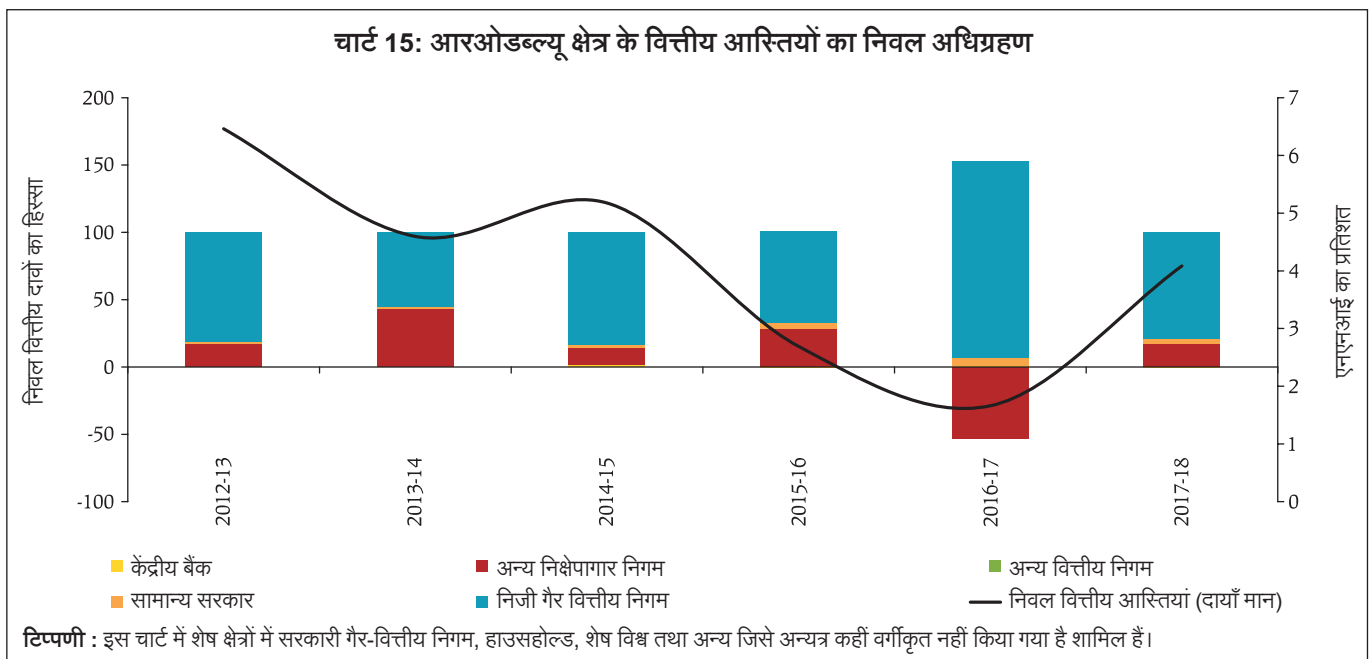
चार्ट 13: हाउसहोल्ड्स क्षेत्र के वित्तीय अधिशेष





बाद अगले वर्ष इसमें बहाली आयी और उसके बाद स्थिर बना रहा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में कर्ज संविभाग में आने वाला निधि-प्रवाह 2017-18 में फेड की दरों में हुई बढ़ोतरी से लगभग अप्रभावित रहा। कई प्रकार की चिंताओं, यथा- आय में वृद्धि, अत्यधिक मूल्यन और प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति के प्रभाव-प्रसार- के बीच इक्विटी में आने वाला एफपीआई लगभग आधा हो गया।

2016-17 में आरओडब्ल्यू द्वारा निवल वित्तीय संपत्ति में गिरावट के बावजूद, इसके माध्यम से भारत की बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता था। यह गिरावट मुख्य रूप से ओडीसी की कर्ज प्रतिभूतियों में आयी कमी और एनएफसी द्वारा चुकाए गए ऋणों के कारण थी। 2017-18 में गैर-वित्तीय निगमों द्वारा इक्विटी में अधिक निवेश के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन अधिक रहा (चार्ट 15)।



V. लिखतवार वित्तीय प्रवाह

वर्ष 2016-17 को छोड़ दें तो 2012-13 से 2017-18 की अवधि के दौरान वित्तीय देनदारियां अर्जित करने वाले लिखतों के संघटन में बदलाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। नकदी और जमाराशियाँ हमेशा से सबसे ज्यादा पसंदीदा वित्तीय लिखत रहे हैं परंतु उनका महत्व घटा है और उनकी जगह इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बीमा और भविष्य निधि ने ले ली है। दूसरी ओर, कर्ज प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जिनमें ज्यादातर वे हैं जो सामान्य सरकार द्वारा जारी की गयी हैं। ऋण और उधार, वित्तीय देनदारियों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरे सबसे महत्वपूर्ण लिखत हैं जिनके बाद इक्विटी का स्थान आता है। जहाँ तक ऋणों और अग्रिमों का प्रश्न है, देयताओं के निर्गम में हाउसहोल्ड्स क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, जबकि निजी गैर-वित्तीय निगम क्षेत्र प्रमुख उधारकर्ता था (चार्ट 16)।

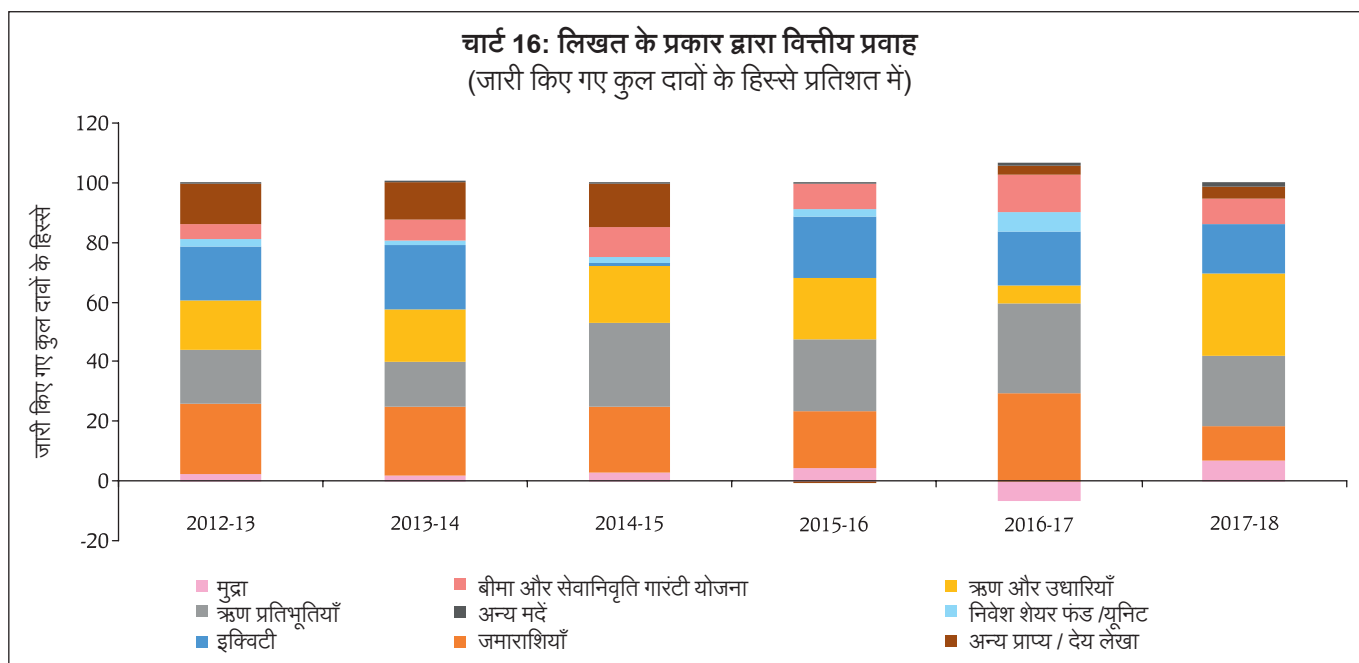
विमुद्रीकरण ने 2016-17 के दौरान वित्तीय देनदारियों के अर्जन के लिए इस्तेमाल किए गए लिखतों पर महत्वपूर्ण परंतु अल्पकालिक प्रभाव डाला और अगले वर्ष इसका बिलकुल उल्टा देखने को मिला। वर्ष 2016-17 के दौरान अधिक संख्या में बीमा पॉलिसियाँ और म्यूचुअल फंड यूनिट्स जारी की गयीं (चार्ट 16, सारणी 3 और विवरण 7)।

VI. वित्तीय विकास के चुनिंदा संकेतक

किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय विकास को व्यवहार अनुपातों, अर्थात्, वित्तीय अनुपात (एफआर), वित्तीय अंतर-संबंध अनुपात (एफआईआर), नवीन निर्गम अनुपात (एनआईआर), और मध्यस्थता अनुपात (आईआर) के संदर्भ में देखा जा सकता है। निष्पक्ष रूप से देखें तो, ये अनुपात वित्तीय विकास और समग्र आर्थिक विकास के बीच संबंधों को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

वित्तीय अनुपात की परिभाषा राष्ट्रीय आय के संबंध में किए गए प्राथमिक और द्वितीयक दावों के कुल निर्गमों के अनुपात के रूप में की जा सकती है और यह उस अर्थव्यवस्था में वित्तीय सेवाएं पहुंचाने की गति को दर्शाता है। एफआर में वृद्धि दर्ज की गयी और इसमें 2013-14 के बाद लगातार तीन वर्षों तक गिरावट के बाद बढ़कर वर्ष 2016-17 के 0.38 की तुलना में 2017-18 में 0.51 हो गया (सारणी 4)।

वित्तीय विकास और भौतिक निवेश में वृद्धि के बीच संबंध का जायजा वित्तीय अंतर-संबंध अनुपात (एफआईआर) द्वारा लिया जाता है। कुल वित्तीय देनदारियों और निवल घरेलू पूंजी निर्माण के अनुपात के रूप में परिभाषित यह अनुपात 2016-17 के 1.63 से बढ़कर 2017-18 में 1.82 हो गया।



सारणी 3: लिखतवार और क्षेत्रवार आस्तियों का अधिग्रहण, 2017-18

(₹ बिलियन में)

लिखत/क्षेत्र	वित्तीय निगम	सामान्य सरकार	गैर वित्तीय निगम	हाउसहोल्ड और एन-आईपीआईएसएच	अन्य विश्व	कुल
1. मौद्रिक स्वर्ण और एसडीआर	125.2	0	0	0	0	125.2
2. मुद्रा और जमाराशियां	-252.5	1,300.0	2,152.3	10,018.2	1,066.0	14,284.0
3. कर्ज प्रतिभूतियाँ	12,940.6	-94.5	1,120.3	39.2	577.1	14,582.7
4. ऋण और उधारियां	19,733.9	735.5	417.1	0	1,039.0	21,925.5
5. इक्विटी और निवेश निधि शेयर	-512.7	1,908.4	3,233.2	1,749.2	3,392.2	9,770.4
6. बीमा,पेंशन और भविष्य निधि	0.6	0	0	7,435.8	0	7,436.4
7. अन्य प्राप्त/देय लेखा	1,087.6	2.3	3,544.8	42.0	-4.8	4,671.9
8. अन्यत्र वर्गीकृत न किए गए मद	40.0	0	0	0	0	40.0
9. कुल	33,162.6	3,851.8	10,467.7	19,284.4	6,069.4	72,836.0

नवीन निर्गम अनुपात (एनआईआर) में हुई वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि 2017-18 के दौरान के तौर पर प्राथमिक निर्गमों में, जो निवल घरेलू पूंजी निर्माण का एक हिस्सा होते हैं, तीव्र उछाल आया है। इसके अतिरिक्त, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरओडब्लू क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक निर्गमों में वृद्धि यह दर्शाती है कि बाह्य वित्त की भूमिका भी बढ़ गयी है।

मध्यस्थता अनुपात (आईआर) यह दर्शाता है कि कोई अर्थव्यवस्था वित्तीय क्षेत्र पर किस हद तक निर्भर करती है। इसे वित्तीय क्षेत्र की देनदारियों (या द्वितीयक निर्गमों) तथा गैर-वित्तीय क्षेत्र की देनदारियों (या प्राथमिक निर्गमों) के अनुपात के रूप में मापा जाता है। इससे यह देखा जा सकता है कि वित्तीय क्षेत्र की

भूमिका प्राथमिक निर्गमों की तुलना में द्वितीयक निर्गमों में अधिक होती है। इससे इस संकल्पना को भी बल मिलता है कि गैर-वित्तीय निगम ज्यादातर अपनी बचत से वित्तपोषित होते हैं अथवा वे अधिकाधिक रूप से बाह्य वाणिज्यिक उधारियों पर निर्भर होते जाते हैं। दूसरे शब्दों में, यह बढ़े हुए बाह्य वित्तपोषण और साथ ही, बढ़े हुए अंतर-क्षेत्रीय निधि प्रवाह से भी परिलक्षित होता है।

VII. वित्तीय लेखा के अनुप्रयोग : वित्तीय प्रवाहों के नेटवर्क का विश्लेषण

वित्तीय लेखा से अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के अंदरूनी हालात की झलक मिलती है। वित्तीय निधियों के स्रोतों और उनके प्रयोगों को समझने की सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करके और

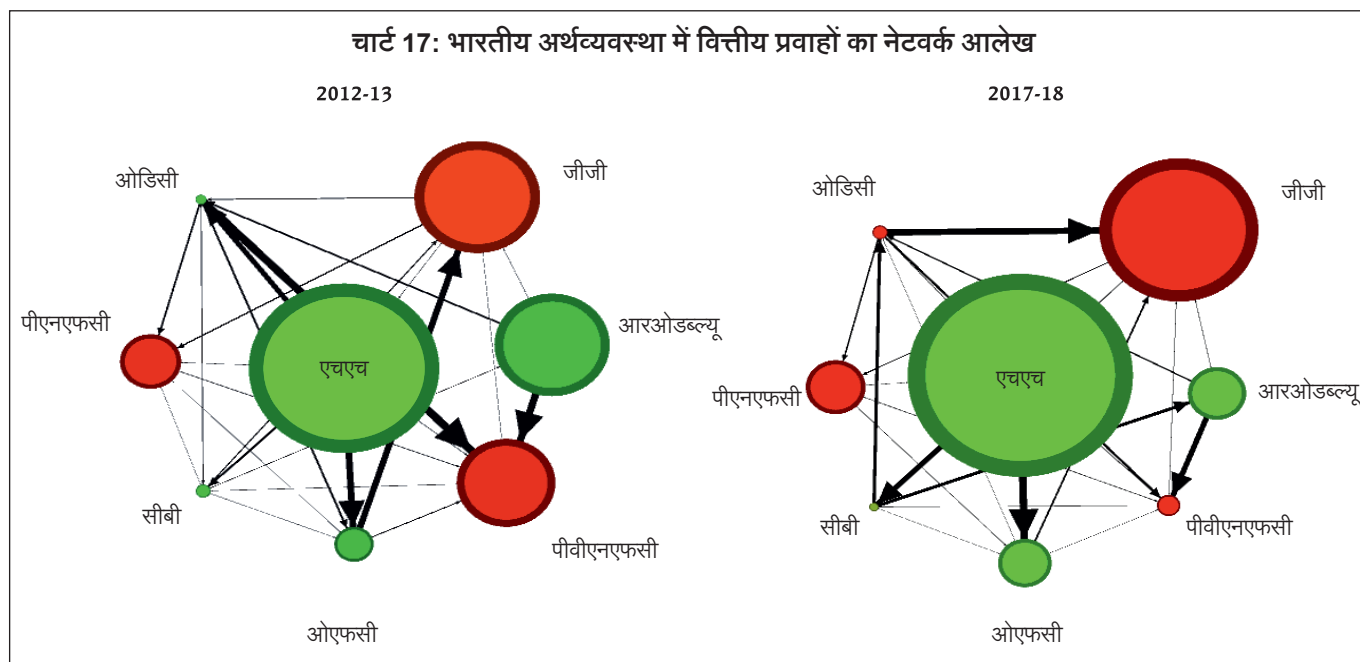
सारणी 4: वित्तीय गतिविधियों का चुनिन्दा संकेतक

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1. गौण मामले#	21,146.9	22,477.4	20,211.3	23,367.9	23,325.5	30,686.0
2. प्राथमिक मामले##	25,992.5	34,588.2	35,042.0	31,242.8	28,058.1	37,507.6
2.1 घरेलू क्षेत्र	24,977.5	31,976.1	31,055.8	29,476.5	26,817.2	34,524.2
2.2 शेष विश्व	1,014.9	2,612.1	3,986.2	1,766.3	1,240.9	2,983.4
3. कुल मामले (1+2)	47,139.4	57,065.6	55,253.3	54,610.7	51,383.7	68,193.6
4. निवल घरेलू पूंजी निर्माण@	27,862.2	25,981.6	28,374.9	29,729.6	31,506.6	37,451.4
5. वित्तीय अनुपात (3 से 5 का अनुपात)	0.54	0.58	0.50	0.45	0.38	0.51
6. वित्तीय आंतर-संबंधी अनुपात (3 से 4 का अनुपात)	1.69	2.20	1.95	1.84	1.63	1.82
7. नए मामले का अनुपात (2 से 4 का अनुपात)	0.93	1.33	1.23	1.05	0.89	1.00
8. मध्यस्थता अनुपात (1 से 2 का अनुपात)	0.81	0.65	0.58	0.75	0.83	0.82

#: वित्तीय बिचोलियों द्वारा उल्लेखित मामले (अर्थात ओडीसी और ओएफसी)।

##: वित्तीय बिचोलियों के अलावा सभी क्षेत्र द्वारा उल्लेखित मामले।

@: वर्तमान कीमत पर।



क्षेत्रवार अधिशेष अथवा घाटे की पहचान करके वह हमें यह समझने में मदद करता है कि अंतर-क्षेत्रीय संबद्धता के कारण जोखिमों और आघातों का संचरण कैसे होता है और हमें बचत, पूंजी निर्माण, घन, ऋणग्रस्तता की व्याख्या करने में भी उससे सहायता मिलती है।

एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू फ्रेमवर्क वित्तीय लेखा में नेटवर्क सिद्धांत के अनुप्रयोग को आसान बनाता है ताकि वित्तीय प्रणाली में आघातों के संचरण से प्रभावी ढंग से मुक्ति पायी जा सके (भा.रि.बैंक, 2018)। इन ग्राफों में यह देखा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच निधियों का निवल प्रवाह (प्रयोग और स्रोत का अंतर) किस सीमा (परिमाण) तक हुआ है (चार्ट 17)। नोड्स का आकार दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों के बीच निवल ऋण/ उधार में से अलग-अलग क्षेत्रों की सापेक्षिक हिस्सेदारी कितनी है। हरे रंग वाले नोड्स निवल ऋणदाताओं को दर्शाते हैं जबकि लाल रंग वाले नोड्स निवल उधारकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। किनारों की भारिता अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों के बीच निवल ऋण/ उधार में से एक क्षेत्र द्वारा दूसरे क्षेत्र को दिए गए निवल ऋणों/ ली गयी उधारियों को दर्शाती है। इससे किन्हीं भी दो क्षेत्रों के बीच कभी भी निवल ऋणों/उधारियों की सापेक्ष स्थिति का पता लगाया जा सकता है, न कि इनका निरपेक्ष मान।

एचएच निवल ऋणदाता होते हैं और सापेक्ष रूप से देखें तो अर्थव्यवस्था में इनका हिस्सा सबसे अधिक होता है। वर्ष

2012-13 की तुलना में देखें तो 2017-18 में निवल उधारकर्ता के रूप में जीजी का आकार बढ़ा है। निवल ऋणदाता के रूप में आरओडब्ल्यू की भूमिका काफी कम हो गयी है, जबकि निवल ऋणदाता के रूप में ओएफसी की भूमिका में मामूली वृद्धि हुई है। पीयूएनएफसी का सापेक्ष आकार मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा है। पीवीएनएफसी के निवल उधार की स्थिति में वर्ष 2012 की तुलना में 2017 में गिरावट आई है। विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप लिखतों के संघटन में बदलाव आया जिससे ओडीसी जो पहले निवल ऋणदाता हुआ करते थे, अब निवल उधारकर्ता बन गए।

VIII. निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था में 2011-12 से 2017-18 की अवधि के दौरान सभी प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय लेनदेन के प्रकृति और मात्रा में बड़े बदलाव देखे गए। हाउसहोल्ड क्षेत्र में, जो निधियों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, घरेलू बचत के अपेक्षाकृत अधिक वित्तीयकरण और विविधीकरण के बल पर बड़ा व्यवहारिक बदलाव देखने को मिल रहा है- यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर बनी रहने के प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है। घरेलू बचत जो पहले प्रायः भौतिक रूप में हुआ करती थी, वह अब वित्तीय आस्तियों के रूप में बदल रही है। इसके अलावा, यह भी देखा जा रहा है कि बैंक जमा का स्थान अब म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन फंड में निवेश ले रहा है।

वित्तीय लेखा से साफ देखा जा सकता है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच अंतर-संबद्धता तेजी से बढ़ रही है। ऐसा पाया गया है कि जिन वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम में गिरावट आयी है, उन वर्षों में एनबीएफसी द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम बढ़े हैं और यही बात इसके उलट भी लागू होती है। नेटवर्क विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अन्य जमा निगमों और अन्य वित्तीय निगमों के बीच अंतर-संबद्धता है। प्रणालीगत जोखिम की निगरानी के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो एससीबी द्वारा दिए गए ऋणों और एससीबी में एनबीएफसी की इक्विटी होल्डिंग के रूप में एससीबी तथा एनबीएफसी के बीच अंतर-संबद्धता महत्वपूर्ण हो जाती है (भारि. बैंक, 2018)।

हाउसहोल्ड्स क्षेत्र द्वारा इक्विटी और कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश में हुई वृद्धि और साथ ही, आरओडब्ल्यू द्वारा इस तरह के लिखतों में किए जाने वाले निवेश में आयी कमी से यह तथ्य उभरकर आता है कि भारतीय इक्विटी बाजार में घरेलू निवेशकों ने विदेशी निवेशकों को पीछे छोड़ दिया है। व्यापार संरक्षणवाद के बढ़ने और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में इसका प्रभाव पूरे विश्व में फैलने के परिणामस्वरूप बने अत्यधिक अनिश्चितता वाले माहौल के बाद शेष विश्व क्षेत्र की भूमिका धीरे धीरे कम होती प्रतीत हुई है।

हाल के वर्षों में, सामान्य सरकार अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख घाटे वाला क्षेत्र बनकर उभरी है जो हाउसहोल्ड्स क्षेत्र द्वारा संचित अधिकांश अधिशेष को खा जा रही है। इससे बाजार में प्रचलित ब्याज दरों पर दबाव बढ़ा है (कानूनगो, 2018)। गैर वित्तीय निगमों द्वारा लिए जा रहे उधार में आयी कमी से भी निजी निवेश के कुछ सीमा तक बहिर्गमन की पुष्टि होती है। निजी गैर-वित्तीय कॉरपोरेट आंतरिक संसाधनों का इस्तेमाल करते रहे हैं और उन्होंने उधार पर निर्भरता कम कर दी है।

संदर्भ

FSB (2018), "Financial Crisis and Information Gaps, Second Phase of the G20 Data Gaps Initiative (DGI-2) Third Progress Report" International Monetary Fund and Financial Stability Board.

Government of India (2012a), "Sequence of National Accounts India", National Statistics Organisation,

Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.

— (2012b), "Sources and Methods", National Statistics, Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.

— (2015), "Changes in Methodology and Data Sources in the New Series of National Accounts Base Year 2011-12", Central Statistical Organisation, Ministry of Statistics & Programme and Implementation, Government of India.

— (2018), "Report of the Committee on Financial Sector Statistics", Central Statistical Organisation, Ministry of Statistics & Programme and Implementation, Government of India.

— (2019), "Back Series Estimation Base 2011-12 Methodology Document", Central Statistical Organisation, Ministry of Statistics & Programme and Implementation, Government of India.

IMF (2016), "Monetary and Financial Statistics Manual and Compilation Guide", International Monetary Fund.

OECD (2018), "National Accounts of OECD Countries, Financial Balance Sheets 2018", OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/na_fbs-2019-en.

RBI (2015); "Report on the Working Group on Compilation of Flow of Funds Accounts of The Indian Economy", Reserve Bank of India.

— (2017), "Flow of Funds Accounts of The Indian Economy:2015-16", RBI Bulletin, August 2017, Reserve Bank of India.

— (2016), "Report on Trends and Progress of Banking in India", Reserve Bank of India.

— (2018), "Report on Trends and Progress of Banking in India", Reserve Bank of India.

— (2017), "Annual Report 2016-17", Reserve Bank of India.

— (2018), "Financial Stability Report", December 2018, Reserve Bank of India.

— (2019); “Bank Deposits: Underlying Dynamics”, RBI Bulletin, May, Reserve Bank of India.

— (2018), “State Finances: A Study of Budgets of 2017-18 and 2018-19”, Reserve Bank of India.

SNA (2008), “System of National Accounts”, United Nations, the European Commission, the Organisation

for Economic Co-operation and Development, the International Monetary Fund and the World Bank Group.

Van de Ven, P. and D. Fano (eds.) (2017), Understanding Financial Accounts, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264281288-en>.

वर्किंग पेपर और ओकेजनल के कागजात की प्रेस प्रकाशनियां

सीमा-पार व्यापार क्रेडिट : आर्थिक संकट के बाद भारत से
संबंधित अनुभवजन्य विश्लेषण

क्या भारत में वित्तीय चक्र मौजूद है ?

सीमा-पार व्यापार क्रेडिट : आर्थिक संकट के बाद भारत से संबंधित अनुभवजन्य विश्लेषण

इस पेपर में भारतीय आयातकों को घरेलू और विदेशी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले व्यापार क्रेडिट के आकार, संघटन और लागत पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसका लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए 2007-08 की पहली तिमाही से लेकर 2016-17 की चौथी तिमाही तक के लिए 55 बैंकों के पैनल डाटा का प्रयोग करते हुए, यह पेपर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि व्यापार क्रेडिट के प्रवाह को मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों से जुड़े कारक प्रभावित करते हैं।

इस पेपर में दर्शाया गया है कि आयात में वृद्धि – चाहे यह बढ़ी हुई कीमतों के कारण हो, या बढ़ी हुई मात्रा के कारण हो – के परिणामस्वरूप व्यापार क्रेडिट बढ़ता है। आपूर्ति पक्ष की दृष्टि से देखें तो बैंकों की वित्तीय सेहत, व्यापार क्रेडिट की लागत और उनका समुद्रपारीय नेटवर्क का आकार उनके व्यापार क्रेडिट परिचालनों को प्रभावित करता दिखाई पड़ता है। इस पेपर के अनुभवजन्य निष्कर्ष इस ओर इशारा करते हैं कि बैंकों को चाहिए कि वे अपने वैश्विक बैंकिंग संबंधों में विस्तार करें और देशी लिखतों (अर्थात् एलओयू/एलओसी) में कारोबार से आगे बढ़ते हुए वैश्विक रूप में स्वीकृत व्यापार वित्त लिखतों में कारोबार करें, हालांकि इससे लागत बढ़ेगी।

क्या भारत में वित्तीय चक्र मौजूद है?

पेपर का उद्देश्य बैंक ऋण, इक्विटी कीमतों, घरों की कीमतों और वास्तविक विनिमय दर पर विचार करते हुए भारतीय संदर्भ में पहली बार वित्तीय चक्र का एक समग्र परिमाण प्रदान करना है। वित्तीय चक्र के अस्तित्व की पहचान करने के लिए वित्तीय चक्र के चक्रीय गुणों की जांच की जाती है। समग्र विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में एक अच्छा परिभाषित वित्तीय चक्र और वित्तीय चक्र के विस्तारक चरण, विशेष रूप से शिखर है जो बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते दबाव और भविष्य में आर्थिक गतिविधि के कमजोर होने की एक प्रारंभिक चेतावनी देते हैं। विश्लेषण से यह भी संकेत मिलता

है कि वित्तीय चक्र में चलनेवाली गिरावट 2018 की चौथी तिमाही तक न्यूनतम तक पहुंच सकती है। पेपर 12 वर्ष की औसत अवधि के साथ लंबी अवधिवाले वित्तीय चक्र, साथ ही साथ 5 वर्ष की औसत अवधि के साथ कम अवधिवाले वित्तीय चक्र का अन्वेषण करता है। 1990 के दशक के मध्य से वित्तीय उदारीकरण की गति में वृद्धि के साथ वित्तीय चक्र के समग्र परिवर्तन में मध्यम अवधि के चक्रों का वर्चस्व बढ़ा है। जबकि भारत में क्रेडिट और इक्विटी दोनों मूल्य वित्तीय चक्र चलाते हैं, 2000 दशक के मध्य से आवासीय कीमतों का योगदान बढ़ गया है। पेपर बताता है कि व्यापक अंतराल और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक नियमित अंतराल पर वित्तीय चक्र की करीबी निगरानी आवश्यक है।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	65
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	66
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	67
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय	68
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	69
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	69
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	70
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	71
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	72
9	कुल चलनिधि राशियां	72
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	73
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	73
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	74
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	74
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	75
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	76
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	77
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	78
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	79
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	79
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	79
21	थोक मूल्य सूचकांक	80
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	83
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	83
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	84
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	84
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	85
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	86
28	वाणिज्यिक पत्र	86
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	86
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	87

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	88
32	विदेशी मुद्रा भंडार	88
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	88
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	89
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	89
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	90
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	90
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	91
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (बिलियन ₹)	92
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	93
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (बिलियन ₹ में)	94
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	95
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	96
	अवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	97
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	98
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	99
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	100
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	101
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	102

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

- = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम

आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2018-19	2017-18		2018-19	
		ति३	ति४	ति३	ति४
		1	2	3	4
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.6	7.3	7.9	6.3	5.7
1.1.1 कृषि	2.9	4.6	6.5	2.8	-0.1
1.1.2 उद्योग	6.2	8.0	8.6	6.0	3.4
1.1.3 सेवाएं	7.7	8.0	8.0	7.6	8.2
1.1क अंतिम खपत व्यय	8.3	5.8	8.1	7.9	8.1
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	10.0	12.2	14.4	11.7	3.6
	2018-19	2018		2019	
		अप्रैल	मई	अप्रैल	मई
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	3.60	4.5	3.8	3.4	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	10.0	7.7	8.1	9.7	11.1
2.1.2 ऋण	13.3	12.3	12.8	13.0	13.5
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	13.4	12.5	13.0	13.1	13.3
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.9	5.6	5.1	2.8	3.7
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	14.5	27.0	24.9	13.0	13.8
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.5	10.2	10.4	10.0	10.3
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.25	19.50	19.50	19.00	19.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	4.9	4.7	4.8	4.9
3.4 ऋण-जमा अनुपात	77.7	74.8	75.2	77.1	76.8
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	99.9	**	**	**	-223.4
3.6 निवेश-जमा अनुपात	26.9	29.5	29.7	27.7	27.7
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	5.4	*	*	*	315.6
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.00	6.00	6.00	6.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	6.00	5.75	5.75	5.75	5.75
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.50	6.25	6.25	6.25	6.25
4.4 बैंक दर	6.50	6.25	6.25	6.25	6.25
4.5 आधार दर	8.95/9.40	8.70/9.45	8.70/9.45	8.95/9.40	8.95/9.40
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.05/8.55	7.80/7.95	7.80/7.95	8.05/8.50	8.05/8.50
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/7.50	6.25/6.75	6.25/6.75	6.25/7.50	6.25/7.50
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.35	5.92	5.94	6.16	5.90
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.31	6.19	6.40	6.44	6.19
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.35	6.42	6.80	6.50	6.27
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.39	6.63	6.93	6.51	6.30
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.34	7.80	7.92	7.45	7.07
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.17	66.78	68.26	70.14	69.81
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	77.70	80.74	79.88	78.13	77.73
5.3 फारवर्ड प्रीमिआ अमेरिकी डालर					
1-माह (%)	6.07	4.22	4.13	4.83	3.95
3-माह (%)	4.80	3.89	4.01	4.51	3.95
6-माह (%)	4.16	3.97	4.04	4.28	3.93
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.4	4.6	4.9	3.0	3.0
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	4.0	4.0	8.3	8.7
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	4.3	3.6	4.8	3.1	2.5
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	2.7	2.6	3.8	6.5	6.2
6.3.2 ईंधन और पावर	11.5	8.0	12.7	3.8	1.0
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	3.7	3.3	3.8	1.7	1.3
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	10.3	2.9	13.6	3.6	4.3
7.2 निर्यात	8.6	5.6	20.5	0.5	3.9

** हर और अंश नकारात्मक है

* हर नकारात्मक है

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(बिलियन ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार / शुक्रवार की स्थिति						
	2018-19	2018	2019				
			जून	मई 31	जून 7	जून 14	जून 21
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	21,137.64	19,174.27	21,713.70	21,936.42	21,938.99	21,799.72	21,635.30
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	0.11	0.09	0.11	0.13	0.11	0.12	0.09
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	21,137.75	19,174.36	21,713.81	21,936.55	21,939.10	21,799.84	21,635.39
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	794.81	743.56	757.82	757.82	757.82	757.82	757.82
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	20,335.59	18,421.54	20,947.36	21,170.21	21,172.84	21,033.63	20,869.24
1.2.3 रुपया सिक्का	7.35	9.26	8.63	8.52	8.44	8.39	8.33
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—	—
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	8,060.12	6,177.25	6,808.97	6,823.03	7,144.77	7,132.26	7,455.15
2.1.1.1 केंद्र सरकार	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	1.01	1.00
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—	—	—
2.1.1.3 राज्य सरकारें	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,657.07	4,922.13	5,364.15	5,093.60	5,441.41	5,032.48	5,720.13
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	41.97	36.86	39.10	38.32	37.99	38.18	39.97
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	34.94	18.82	25.84	27.14	26.44	25.33	26.61
2.1.1.7 अन्य बैंक	320.36	274.21	301.72	300.01	301.11	297.83	308.66
2.1.1.8 अन्य	1,997.34	923.80	1,076.73	1,355.35	1,336.39	1,737.01	1,358.36
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	7.00	—	—	7.18	—	—	—
2.1.2 अन्य देयताएं	10,876.86	10,307.00	11,436.01	11,358.34	11,384.83	11,546.32	11,309.45
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	18,936.98	16,484.25	18,244.98	18,181.37	18,529.60	18,678.58	18,764.59
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	0.11	0.09	0.11	0.13	0.11	0.12	0.09
2.2.2 विदेश में रखे शेष	6,466.40	7,925.82	6,803.28	6,496.05	6,504.09	6,963.93	6,926.94
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	—	253.22	—	425.31	429.52	—	65.96
2.2.3.2 राज्य सरकारें	0.10	6.43	13.22	54.01	92.76	1.63	16.61
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1,806.88	918.26	449.76	265.44	432.95	512.30	541.85
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—	0.35	0.35	0.35	—	—
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.6 नाबार्ड	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.8 अन्य	134.63	62.37	70.21	68.34	67.28	64.79	67.91
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	7.00	—	—	7.18	—	—	—
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	—	—	—	—	—	—	—
2.2.5 निवेश	9,230.80	6,361.53	9,628.90	9,593.19	9,728.07	9,857.32	9,857.67
2.2.6 अन्य आस्तियां	1,291.06	956.53	1,279.15	1,271.37	1,274.47	1,278.49	1,287.57
2.2.6.1 सोना	871.69	697.93	844.83	844.83	844.83	844.83	844.83

* डाटा अंतिम है।

सं. 3: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(बिलियन ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिपो दर				विक्रय	क्रय	
मई 1, 2019	-	242.41	-	-	0.70	-	-	-	-	-241.71
मई 2, 2019	50.41	224.55	-	-	5.10	0.75	-	-	-	-168.29
मई 3, 2019	44.21	406.85	123.65	-	3.17	-	-	-	125.00	-110.82
मई 4, 2019	-	324.57	-	-	-	-	-	-	-	-324.57
मई 6, 2019	44.36	405.30	-	118.35	-	-	-	-	-	-479.29
मई 7, 2019	45.51	369.82	107.00	-	6.00	-	-	-	-	-211.31
मई 8, 2019	60.31	134.53	-	95.89	0.50	-	-	-	-	-169.61
मई 9, 2019	164.61	124.47	-	-	3.85	-	-	-	-	43.99
मई 10, 2019	56.21	447.43	225.90	-	0.66	-	-	-	-	-164.66
मई 13, 2019	76.66	202.21	-	-	0.52	-	-	-	-	-125.03
मई 14, 2019	44.16	335.48	183.50	-	-	-	-	-	-	-107.82
मई 15, 2019	114.91	127.01	-	209.22	1.82	-	-	-	-	-219.50
मई 16, 2019	61.36	113.85	-	300.06	0.07	-	-	-	-	-352.48
मई 17, 2019	90.61	64.10	118.50	177.99	17.70	-0.78	-	-	125.00	108.94
मई 18, 2019	-	127.64	-	-	41.25	-	-	-	-	-86.39
मई 20, 2019	70.11	189.82	-	-	4.25	-0.56	-	-	-	-116.02
मई 21, 2019	80.16	102.46	156.50	-	-	1.34	-	-	-	135.54
मई 22, 2019	67.41	115.09	-	-	0.02	-1.70	-	-	-	-49.36
मई 23, 2019	45.01	232.56	-	-	-	1.90	-	-	-	-185.65
मई 24, 2019	48.46	295.88	165.00	248.98	16.15	-	-	-	-	-315.25
मई 27, 2019	183.31	85.72	-	400.07	1.00	-1.40	-	-	-	-302.88
मई 28, 2019	114.46	149.58	35.60	250.40	10.00	0.90	-	-	-	-239.02
मई 29, 2019	52.66	190.10	-	350.10	5.00	-	-	-	-	-482.54
मई 30, 2019	156.06	123.60	-	464.60	-	-	-	-	-	-432.14
मई 31, 2019	99.56	120.91	31.50	419.41	4.66	-	-	-	-	-404.60

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में परिचालन

मद	2018-19	2018	2019	
		मई	अप्रैल	मई
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	-15,377.00	-5,767.00	4,901.00	2,538.00
1.1 क्रय (+)	40,804.00	4,101.00	7,724.00	5,118.00
1.2 विक्रय (-)	56,181.00	9,868.00	2,823.00	2,580.00
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (बिलियन ₹)	-1,119.45	-392.20	330.92	167.98
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डालर)	-15,377.00	-8,250.00	4,901.00	7,439.00
(बिलियन ₹)	-1,119.45	-552.20	330.92	498.90
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	-13,774.00	11,252.00	-18,512.00	-18,288.00

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2018-19	2018	2019	
		मई	अप्रैल	मई
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 क्रय (+)	13,935.0	2,705.00	180.00	312.00
1.2 विक्रय (-)	13,935.0	2,705.00	180.00	312.00
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	0.00	-735.00	0.00	0.00

**सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)**

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	31 मई 2019 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	1,418	1,951	-533
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	200	2,645	-2,445
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	0	4,425	-4,425
4. 1 वर्ष से अधिक	0	10,885	-10,885
कुल (1+2+3+4)	1,618	19,906	-18,288

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2018-19	2018	2019					
			जून 22	जनवरी 18	फरवरी 15	मार्च 29	अप्रैल 26	मई 24
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	128.8	20.4	5.0	10.9	128.8	10.0	16.2	14.0
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 सीमा	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3.2 बकाया	26.8	23.9	17.0	17.9	26.8	23.5	27.6	24.5
4.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	155.6	44.4	22.1	28.8	155.6	33.5	43.8	38.5

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2018-19	2018		2019	
		मई 25	अप्रैल 26	मई 10	मई 24
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	20,522.3	18,537.9	20,920.6	21,177.7	21,173.7
1.1 संचलन में नोट	21,108.8	19,050.6	21,540.7	21,778.2	21,786.1
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	251.4	249.6	251.7	251.7	251.7
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
1.4 बैंकों के पास नकदी	845.4	769.6	879.2	859.6	871.5
2 जनता की जमाराशियां	16,580.5	13,100.3	14,941.0	14,540.6	14,562.1
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	16,263.1	12,831.7	14,664.4	14,253.2	14,277.5
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	317.4	268.6	276.6	287.4	284.5
3 एम₁ (1+2)	37,102.8	31,638.2	35,861.6	35,718.3	35,735.8
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	1,348.6	1,138.5	1,348.6	1,348.6	1,348.6
5 एम₂ (3+4)	38,451.5	32,776.7	37,210.3	37,066.9	37,084.4
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	117,205.9	108,206.5	117,924.4	118,679.9	118,475.0
7 एम₃ (3+6)	154,308.7	139,844.8	153,786.0	154,398.2	154,210.8
8 कुल डाकघर जमाराशियां	3,579.5	3,108.0	3,579.5	3,579.5	3,579.5
9 एम₄ (7+8)	157,888.3	142,952.7	157,365.5	157,977.7	157,790.3

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(बिलियन ₹)

स्रोत	मार्च 31 / माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		मई 25	अप्रैल 26	मई 10	मई 24
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	43,877.9	42,037.7	45,029.7	46,020.0	46,044.1
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	8,019.5	6,234.0	8,428.1	8,865.0	8,792.1
1.1.1 सरकार पर दावे	9,296.9	6,275.9	9,285.5	9,367.2	9,465.3
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	9,281.7	6,262.8	9,284.8	9,334.1	9,460.0
1.1.1.2 राज्य सरकारें	15.2	13.1	0.7	33.1	5.3
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	1,277.4	41.9	857.4	502.2	673.2
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	1,276.9	41.5	857.0	501.8	672.8
1.1.2.2 राज्य सरकारें	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	35,858.4	35,803.7	36,601.6	37,155.0	37,252.0
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	103,801.8	91,248.8	102,268.2	102,335.9	102,296.6
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	153.6	94.5	86.8	91.8	92.5
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	103,648.2	91,154.3	102,181.3	102,244.1	102,204.1
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	97,691.9	85,376.6	96,209.5	96,247.6	96,215.5
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	5,859.3	5,693.4	5,883.7	5,900.5	5,888.1
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	97.0	84.3	88.2	96.0	100.6
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	30,708.4	29,759.5	31,433.3	31,470.9	31,365.5
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	28,485.9	28,144.4	29,210.8	29,248.3	29,143.0
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	28,488.0	28,146.4	29,212.9	29,250.5	29,145.1
3.1.2 विदेशी देयताएं	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2,222.5	1,615.1	2,222.5	2,222.5	2,222.5
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	258.9	257.0	259.1	259.1	259.1
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	24,338.2	23,458.2	25,204.3	25,687.7	25,754.5
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	10,588.0	9,987.7	10,933.7	10,863.9	10,711.3
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	13,750.3	13,470.5	14,270.6	14,823.8	15,043.2
एम₃ (1+2+3+4-5)	154,308.7	139,844.8	153,786.0	154,398.2	154,210.8

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		मई 25	अप्रैल 26	मई 10	मई 24
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम ₁ (1.1 + 1.2.1+1.3)	37,102.8	31,638.2	35,861.6	35,718.3	35,735.8
एन एम ₂ (एन एम ₁ + 1.2.2.1)	89,108.8	79,635.8	88,136.2	88,330.8	88,279.5
एन एम ₃ (एन एम ₂ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	156,452.1	141,970.2	155,721.9	156,232.8	156,077.8
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	20,522.3	18,537.9	20,920.6	21,177.7	21,173.7
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	131,831.8	119,492.9	130,830.1	131,169.9	131,041.5
1.2.1 मांग जमाराशियां	16,263.1	12,831.7	14,664.4	14,253.2	14,277.5
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	115,568.7	106,661.2	116,165.7	116,916.7	116,763.9
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	52,005.9	47,997.6	52,274.6	52,612.5	52,543.8
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	2,849.9	2,123.9	2,786.0	2,678.5	2,550.0
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	63,562.8	58,663.7	63,891.1	64,304.2	64,220.2
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	317.4	268.6	276.6	287.4	284.5
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,780.5	3,670.7	3,694.6	3,597.8	3,578.1
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	156,561.0	141,879.5	156,523.1	157,368.0	157,242.9
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	43,877.9	42,037.7	45,029.7	46,020.0	46,044.1
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	8,019.5	6,234.0	8,428.1	8,865.0	8,792.1
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	35,858.4	35,803.7	36,601.6	37,155.0	37,252.0
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	112,683.1	99,841.9	111,493.4	111,348.0	111,198.8
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	153.6	94.5	86.8	91.8	92.5
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	112,529.4	99,747.4	111,406.6	111,256.3	111,106.4
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	8,798.5	8,512.3	9,135.9	8,920.8	8,805.3
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	258.9	257.0	259.1	259.1	259.1
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,017.3	26,829.0	28,570.7	28,405.5	28,380.1
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,485.9	28,144.4	29,210.8	29,248.3	29,143.0
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-468.6	-1,315.4	-640.1	-842.9	-762.9
2.4 पूंजी खाता	23,467.4	22,011.8	23,993.6	24,124.0	24,055.7
2.5 अन्य मर्दे (निवल)	4,917.6	4,983.5	5,637.3	5,675.8	5,748.6

सं. 9: कुल चलनिधि राशियां

(बिलियन ₹)

समुच्चय	2018-19	2018	2019		
		मई	मार्च	अप्रैल	मई
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	156,452.1	141,970.2	156,452.1	155,721.9	156,077.8
2 डाकघर जमाराशियां	3,579.5	3,108.0	3,579.5	3,579.5	3,579.5
3 एल₁ (1 + 2)	160,031.6	145,078.2	160,031.6	159,301.4	159,657.3
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
4.1 सावधि मुद्रा उधार	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4.3 सावधि जमाराशियां	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5 एल₂ (3 + 4)	160,060.9	145,107.5	160,060.9	159,330.8	159,686.6
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	319.1	..	319.1
7 एल₃ (5 + 6)	160,380.0	..	160,380.0

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		मई 25	अप्रैल 26	मई 10	मई 24
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	21,367.7	19,307.6	21,799.8	22,037.3	22,045.2
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमा राशियां	6,019.7	5,033.5	5,604.6	5,421.2	5,343.7
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,585.0	4,708.5	5,229.4	5,059.2	4,982.0
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमा राशियां	317.4	268.6	276.6	287.4	284.5
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	27,704.8	24,609.7	27,681.0	27,745.9	27,673.4
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	9,548.0	6,196.0	9,144.8	9,102.3	8,982.6
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	8,019.5	6,234.0	8,428.1	8,865.0	8,792.1
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	8,004.7	6,221.3	8,427.9	8,832.4	8,787.3
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	9,274.3	6,253.5	9,275.7	9,325.2	9,451.3
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	9,274.3	6,253.5	9,275.7	9,325.2	9,451.3
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	7.4	9.3	9.1	8.9	8.7
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमा राशियां	1,276.9	41.5	857.0	501.8	672.8
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	14.8	12.7	0.2	32.6	4.8
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के ऋण	1,374.9	-132.4	629.9	145.6	98.1
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	1,374.9	-132.4	629.9	145.6	98.1
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	153.6	94.5	86.8	91.8	92.5
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	26.8	23.2	23.5	27.4	27.6
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	258.9	257.0	259.1	259.1	259.1
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,485.9	28,144.4	29,210.8	29,248.3	29,143.0
2.3.1 सोना	1,595.9	1,449.2	1,611.9	1,607.8	1,607.8
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,890.2	26,695.4	27,599.1	27,640.8	27,535.4
2.4 पूंजी खाता	9,702.7	9,526.7	10,017.7	9,962.5	9,752.0
2.5 अन्य मदें (निवल)	885.3	461.1	916.0	901.3	959.3

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(बिलियन ₹)

मद	2018-19	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
		2018		2019				
		मई 25	अप्रैल 26	मई 3	मई 10	मई 17	मई 24	मई 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	27,704.8	24,609.7	27,681.0	27,880.2	27,745.9	28,165.6	27,673.4	28,001.0
1 घटक								
1.1 संचलन में मुद्रा	21,367.7	19,307.6	21,799.8	21,872.3	22,037.3	22,097.5	22,045.2	21,973.2
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमा राशियां	6,019.7	5,033.5	5,604.6	5,721.7	5,421.2	5,777.6	5,343.7	5,730.8
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमा राशियां	317.4	268.6	276.6	286.2	287.4	290.4	284.5	297.0
2 स्रोत								
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	8,019.5	6,234.0	8,428.1	8,814.8	8,865.0	9,016.5	8,792.1	9,440.0
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	1,374.9	-132.4	629.9	400.5	145.6	456.5	98.1	-90.2
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	153.6	94.5	86.8	91.3	91.8	91.0	92.5	89.9
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,485.9	28,144.4	29,210.8	28,909.9	29,248.3	29,216.5	29,143.0	29,351.1
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	258.9	257.0	259.1	259.1	259.1	259.1	259.1	259.5
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	10,588.0	9,987.7	10,933.7	10,595.4	10,863.9	10,874.0	10,711.3	11,049.3

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार / माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018		2019	
			मई 25	अप्रैल 26	मई 10
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	124,088.4	111,982.9	123,080.0	123,410.7	123,284.4
1.1.1 मांग जमाराशियां	15,110.8	11,698.9	13,517.2	13,107.0	13,130.9
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	108,977.5	100,284.0	109,562.8	110,303.7	110,153.5
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	49,039.9	45,127.8	49,303.3	49,636.7	49,569.1
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	2,849.9	2,123.9	2,786.0	2,678.5	2,550.0
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	59,937.6	55,156.2	60,259.5	60,667.0	60,584.5
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	3,780.5	3,670.7	3,694.6	3,597.8	3,578.1
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	140,289.7	127,621.5	139,902.8	140,283.3	140,249.7
2.1.1 सरकार को ऋण	33,783.0	33,726.8	34,543.3	35,092.1	35,199.7
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	106,506.7	93,894.7	105,359.5	105,191.2	105,050.0
2.1.2.1 बैंक ऋण	97,691.9	85,376.6	96,209.5	96,247.6	96,215.5
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	97,275.8	84,847.4	95,777.9	95,630.6	95,558.3
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	85.4	83.4	91.9	94.0	99.6
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	20.5	12.0	11.8	18.4	19.3
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	8,708.9	8,422.7	9,046.3	8,831.2	8,715.6
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-468.6	-1,315.4	-640.1	-842.9	-762.9
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2,623.8	1,590.8	2,516.0	2,412.3	2,408.2
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	1,637.2	1,545.3	1,758.7	1,763.2	1,711.1
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	1,455.3	1,360.9	1,397.5	1,492.0	1,460.0
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	5,380.8	5,513.3	5,381.2	5,677.2	5,658.0
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	5,657.1	4,708.5	5,229.4	5,059.2	4,982.0
2.3.2 उपलब्ध नकदी	748.5	672.3	781.7	763.5	774.2
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	1,024.8	-132.4	629.9	145.6	98.1
2.4 पूंजी खाता	13,523.1	12,243.4	13,734.2	13,919.7	14,061.9
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	3,809.9	3,922.3	4,135.1	4,189.4	4,220.4
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	3,979.8	3,537.3	3,482.5	3,412.5	3,384.0
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-484.5	-344.0	-559.1	-508.8	-579.0

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(बिलियन ₹)

मद	29 मार्च, 2019 की स्थिति	2018		2019	
		मई 25	अप्रैल 26	मई 10	मई 24
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	33,810.6	33,738.8	34,555.1	35,110.5	35,219.0
2 वाणिज्यिक पत्र	903.6	1,458.5	932.2	979.4	907.5
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	115.4	118.4	117.2	116.9	116.9
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	695.9	747.5	692.3	693.1	696.0
3.3 अन्य	63.8	42.6	63.2	55.9	55.9
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	1,348.2	1,254.1	1,327.3	1,312.2	1,305.8
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	2,687.8	2,168.5	2,594.3	2,582.6	2,537.7
4.3 अन्य	1,700.5	1,193.6	1,673.5	1,687.6	1,673.9
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	209.9	678.4	461.3	460.0	489.2
5.2 वित्तीय संस्थाएं	983.8	878.9	956.0	943.5	932.8

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2018-19	2018	2019		2018-19	2018	2019	
		मई	अप्रैल	मई		मई	अप्रैल	मई
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	222	223	213	213	147	149	138	138
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	2,763.5	2,495.0	2,597.6	2,564.2	2,714.3	2,443.3	2,548.1	2,516.4
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमा राशियां	1,816.5	1,567.2	1,745.9	1,769.7	1,768.3	1,521.7	1,700.3	1,723.2
1.2 बैंकों से उधार राशि	794.9	769.1	747.6	687.9	794.6	764.3	745.6	687.8
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	152.1	158.8	104.0	106.6	151.4	157.2	102.3	105.4
2 अन्य के प्रति देयताएं	138,359.8	125,238.6	136,819.1	138,321.1	134,956.7	122,097.1	133,412.3	134,890.4
2.1 कुल जमा राशियां	129,015.8	116,531.0	128,116.5	129,404.5	125,737.7	113,528.2	124,838.7	126,112.6
2.1.1 मांग	15,425.5	11,983.4	13,819.1	13,752.0	15,112.9	11,698.9	13,517.2	13,451.4
2.1.2 मीयादी	113,590.3	104,547.7	114,297.4	115,652.5	110,624.8	101,829.4	111,321.5	112,661.2
2.2 उधार	3,818.6	3,718.5	3,731.7	3,577.5	3,782.5	3,670.7	3,694.6	3,539.7
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	5,525.3	4,989.1	4,970.9	5,339.2	5,436.5	4,898.1	4,879.0	5,238.2
3 रिजर्व बैंक से उधार	1,806.9	581.8	1,054.8	450.1	1,806.9	581.8	1,054.8	449.8
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अन्य	1,806.9	581.8	1,054.8	450.1	1,806.9	581.8	1,054.8	449.8
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	6,575.6	5,519.1	6,165.8	6,297.7	6,405.8	5,380.8	6,011.1	6,147.2
4.1 उपलब्ध नकदी	765.5	689.5	799.1	801.3	748.77	672.3	781.7	783.0
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	5,810.0	4,829.6	5,366.8	5,496.3	5,657.1	4,708.5	5,229.4	5,364.2
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	3,726.7	3,258.1	3,604.2	3,579.8	3,278.1	2,870.6	3,199.1	3,129.8
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	2,458.8	2,154.2	2,429.1	2,479.3	2,230.5	1,987.9	2,227.1	2,266.4
5.1.1 चालू खाते में	172.2	99.3	138.0	145.7	133.3	79.6	112.4	121.1
5.1.2 अन्य खातों में	2,286.6	2,054.9	2,291.2	2,333.6	2,097.2	1,908.3	2,114.7	2,145.4
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	470.5	477.2	404.0	335.3	322.5	299.7	273.2	203.0
5.3 बैंकों को अग्रिम	329.5	304.3	282.9	317.6	296.4	299.7	264.6	275.4
5.4 अन्य आस्तियां	467.9	322.5	488.2	447.8	428.8	283.3	434.1	385.0
6 निवेश	34,756.1	34,681.7	35,483.5	35,928.3	33,810.6	33,738.8	34,555.1	34,990.8
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	34,678.4	34,616.7	35,414.8	35,852.3	33,790.0	33,726.8	34,543.3	34,973.0
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	77.6	64.9	68.8	76.0	20.5	12.0	11.8	17.8
7 बैंक ऋण	100,471.2	87,943.6	99,068.3	99,737.2	97,717.2	85,376.6	96,209.5	96,879.9
7क खाद्यान्न ऋण	646.4	759.4	702.0	1,031.1	416.1	529.1	431.6	760.8
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	97,922.9	85,736.2	96,677.0	97,391.1	95,219.9	83,226.6	93,867.5	94,580.1
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	276.4	214.9	257.8	279.5	262.2	190.8	244.3	267.2
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	1,609.8	1,378.5	1,487.7	1,457.7	1,583.0	1,352.2	1,461.6	1,433.6
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	249.1	237.1	239.2	226.6	245.9	234.9	235.2	222.5
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	413.0	376.9	406.5	382.3	406.2	372.0	400.8	376.5

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(बिलियन ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			मई 25	अप्रैल 26		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	86,749	76,365	85,241	85,167	-1.8	11.5
1.1 खाद्यान्न ऋण	415	527	430	655	57.9	24.2
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	86,334	75,838	84,810	84,512	-2.1	11.4
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	11,113	10,279	11,080	11,079	-0.3	7.8
1.2.2 उद्योग	28,858	26,446	28,352	28,140	-2.5	6.4
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	3,755	3,613	3,666	3,653	-2.7	1.1
1.2.2.2 मझौले	1,064	1,023	1,063	1,054	-0.9	3.0
1.2.2.3 बड़े	24,039	21,809	23,623	23,433	-2.5	7.4
1.2.3 सेवाएं	24,156	19,932	23,150	22,879	-5.3	14.8
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	1,385	1,218	1,409	1,416	2.2	16.2
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	185	182	186	184	-0.7	1.0
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	390	372	399	389	-0.2	4.6
1.2.3.4 नौवहन	77	66	65	62	-19.4	-5.2
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	1,715	1,546	1,713	1,708	-0.4	10.5
1.2.3.6 व्यापार	5,282	4,729	5,074	5,075	-3.9	7.3
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	2,505	2,100	2,267	2,267	-9.5	7.9
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	2,776	2,629	2,807	2,808	1.1	6.8
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	2,023	1,840	2,003	2,007	-0.8	9.1
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	6,412	4,439	6,234	6,235	-2.8	40.5
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	6,686	5,540	6,068	5,802	-13.2	4.7
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	22,207	19,181	22,228	22,414	0.9	16.9
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	63	201	62	61	-3.7	-69.8
1.2.4.2 आवास	11,601	9,919	11,686	11,769	1.4	18.7
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	829	632	674	665	-19.8	5.1
1.2.4.4 शेयरों और बाडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	63	55	57	55	-11.8	1.3
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	883	743	925	936	6.1	26.1
1.2.4.6 शिक्षा	680	692	675	674	-0.8	-2.5
1.2.4.7 वाहन ऋण	2,022	1,911	1,998	2,019	-0.1	5.7
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	6,068	5,029	6,150	6,235	2.8	24.0
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	27,390	24,828	27,299	27,275	-0.4	9.9
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	11,050	10,228	11,012	11,005	-0.4	7.6
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	10,672	9,503	10,660	10,623	-0.5	11.8
1.2अ.2.1 विनिर्माण	3,755	3,613	3,666	3,653	-2.7	1.1
1.2अ.2.2 सेवाएं	6,917	5,890	6,994	6,970	0.8	18.3
1.2अ.3 आवास	4,327	3,699	4,321	4,325	-0.0	16.9
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	241	197	273	276	14.6	40.1
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	540	572	538	542	0.4	-5.4
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	4	3	4	4	-3.3	25.9
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	6,626	5,718	6,770	6,794	2.5	18.8
1.2अ.8 निर्यात ऋण	156	208	152	144	-7.6	-30.9

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(बिलियन ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			मई 25	अप्रैल 26		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	28,858	26,446	28,352	28,140	-2.5	6.4
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	418	394	419	414	-0.9	4.9
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	1,571	1,499	1,540	1,517	-3.4	1.2
1.2.1 चीनी	297	268	305	296	-0.4	10.4
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	213	208	209	201	-5.7	-3.3
1.2.3 चाय	50	50	51	50	1.1	0.4
1.2.4 अन्य	1,010	973	974	970	-4.0	-0.3
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	147	146	130	138	-5.6	-5.1
1.4 वस्त्र	2,035	2,038	1,993	1,945	-4.5	-4.6
1.4.1 सूती वस्त्र	977	1,018	955	933	-4.5	-8.3
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	21	23	21	22	1.5	-6.0
1.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	267	235	265	257	-4.0	9.4
1.4.4 अन्य वस्त्र	770	762	752	733	-4.7	-3.8
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	111	112	111	111	-0.1	-1.3
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	120	110	116	116	-2.9	5.4
1.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	303	299	301	301	-0.9	0.6
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	631	639	549	526	-16.7	-17.7
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	1,915	1,612	1,776	1,760	-8.1	9.2
1.9.1 उर्वरक	400	296	328	340	-15.2	14.8
1.9.2 औषधि और दवाइयाँ	505	491	499	485	-4.0	-1.2
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	467	371	412	398	-14.9	7.3
1.9.4 अन्य	542	455	537	538	-0.8	18.4
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	458	419	454	458	-0.0	9.3
1.11 कांच और कांच के सामान	99	89	98	99	-0.2	11.4
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	557	530	553	555	-0.3	4.8
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	3,716	3,980	3,553	3,516	-5.4	-11.7
1.13.1 लोहा और स्टील	2,829	3,093	2,700	2,665	-5.8	-13.9
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	887	887	853	851	-4.0	-4.0
1.14 सभी अभियांत्रिकी	1,686	1,514	1,664	1,652	-2.1	9.1
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	379	338	381	374	-1.1	10.6
1.14.2 अन्य	1,308	1,176	1,283	1,277	-2.3	8.6
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	799	720	778	788	-1.3	9.5
1.16 रत्न और आभूषण	720	701	667	657	-8.8	-6.4
1.17 निर्माण	995	902	984	974	-2.1	8.0
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	10,559	8,839	10,647	10,419	-1.3	17.9
1.18.1 पावर	5,690	5,142	5,698	5,567	-2.2	8.3
1.18.2 दूरसंचार	1,156	864	1,297	1,239	7.2	43.3
1.18.3 सड़क	1,869	1,638	1,862	1,863	-0.3	13.7
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,845	1,194	1,790	1,750	-5.1	46.6
1.19 अन्य उद्योग	2,020	1,904	2,019	2,195	8.7	15.3

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2018-19	2018		2019					
		अप्रैल, 27	फरवरी, 15	फरवरी, 22	मार्च, 01	मार्च, 15	मार्च, 29	अप्रैल, 12	अप्रैल, 26
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	31	32	32	31	32	32	31	31	31
1 कुल जमा राशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	613.7	583.8	587.8	610.2	619.0	614.7	613.7	625.0	618.1
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	180.2	166.0	199.7	182.0	191.2	187.3	180.2	176.8	179.7
2.1.1 जमा राशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	58.4	44.3	51.3	44.6	57.6	55.4	58.4	46.6	52.6
2.1.1.2 अन्य	95.9	93.4	95.4	100.8	100.3	97.9	95.9	101.7	96.6
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	2.6	4.4	4.6	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	25.9	25.8	48.6	31.9	30.8	31.5	25.9	28.6	30.5
2.2 मीयादी देयताएं	979.1	935.8	926.6	939.5	963.8	963.9	979.1	1004.6	983.8
2.2.1 जमा राशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	454.8	429.8	426.1	423.1	438.1	437.6	454.8	474.4	455.7
2.2.1.2 अन्य	517.8	490.5	492.4	509.4	518.7	516.8	517.8	523.3	521.5
2.2.2 बैंकों से उधार	0.0	6.6	1.0	0.4	0.1	2.6	0.0	0.0	0.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	6.6	8.9	7.1	6.5	6.9	6.9	6.6	6.9	6.6
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	503.8	439.0	503.4	506.8	510.5	499.2	503.8	478.2	469.5
4.1 मांग	168.3	144.2	167.1	174.7	170.0	160.3	168.3	153.7	151.9
4.2 मीयादी	335.5	294.7	336.3	332.1	340.5	338.8	335.5	324.5	317.7
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	57.1	53.0	48.2	48.9	50.8	49.5	57.1	50.6	54.4
5.1 उपलब्ध नकदी	3.1	2.9	3.1	2.9	3.3	3.2	3.1	2.6	2.9
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	54.0	50.0	45.1	46.0	47.5	46.4	54.0	48.0	51.5
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	15.0	8.6	11.2	12.1	12.1	11.0	15.0	8.6	8.9
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	307.0	320.3	312.3	307.3	317.9	313.7	307.0	311.6	313.5
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	161.9	199.8	168.7	252.0	177.3	167.3	161.9	167.1	144.0
9 बैंक ऋण (10.1+11)	597.9	555.5	593.0	590.3	588.6	592.6	597.9	620.6	627.6
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	597.9	555.5	593.0	590.2	588.6	592.6	597.9	620.6	627.6
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	826.1	712.2	806.6	810.9	816.7	812.8	826.1	807.7	804.4
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2018-19			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	मई 18	अप्रैल 19	मई 19	मई 18	अप्रैल 19	मई 19	मई 18	अप्रैल 19	मई 19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	139.5	138.4	139.1	139.1	138.0	139.2	136.4	141.7	143.8	138.1	139.4	140.9
1.1 अनाज और उत्पाद	137.7	137.2	137.5	137.4	137.1	137.4	135.0	140.0	140.4	136.6	138.0	138.3
1.2 मांस और मछली	149.5	147.5	148.8	145.7	156.2	159.5	148.2	153.7	156.7	146.6	155.3	158.5
1.3 अंडा	137.3	137.3	137.3	135.5	134.7	134.6	130.5	139.4	138.3	133.6	136.5	136.0
1.4 दूध और उत्पाद	142.7	141.3	142.2	142.9	142.4	142.7	140.7	141.9	142.4	142.1	142.2	142.6
1.5 तेल और चर्बी	124.0	117.6	121.6	123.6	124.0	124.1	116.4	118.4	118.6	121.0	121.9	122.1
1.6 फल	146.8	143.4	145.2	157.5	143.8	143.8	151.3	148.6	149.7	154.6	146.0	146.6
1.7 सब्जी	141.4	142.1	141.6	137.8	129.3	133.4	131.4	150.2	161.6	135.6	136.4	143.0
1.8 दाल और उत्पाद	124.1	115.3	121.1	127.2	122.9	125.1	112.8	121.7	124.4	122.3	122.5	124.9
1.9 चीनी और उत्पाद	111.9	110.8	111.5	111.8	108.4	109.3	105.3	110.4	111.2	109.6	109.1	109.9
1.10 मसाले	138.8	140.7	139.4	137.4	138.7	139.2	139.6	140.4	141.0	138.1	139.3	139.8
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	134.9	127.5	131.8	132.2	137.5	137.7	126.6	128.7	128.9	129.9	133.8	134.0
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	155.3	151.3	153.4	154.3	156.3	156.4	148.7	154.2	154.5	151.7	155.3	155.5
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	159.4	162.9	160.4	157.0	162.9	163.3	160.3	165.7	166.2	157.9	163.6	164.1
3 कपड़ा और जूते	150.3	139.3	145.9	149.8	150.1	150.7	137.0	142.0	142.2	144.7	146.9	147.3
3.1 कपड़ा	151.2	141.0	147.2	150.8	150.8	151.3	138.6	143.9	144.1	146.0	148.1	148.5
3.2 जूते	145.2	129.5	138.7	144.1	146.3	146.6	127.9	131.3	131.7	137.4	140.1	140.4
4 आवास	--	145.6	145.6	--	--	--	143.2	149.7	150.1	143.2	149.7	150.1
5 ईंधन और लाइट	147.0	129.3	140.3	144.3	146.6	146.9	124.7	129.1	129.4	136.9	140.0	140.3
6 विविध	138.6	131.1	134.9	135.1	142.6	142.9	128.9	133.1	133.3	132.1	138.0	138.2
6.1 घरेलू सामान और सेवा	145.9	134.8	140.6	141.8	149.4	149.5	132.5	136.9	137.2	137.4	143.5	143.7
6.2 स्वास्थ्य	143.5	135.5	140.5	138.4	150.9	151.3	132.0	139.5	139.8	136.0	146.6	146.9
6.3 परिवहन और संचार	128.5	120.3	124.2	126.4	130.2	130.2	119.8	120.2	120.1	122.9	124.9	124.9
6.4 मनोरंजन	140.4	130.3	134.7	136.8	144.9	145.9	128.0	133.8	134.0	131.8	138.6	139.2
6.5 शिक्षा	149.4	144.5	146.5	144.4	156.3	156.7	140.4	147.7	148.0	142.1	151.3	151.6
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	132.6	129.9	131.5	131.2	133.7	133.9	128.1	132.4	132.6	129.9	133.2	133.4
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	141.3	137.7	139.6	139.8	141.7	142.4	135.4	140.6	141.5	137.8	141.2	142.0

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2018-19	2018		2019	
				मई	अप्रैल	मई	
	1	2	3	4	5	6	
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	300	289	312	314	
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	907	891	932	940	
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	915	899	939	948	

स्रोत : श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2018-19	2018	2019	
			मई	अप्रैल
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	31,193	31,116	31,659	31,738
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	38,404	39,716	37,328	36,590

स्रोत : मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018		2019	
			मई	मार्च	अप्रैल (अ)	मई (अ)
1 सभी पण्य	100.000	119.8	118.3	119.9	120.9	121.2
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	134.2	131.4	134.5	139.2	139.5
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	143.7	140.3	144.5	150.1	150.1
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	146.7	140.8	153.4	153.5	154.3
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	147.3	141.1	141.8	164.7	161.5
1.1.1.3 दूध	4.440	143.1	141.8	143.2	143.3	143.4
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	138.0	136.6	140.9	141.7	144.3
1.1.1.5 मसाले	0.529	129.6	128.4	125.7	127.4	132.3
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.4	144.2	147.7	149.6	148.5
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	123.1	120.3	123.7	126.7	127.8
1.1.2.1 फाइबर	0.839	127.0	118.5	127.6	133.7	134.2
1.1.2.2 तिलहन	1.115	140.5	137.8	145.5	147.8	147.8
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	107.3	109.4	102.3	102.8	103.6
1.1.2.4 फूल	0.204	164.1	137.6	194.9	211.6	225.1
1.1.3 खनिज	0.833	136.5	129.6	138.0	144.0	138.0
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	123.0	114.9	124.9	133.0	124.9
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.5	181.2	183.7	182.4	183.7
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	92.4	95.1	88.2	89.7	92.8
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	104.1	102.4	102.5	102.8	103.4
1.2.1 कोल	2.138	123.3	123.0	123.6	123.6	123.6
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	132.9	132.0	133.9	133.9	133.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	120.3	120.0	121.2	121.2	121.2
1.2.2 खनिज तेल	7.950	96.7	93.6	95.0	95.4	96.4
1.2.3 बिजली	3.064	109.6	110.7	107.3	107.3	107.3
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	117.9	116.9	118.3	118.3	118.4
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	128.6	127.2	128.4	128.7	129.2
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	136.7	137.0	134.2	135.4	135.6
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	132.1	126.2	131.2	132.4	134.3
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	116.3	111.2	112.2	113.8
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	117.6	120.0	113.7	113.2	113.2
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	136.2	138.5	134.5	134.6	135.9
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	141.6	137.7	144.3	143.7	143.3
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	116.6	110.6	131.7	133.3	135.6
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	129.3	127.5	131.2	131.2	131.3
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	111.2	104.0	111.9	112.8	115.0
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.7	123.6	126.9	128.3	127.8
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	134.5	128.3	135.1	133.1	137.8
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	137.7	138.6	131.2	142.1	139.0
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	122.2	119.3	125.8	125.3	126.3
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.0	125.8	129.4	129.3	128.3
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.6	137.6	156.6	158.3	156.9
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	157.5	152.3	161.5	160.5	163.7
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	120.7	119.2	122.0	122.7	122.5
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.8	111.9	115.1	115.8	115.6
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	120.5	118.3	122.1	121.8	123.4
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	131.2	130.8	132.1	133.5	132.0
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	150.4	149.8	153.8	154.6	152.1
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	150.4	149.8	153.8	154.6	152.1
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.9	115.7	118.6	119.4	119.7
1.3.4.1 धागों की कलाई और वस्त्र तैयार करना	2.582	110.6	108.4	110.4	111.2	111.2
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	127.3	125.4	129.6	130.2	130.9
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	112.9	111.6	110.6	111.6	114.4
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	130.3	125.7	134.8	135.1	134.8
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	138.7	137.1	135.5	138.9	139.7
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	118.3	115.9	116.2	116.9	116.6
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.8	139.8	138.3	138.5	139.2
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.4	139.9	138.9	139.1	140.5
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	137.0	139.5	136.7	136.8	136.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2018-19	2018		2019	
			मई	मार्च	अप्रैल (अ)	मई (अ)
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	121.8	122.3	120.6	120.8	119.7
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	111.0	115.8	106.7	108.2	106.0
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	134.7	133.8	133.4	133.6	135.6
1.3.6.3 जुते चप्पल	0.318	123.5	122.5	123.8	123.4	122.0
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और काँक के उत्पाद	0.772	133.5	133.4	135.1	133.6	134.3
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	124.5	123.7	126.2	125.6	126.5
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॉमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड	0.493	136.3	135.3	136.7	134.7	135.4
1.3.7.3 बिल्डरों की बड़ईगीरी	0.036	158.7	157.4	171.5	171.6	174.6
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	124.1	128.5	127.0	126.1	126.0
1.3.8 कागज और कागज के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	123.3	121.6	123.8	123.7	123.5
1.3.8.1 लुगदी, कागज और कागज बोर्ड	0.493	129.3	126.0	130.5	129.8	128.9
1.3.8.2 लहरदार कागज और पेपर बोर्ड और कागज के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.5	116.4	115.3	115.8	115.7
1.3.8.3 कागज की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	120.6	119.9	121.7	122.0	122.9
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	146.6	146.3	146.1	147.5	148.3
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	146.6	146.3	146.1	147.5	148.3
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	119.1	117.4	119.6	119.7	119.7
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	125.0	122.4	125.3	125.5	124.9
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	121.1	118.8	123.0	122.7	123.1
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	117.6	118.1	115.5	116.9	115.5
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रीकेमिकल उत्पाद	0.454	120.2	118.2	122.8	122.9	124.2
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	112.7	112.0	113.8	114.7	115.2
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	116.8	114.5	119.4	119.4	119.6
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	116.6	114.7	115.9	115.6	115.8
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.0	103.1	102.7	100.7	101.0
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	123.5	122.3	126.4	124.4	125.5
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	123.5	122.3	126.4	124.4	125.5
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	109.6	108.5	110.1	110.3	109.2
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	97.4	99.3	100.5	99.5
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.7	90.2	92.7	92.8	92.5
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	117.6	116.8	118.0	117.9	116.6
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	115.9	115.6	116.6	116.8	118.4
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	121.4	118.5	125.0	125.3	126.0
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	111.1	110.5	110.4	108.0	107.7
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	98.0	101.4	98.1	99.5	101.4
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.7	112.5	114.4	114.5	114.5
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	114.3	114.4	117.3	119.2	122.0
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.5	121.8	122.0	121.1	120.8
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	118.8	117.9	119.7	120.1	119.9
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	130.4	129.0	105.2	94.4	95.2
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	112.2	112.2	111.1	110.6	109.7
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	113.0	111.6	108.3	106.3	105.7
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	117.8	119.6	114.3	114.9	114.0
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.5	99.8	98.1	98.1	96.7
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	110.2	109.8	110.1	109.7	109.4
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	119.6	120.5	117.3	116.4	115.3
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	111.7	111.7	111.6	110.5	109.5
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	112.7	116.4	109.7	109.6	109.7
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.6	123.4	128.1	127.2	127.1
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.2	114.1	110.6	110.2	109.2
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.8	106.1	114.9	114.8	111.5
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	126.8	118.5	138.3	140.1	141.6
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.1	112.6	116.8	117.2	116.9
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	112.8	109.5	115.0	115.6	115.3
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	127.3	125.3	126.1	126.8	126.3
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरस को छोड़कर	0.145	105.9	108.5	104.8	104.8	102.6
1.3.15.4 धातु की फोजिंग, दबाना, स्टेपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.3	92.1	103.9	103.1	102.3
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	99.7	99.5	100.1	100.0	100.1
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	123.1	120.6	124.9	125.7	126.1
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	111.8	111.3	111.4	111.0	111.4
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	100.9	102.6	98.8	98.8	98.7
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	132.5	127.3	135.0	135.0	135.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2018-19	2018		2019	
			मई	मार्च	अप्रैल (अ)	मई (अ)
			1	2	3	4
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	116.7	116.3	116.3	116.3	116.6
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.8	103.6	102.8	101.7	102.0
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	109.1	111.4	108.4	109.0	111.9
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.9	137.4	139.7	136.6	136.6
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.2	102.0	102.5	102.5	105.3
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.7	111.8	107.4	108.9	109.2
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	111.7	110.8	112.3	112.0	112.0
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	107.7	105.6	109.1	109.3	109.6
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.7	117.3	116.8	117.6	117.5
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	126.1	126.0	125.8	119.0	118.0
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	111.2	110.6	111.0	110.9	110.2
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.6	109.2	109.8	109.5	110.0
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.6	122.8	120.3	120.2	120.4
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	107.0	109.7	108.9	108.5
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	111.3	109.9	112.3	112.1	112.7
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	103.0	101.1	104.5	105.1	105.5
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	118.2	117.2	118.5	117.6	119.3
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.9	108.7	109.3	109.1	110.2
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.2	112.5	109.6	110.6	109.9
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां	0.008	78.2	79.6	77.7	77.9	79.3
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने - उतारने वाले उपकरण	0.285	110.4	109.8	111.8	112.0	111.9
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	129.6	128.6	128.3	128.1	128.6
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	116.9	114.2	119.4	118.9	119.2
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	101.8	97.5	105.0	104.9	107.2
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	73.8	77.1	77.2	76.8
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.7	121.5	124.5	121.6	123.9
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.9	120.2	120.3	118.8	121.8
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	123.8	123.2	126.6	125.6	125.8
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	67.3	68.8	66.6	66.6	66.6
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रैलरों और अर्ध-ट्रैलरों का विनिर्माण	4.969	112.8	112.1	112.9	113.0	113.3
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.3	112.4	113.0	113.6	113.7
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	112.2	111.7	112.8	112.4	112.9
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	111.7	110.4	113.3	113.4	114.8
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली - वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	104.7	105.2	105.8	105.8	106.2
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	106.6	105.2	108.3	108.4	110.3
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	127.8	124.7	130.3	129.9	128.7
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	123.5	121.6	124.7	124.7	125.0
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	127.3	126.2	129.5	129.3	129.4
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	127.3	126.2	129.5	129.3	129.4
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	107.0	106.9	107.3	106.4	106.3
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	103.9	103.8	104.2	103.3	103.1
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.1	178.7	177.5	170.4	173.0
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	127.4	126.5	126.4	126.4	127.0
1.3.22.4 खेल और खिलाड़ियों	0.005	132.2	131.7	135.2	135.7	136.1
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	159.2	160.0	160.9	160.9	160.9
2 खाद्य सूचकांक	24.378	138.1	135.4	138.5	142.1	142.3

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारंक	2017-18	2018-19	अप्रैल	
				2018	2019
	1	2	3	4	5
सामान्य सूचकांक	100.00	125.3	129.8	122.6	126.8
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण					
1.1 खनन	14.37	104.9	107.9	102.6	107.8
1.2 विनिर्माण	77.63	126.6	131.0	123.1	126.6
1.3 बिजली	7.99	149.2	156.9	153.7	162.9
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण					
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	121.8	126.1	119.7	125.9
2.2 पूंजीगत माल	8.22	105.6	108.6	97.6	100.0
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	125.1	124.5	120.1	121.3
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	132.0	141.9	135.9	138.2
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	123.6	130.4	124.4	127.4
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	139.9	145.3	132.8	139.7

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - मई			
	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वर्तमान)	2018-19 (वर्तमान)	बजट अनुमान का प्रतिशत	
				2019-20	2018-19
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्ति	19,776.9	1,437.6	1,264.6	7.3	7.3
1.1 कर राजस्व (निवल)	17,050.5	1,153.4	1,024.1	6.8	6.9
1.2 करेतर राजस्व	2,726.5	284.2	240.5	10.4	9.8
2 पूंजीगत प्राप्ति	1,025.1	30.7	10.0	3.0	1.1
2.1 ऋण की वसूली	125.1	7.1	5.7	5.7	4.7
2.2 अन्य प्राप्ति	900.0	23.6	4.3	2.6	0.5
3 कुल प्राप्ति (1+2)	20,802.0	1,468.3	1,274.6	7.1	7.0
4 राजस्व व्यय					
4.1 ब्याज भुगतान	24,479.1	4,652.8	4,091.6	19.0	19.1
5 पूंजी व्यय	6,650.6	748.0	736.1	11.2	12.8
6 कुल व्यय (4+5)	3,362.9	477.0	637.9	14.2	21.2
7 राजस्व घाटा (4-1)	27,842.0	5,129.9	4,729.5	18.4	19.4
8 राजकोषीय घाटा {6-(1+2)}	4,702.1	3,215.2	2,827.1	68.4	68.0
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	7,040.0	3,661.6	3,454.9	52.0	55.3
	389.4	2,913.5	2,718.9	748.2	560.8

स्रोत : महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और यूनिन बजट 2018-19।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(बिलियन ₹)

मद	2018-19	2018		2019				
		मई 25	अप्रैल 26	मई 3	मई 10	मई 17	मई 24	मई 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	185.2	534.9	228.7	261.0	248.8	247.1	248.9	245.8
1.2 प्राथमिक व्यापारी	178.8	177.1	165.7	189.2	211.3	186.7	182.1	218.7
1.3 राज्य सरकारें	270.0	634.7	291.1	301.1	391.1	491.1	551.1	521.1
1.4 अन्य	277.5	332.9	448.8	442.9	481.5	557.7	609.6	627.0
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	319.5	293.8	406.6	438.3	432.6	414.9	409.7	419.1
2.2 प्राथमिक व्यापारी	387.4	343.1	455.2	458.9	491.9	520.9	554.5	556.2
2.3 राज्य सरकारें	280.4	240.3	209.5	219.5	209.4	209.2	209.2	209.2
2.4 अन्य	185.7	216.5	150.8	145.8	149.6	169.4	170.6	190.0
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	488.1	323.9	526.5	518.6	511.2	509.8	491.6	474.4
3.2 प्राथमिक व्यापारी	741.7	708.1	784.9	788.6	843.0	842.9	867.4	884.5
3.3 राज्य सरकारें	188.9	142.1	201.6	187.1	187.1	187.1	187.1	187.1
3.4 अन्य	623.9	485.2	535.7	540.5	492.9	495.6	489.8	493.2
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 प्राथमिक व्यापारी	—	—	—	—	—	—	—	—
4.3 राज्य सरकारें	1,656.1	1,673.6	1,464.3	1,469.0	1,147.0	1,003.7	1,436.5	1,309.1
4.4 अन्य	2.5	7.1	5.2	5.1	5.2	3.6	3.3	4.5
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	4,127.0	4,432.7	4,405.1	4,491.4	4,650.4	4,832.4	4,971.5	5,026.4

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि बिलियन ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)		
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या				कुल अंकित मूल्य	
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2019-20										
अप्रैल 30	90	32	156.36	26.00	21	90.00	26.00	116.00	98.42	6.4391
मई 8	90	60	433.88	94.02	46	89.98	94.02	184.00	98.41	6.4805
मई 15	90	57	496.40	108.03	42	89.97	108.03	198.00	98.43	6.3977
मई 22	90	59	488.70	76.31	45	89.99	76.31	166.30	98.44	6.3563
मई 29	90	77	963.80	30.02	22	89.98	30.02	120.00	98.48	6.1908
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2019-20										
अप्रैल 30	70	46	185.72	10.00	18	70.00	10.00	80.00	96.86	6.5014
मई 8	70	47	194.07	0.00	22	70.00	0.00	70.00	96.86	6.5014
मई 15	70	46	243.60	0.03	27	69.97	0.03	70.00	96.88	6.4587
मई 22	70	56	281.75	0.00	22	70.00	0.00	70.00	96.91	6.3946
मई 29	70	56	194.05	0.00	24	70.00	0.00	70.00	96.97	6.2665
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2019-20										
अप्रैल 30	40	53	134.35	—	22	40.00	—	40.00	93.90	6.5141
मई 8	40	38	96.73	0.00	15	40.00	0.00	40.00	93.88	6.5369
मई 15	40	61	195.42	0.00	16	40.00	0.00	40.00	93.94	6.4686
मई 22	40	59	161.91	0.02	13	39.98	0.02	40.00	93.99	6.4119
मई 29	40	53	155.70	0.09	14	39.91	0.09	40.00	94.09	6.2985

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
मई	2, 2019	4.50-6.25	6.06
मई	3, 2019	4.50-6.25	6.02
मई	4, 2019	4.20-5.95	5.46
मई	6, 2019	4.50-6.25	5.94
मई	7, 2019	4.50-6.95	5.94
मई	8, 2019	4.50-6.05	5.96
मई	9, 2019	4.50-6.15	5.98
मई	10, 2019	4.50-6.10	5.95
मई	13, 2019	4.50-6.25	5.92
मई	14, 2019	4.50-6.15	5.91
मई	15, 2019	4.50-6.10	5.95
मई	16, 2019	4.50-6.05	5.96
मई	17, 2019	4.50-6.15	5.99
मई	20, 2019	4.50-6.10	5.96
मई	21, 2019	4.50-6.15	5.94
मई	22, 2019	4.50-6.20	5.94
मई	23, 2019	4.50-6.10	5.90
मई	24, 2019	4.50-6.15	5.88
मई	27, 2019	4.50-6.05	5.94
मई	28, 2019	4.50-6.30	5.87
मई	29, 2019	4.50-6.05	5.87
मई	30, 2019	4.50-6.05	5.92
मई	31, 2019	4.50-6.25	5.91
जून	1, 2019	4.50-6.00	5.58
जून	3, 2019	4.50-6.00	5.85
जून	4, 2019	4.50-6.00	5.87
जून	6, 2019	4.40-6.00	5.85
जून	7, 2019	4.40-5.80	5.69
जून	10, 2019	4.40-5.80	5.69
जून	11, 2019	4.40-5.80	5.70
जून	12, 2019	4.40-5.80	5.69
जून	13, 2019	4.40-5.85	5.69
जून	14, 2019	4.40-6.12	5.81
जून	15, 2019	4.60-6.00	5.59

टिप्पणी : नोटिस मुद्रा सहित।

सं. 27: जमा प्रमाणपत्र

मद	2018	2019			
	मई 25	अप्रैल 12	अप्रैल 26	मई 10	मई 24
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	2,052.2	2,617.3	2,254.8	2,494.8	2,271.5
1.1 परखवाड़े के दौरान जारी (बिलियन ₹)	172.0	145.5	45.8	66.2	139.4
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	7.43-8.50	6.45-8.50	6.65-7.33	7.30-8.60	6.72-7.90

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2018	2019			
	मई 31	अप्रैल 15	अप्रैल 30	मई 15	मई 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	4,668.9	5,736.0	5,428.9	5,837.2	5,519.8
1.1 परखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (बिलियन ₹)	850.2	1,292.1	712.1	1,059.7	1,024.5
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.89-9.84	6.41-9.98	6.67-13.14	6.81-13.04	6.43-10.08

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(बिलियन ₹)

मद	2018-19	2018	2019					
		मई 25	अप्रैल 26	मई 3	मई 10	मई 17	मई 24	मई 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	312.8	315.6	381.3	287.1	347.9	391.2	425.0	340.8
2 नोटिस मुद्रा	49.3	4.5	6.8	127.7	8.8	3.1	4.8	74.0
3 मीयादी मुद्रा	7.4	5.1	9.0	10.4	9.0	5.5	7.8	4.8
4 सीबीएलओ/त्रिपक्षीय रिपो	2,130.1	1,784.0	2,197.7	2,770.2	2,253.6	2,708.7	2,713.2	2,757.3
5 बाजार रिपो	2,009.7	1,812.5	1,589.3	2,174.7	1,958.1	2,185.4	1,985.5	2,334.4
6 कार्पोरेट बांड में रिपो		8.2	45.5	36.4	6.6	1.8	19.5	29.5
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67,793	64,600	76,959	73,393	59,113	59,697	64,867	65,606
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	658	511.6	602.2	401.9	616.6	718.9	908.2	1,091.7
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	43.2	27.0	61.8	51.9	43.6	50.3	58.0	98.9
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	33.8	25.7	38.8	15.9	35.6	40.9	37.4	28.2
10.2 182-दिवसीय	14.5	6.9	29.5	15.0	15.1	9.9	17.8	39.7
10.3 364-दिवसीय	16.2	12.1	16.5	11.2	8.3	27.3	29.4	41.4
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	14	—	—	—	—	—	—	—
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	779.7	583.3	748.7	495.9	719.2	847.3	1,050.8	1,300.0
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	—	3.8	2.1	62.6	1.2	27.6	2.8	2.7

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि बिलियन ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2018-19		2018-19 (अप्रैल-मई)		2019-20 (अप्रैल-मई)*		मई 2018		मई 2019 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	129	167.5	34	25.7	16	522.3	20	22.3	7	244.8
1ए प्रीमियम	124	160.8	33	24.4	16	310.4	20	21.3	7	233.3
1.1 पब्लिक	119	146.1	32	24.2	12	28.5	20	22.3	5	1.1
1.1.1 प्रीमियम	115	141.2	31	22.9	12	27.9	20	21.3	5	0.9
1.2 राइट्स	10	21.5	2	1.5	4	493.8	—	—	2	243.7
1.2.1 प्रीमियम	9	19.6	2	1.5	4	282.5	—	—	2	232.4
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 डिबेंचर	25	366.8	5	154.2	9	32.4	3	122.1	4	10.5
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	25	366.8	5	154.2	9	32.4	3	122.1	4	10.5
3.1.1 पब्लिक	25	366.8	5	154.2	9	32.4	3	122.1	4	10.5
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 कुल (1+2+3+4)	154	534.3	39	179.8	25	554.7	23	144.3	11	255.3
5.1 पब्लिक	144	512.8	37	178.4	21	60.9	23	144.3	9	11.5
5.2 राइट्स	10	21.5	2	1.5	4	493.8	—	—	2	243.7

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

टिप्पणी : अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2018-19	2018		2019			
		1	मई	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई
			2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	बिलियन ₹	23,039.0	1,949.3	1,863.3	1,902.9	2,264.6	1,810.0	2,092.8
	अमेरिकी मिलियन डालर	329,536.2	28,861.4	26,342.1	26,717.6	32,594.5	26,070.1	29,994.5
1.1 तेल	बिलियन ₹	3,248.2	353.8	224.6	217.7	248.5	255.1	360.3
	अमेरिकी मिलियन डालर	46,397.4	5,237.8	3,175.8	3,056.3	3,576.2	3,674.6	5,164.2
1.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	19,790.8	1,595.5	1,638.6	1,685.2	2,016.2	1,554.9	1,732.5
	अमेरिकी मिलियन डालर	283,138.8	23,623.6	23,166.3	23,661.3	29,018.3	22,395.5	24,830.2
2 आयात	बिलियन ₹	35,876.8	2,936.6	2,907.2	2,583.5	3,018.1	2,874.4	3,164.5
	अमेरिकी मिलियन डालर	513,085.9	43,479.9	41,100.8	36,273.6	43,439.9	41,401.1	45,354.0
2.1 तेल	बिलियन ₹	9,860.2	776.5	796.0	670.5	816.1	789.9	868.2
	अमेरिकी मिलियन डालर	140,883.8	11,497.6	11,253.1	9,414.0	11,746.0	11,377.8	12,443.5
2.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	26,016.6	2,160.1	2,111.2	1,913.0	2,202.0	2,084.4	2,296.3
	अमेरिकी मिलियन डालर	372,202.1	31,982.3	29,847.7	26,859.6	31,693.9	30,023.3	32,910.5
3 व्यापार शेष	बिलियन ₹	-12,837.9	-987.3	-1,043.9	-680.6	-753.5	-1,064.4	-1,071.7
	अमेरिकी मिलियन डालर	-183,549.7	-14,618.4	-14,758.7	-9,556.0	-10,845.4	-15,330.9	-15,359.5
3.1 तेल	बिलियन ₹	-6,612.0	-422.8	-571.3	-452.8	-567.6	-534.8	-507.9
	अमेरिकी मिलियन डालर	-94,486.4	-6,259.8	-8,077.3	-6,357.7	-8,169.8	-7,703.2	-7,279.3
3.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	-6,225.9	-564.5	-472.6	-227.8	-185.9	-529.6	-563.8
	अमेरिकी मिलियन डालर	-89,063.3	-8,358.6	-6,681.4	-3,198.3	-2,675.5	-7,627.8	-8,080.3

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2018	2019						
		1	जून 22	मई 17	मई 24	May 31	जून 7	जून 14	जून 21
			2	3	मई 31	5	6	7	
1 कुल भंडार	बिलियन ₹	27,619	29,322	29,241	29,449	29,365	29,376	29,697	
	अमेरिकी मिलियन डालर	407,816	417,998	419,992	421,868	423,554	422,200	426,416	
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	बिलियन ₹	25,910	27,379	27,300	27,513	27,430	27,440	27,760	
	अमेरिकी मिलियन डालर	382,500	390,197	392,189	394,135	395,801	394,447	398,649	
1.2 स्वर्ण	बिलियन ₹	1,439	1,608	1,608	1,603	1,603	1,603	1,603	
	अमेरिकी मिलियन डालर	21,332	23,022	23,022	22,959	22,959	22,959	22,959	
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1,057	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	
	बिलियन ₹	101	101	101	101	100	101	101	
	अमेरिकी मिलियन डालर	1,492	1,445	1,445	1,443	1,449	1,449	1,453	
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	बिलियन ₹	169	234	232	233	232	233	234	
	अमेरिकी मिलियन डालर	2,493	3,335	3,337	3,331	3,345	3,345	3,355	

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(अमेरिकी मिलियन डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2018-19	2018	2019		2018-19	2019-20
		मई	अप्रैल	मई	अप्रैल-मई	अप्रैल-मई
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130,423	123,484	130,912	131,886	2,263	2,441
1.1 एफसीएनआर (बी)	23,170	22,246	24,580	24,323	220	1,153
1.2 एनआर (ई) आरए	92,017	87,482	91,282	92,192	1,736	1,015
1.3 एनआरओ	15,236	13,756	15,050	15,370	307	273

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	2018-19	2018-19	2019-20	2018	2019	
		अप्रैल-मई	अप्रैल-मई	मई	अप्रैल	मई
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	30,712	7,928	6,836	3,668	4,676	2,160
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.1.2)	43,302	10,111	8,859	4,637	5,503	3,355
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	62,001	12,666	12,357	5,915	7,252	5,104
1.1.1.1.1 ईक्विटी	45,055	9,970	9,156	4,567	5,306	3,850
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	2,429	1,305	271	893	63	208
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	36,315	8,065	7,564	3,380	4,584	2,979
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	5,622	490	1,212	239	604	608
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	689	108	108	54	54	54
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	13,672	2,152	2,152	1,076	1,076	1,076
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3,274	545	1,049	272	870	179
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	18,699	2,556	3,498	1,278	1,749	1,749
1.1.1.2.1 ईक्विटी	18,452	2,547	3,486	1,274	1,743	1,743
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	247	8	12	4	6	6
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	12,590	2,183	2,023	970	827	1,195
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	7,201	1,414	838	553	306	533
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3,032	505	505	253	253	253
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5,202	447	903	256	381	522
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	2,845	184	224	92	112	112
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	-618	-4,264	-966	-1,373	-1,643	677
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	1,820	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	-2,225	-4,904	2,270	-1,694	-25	2,295
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	213	-640	3,236	-320	1,618	1,618
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	30,094	3,664	5,871	2,294	3,033	2,838

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	2018-19	2018	2019		
		मई	मार्च	अप्रैल	मई
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	13,787.6	996.1	1,476.8	1,287.9	1,486.1
1.1 जमाराशियां	455.9	31.0	100.6	65.2	50.2
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	84.5	8.2	10.5	8.5	9.4
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	422.9	26.5	74.4	35.4	31.6
1.4 उपहार	1,370.2	118.6	161.0	166.6	154.2
1.5 दान	8.7	0.2	0.3	0.5	2.8
1.6 यात्रा	4,803.8	364.7	429.2	429.8	568.3
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,800.9	248.8	322.9	296.1	300.0
1.8 चिकित्सा उपचार	28.6	2.1	2.5	2.5	2.5
1.9 विदेश में शिक्षा	3,569.9	178.0	333.8	252.8	334.4
1.10 अन्य	242.2	17.9	41.6	30.5	32.7

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2017-18	2018-19	2018	2019	
			जून	मई	जून
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	76.94	72.64	73.94	74.11	74.23
1.2 रीर	119.71	114.01	115.94	115.86	116.04
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	78.89	74.18	75.71	75.57	75.75
2.2 रीर	121.94	116.32	118.53	118.25	118.54
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	67.91	63.07	64.10	64.23	64.45
1.2 रीर	129.19	121.70	123.18	125.15	124.55
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	92.88	94.40	94.58	94.91
2.2 रीर	100.00	94.20	95.35	96.87	96.41

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार — पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)

मद	2017-18	2018	2019	
		मई	अप्रैल	मई
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	769	84	108	117
1.2 राशि	20,397	1,347	2,658	2,895
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	38	-	1	5
2.2 राशि	8,471	-	500	653
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	807	84	109	122
3.2 राशि	28,868	1,347	3,158	3,548
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.10	3.10	4.70	5.40
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.34	1.11	1.31	1.35
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-12.25	0.00-13.88	0.00-11.50	0.00-11.50

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	जनवरी-मार्च 2018 (आं.सं)			जनवरी-मार्च 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	329,455	316,218	13,237	324,141	309,979	14,162
1 चालू खाता (1.1+1.2)	156,683	169,750	-13,066	165,160	169,807	-4,647
1.1 पण्य	82,218	123,841	-41,623	87,367	122,581	-35,214
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	74,466	45,909	28,557	77,792	47,226	30,567
1.2.1 सेवाएं	51,585	31,421	20,164	54,630	33,299	21,331
1.2.1.1 यात्रा	7,710	4,728	2,983	7,583	5,112	2,470
1.2.1.2 परिवहन	4,688	4,941	-253	5,154	5,436	-282
1.2.1.3 बीमा	638	370	268	720	603	117
1.2.1.4 जीएनआईई	179	305	-126	156	285	-129
1.2.1.5 विविध	38,370	21,076	17,293	41,018	21,863	19,155
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	19,906	1,345	18,561	21,439	1,571	19,868
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	9,936	9,433	503	10,290	11,109	-820
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1,686	1,171	515	1,111	618	494
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	600	263	337	760	336	424
1.2.2 अंतरण	18,100	1,887	16,213	17,972	1,812	16,160
1.2.2.1 आधिकारिक	30	219	-190	69	226	-157
1.2.2.2 निजी	18,070	1,668	16,402	17,903	1,587	16,317
1.2.3 आय	4,781	12,601	-7,820	5,190	12,115	-6,925
1.2.3.1 निवेश आय	3,651	11,984	-8,333	4,033	11,521	-7,488
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षति पूर्ति	1,129	617	513	1,157	593	564
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	171,492	146,468	25,024	158,982	139,740	19,241
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	85,777	77,094	8,683	93,816	77,960	15,856
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	13,840	7,432	6,408	16,654	10,235	6,420
2.1.1.1 भारत में	13,097	4,492	8,605	15,461	5,671	9,790
2.1.1.1.1 इक्विटी	9,096	4,458	4,638	11,058	5,636	5,422
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3,393	-	3,393	3,650	-	3,650
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	608	34	574	753	36	718
2.1.1.2 विदेश में	743	2,941	-2,198	1,193	4,563	-3,370
2.1.1.2.1 इक्विटी	743	1,263	-520	1,193	1,683	-489
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	713	-713	0	758	-758
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	964	-964	0	2,123	-2,123
2.1.2 संविभाग निवेश	71,937	69,661	2,276	77,162	67,726	9,436
2.1.2.1 भारत में	71,802	69,427	2,376	76,807	65,338	11,469
2.1.2.1.1 एफआईआई	71,802	69,427	2,376	76,807	65,338	11,469
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	58,274	56,148	2,126	58,600	50,602	7,998
2.1.2.1.1.2 ऋण	13,528	13,279	249	18,207	14,736	3,471
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	-	0
2.1.2.2 विदेश में	135	235	-100	355	2,388	-2,033
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	40,835	33,870	6,965	31,255	20,997	10,258
2.2.1 बाह्य सहायता	2,686	1,257	1,430	2,554	1,301	1,253
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	31	-17	12	30	-18
2.2.1.2 भारत को	2,673	1,225	1,447	2,542	1,271	1,271
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	13,581	12,589	992	17,993	10,456	7,537
2.2.2.1 भारत द्वारा	6,134	6,098	36	7,291	7,000	292
2.2.2.2 भारत को	7,447	6,491	956	10,702	3,456	7,246
2.2.3 भारत को अल्पावधि	24,568	20,025	4,543	10,708	9,241	1,468
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	22,951	20,025	2,926	10,052	9,241	812
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	1,617	0	1,617	656	0	656
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	31,834	27,205	4,629	21,606	29,670	-8,064
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	31,751	27,205	4,547	20,599	29,668	-9,069
2.3.1.1 आस्तियां	7,132	10,960	-3,829	443	16,542	-16,099
2.3.1.2 देयताएं	24,620	16,244	8,375	20,156	13,127	7,029
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	20,068	15,432	4,636	14,974	11,563	3,411
2.3.2 अन्य	83	0	83	1,007	1	1,006
2.4 रुपया ऋण चुकौती	-	50	-50	-	7	-7
2.5 अन्य पूंजी	13,045	8,250	4,795	12,304	11,107	1,197
3 भूल-चूक	1,279	-	1,279	-	431	-431
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	13,237	-13,237	0	14,162	-14,162
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	13,237	-13,237	0	14,162	-14,162

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(बिलियन ₹)

मद	जनवरी-मार्च 2018 (आं.सं)			जनवरी-मार्च 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	21,198	20,347	852	22,845	21,847	998
1 चालू खाता (1.1+1.2)	10,082	10,922	-841	11,640	11,968	-328
1.1 पण्य	5,290	7,968	-2,678	6,157	8,639	-2,482
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	4,791	2,954	1,837	5,483	3,328	2,154
1.2.1 सेवाएं	3,319	2,022	1,297	3,850	2,347	1,503
1.2.1.1 यात्रा	496	304	192	534	360	174
1.2.1.2 परिवहन	302	318	-16	363	383	-20
1.2.1.3 बीमा	41	24	17	51	42	8
1.2.1.4 जीएनआईई	12	20	-8	11	20	-9
1.2.1.5 विविध	2,469	1,356	1,113	2,891	1,541	1,350
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	1,281	87	1,194	1,511	111	1,400
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	639	607	32	725	783	-58
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	108	75	33	78	44	35
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	39	17	22	54	24	30
1.2.2 अंतरण	1,165	121	1,043	1,267	128	1,139
1.2.2.1 आधिकारिक	2	14	-12	5	16	-11
1.2.2.2 निजी	1,163	107	1,055	1,262	112	1,150
1.2.3 आय	308	811	-503	366	854	-488
1.2.3.1 निवेश आय	235	771	-536	284	812	-528
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	73	40	33	82	42	40
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	11,034	9,424	1,610	11,205	9,849	1,356
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	5,519	4,961	559	6,612	5,494	1,117
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	891	478	412	1,174	721	452
2.1.1.1 भारत में	843	289	554	1,090	400	690
2.1.1.1.1 इक्विटी	585	287	298	779	397	382
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	218	0	218	257	0	257
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	39	2	37	53	3	51
2.1.1.2 विदेश में	48	189	-141	84	322	-238
2.1.1.2.1 इक्विटी	48	81	-33	84	119	-34
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	46	-46	0	53	-53
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	62	-62	0	150	-150
2.1.2 संविभाग निवेश	4,629	4,482	146	5,438	4,773	665
2.1.2.1 भारत में	4,620	4,467	153	5,413	4,605	808
2.1.2.1.1 एफआईआई	4,620	4,467	153	5,413	4,605	808
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	3,750	3,613	137	4,130	3,566	564
2.1.2.1.1.2 ऋण	870	854	16	1,283	1,039	245
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	9	15	-6	25	168	-143
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	2,628	2,179	448	2,203	1,480	723
2.2.1 बाह्य सहायता	173	81	92	180	92	88
2.2.1.1 भारत द्वारा	1	2	-1	1	2	-1
2.2.1.2 भारत को	172	79	93	179	90	90
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	874	810	64	1,268	737	531
2.2.2.1 भारत द्वारा	395	392	2	514	493	21
2.2.2.2 भारत को	479	418	62	754	244	511
2.2.3 भारत को अल्पावधि	1,581	1,288	292	755	651	103
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	1,477	1,288	188	708	651	57
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	104	0	104	46	0	46
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	2,048	1,750	298	1,523	2,091	-568
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	2,043	1,750	293	1,452	2,091	-639
2.3.1.1 आस्तियां	459	705	-246	31	1,166	-1,135
2.3.1.2 देयताएं	1,584	1,045	539	1,421	925	495
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	1,291	993	298	1,055	815	240
2.3.2 अन्य	5	0	5	71	0	71
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	3	-3	0	0	-0
2.5 अन्य पूंजी	839	531	309	867	783	84
3 भूल-चूक	82	0	82	0	30	-30
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	852	-852	0	998	-998
4.1 आईएमएफ	-	-	-	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	852	-852	0	998	-998

सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	जनवरी-मार्च 2018 (आं.सं)			जनवरी-मार्च 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	156,683	169,730	-13,047	165,158	169,786	-4,628
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	133,803	155,262	-21,459	141,998	155,880	-13,883
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	82,218	123,841	-41,623	87,367	122,581	-35,214
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	82,872	116,776	-33,904	86,579	114,412	-27,832
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-655	0	-655	788	0	788
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	-	7,065	-7,065	-	8,170	-8,170
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	51,585	31,421	20,164	54,630	33,299	21,331
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	55	13	43	78	11	67
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	60	155	-95	41	358	-317
1.अ.ख.3 परिवहन	4,688	4,941	-253	5,154	5,436	-282
1.अ.ख.4 यात्रा	7,710	4,728	2,983	7,583	5,112	2,470
1.अ.ख.5 निर्माण	535	585	-50	747	625	122
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	638	370	268	720	603	117
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1,686	1,171	515	1,111	618	494
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	212	1,704	-1,492	120	1,826	-1,706
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	20,574	1,708	18,866	22,262	2,029	20,233
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	9,936	9,433	503	10,290	11,109	-820
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	480	616	-136	451	649	-198
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	179	305	-126	156	285	-129
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	4,830	5,691	-861	5,917	4,638	1,279
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	4,781	12,601	-7,820	5,190	12,115	-6,925
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1,129	617	513	1,157	593	564
1.आ.2 निवेश आय	2,844	11,841	-8,997	3,390	11,109	-7,719
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1,337	5,968	-4,631	1,411	4,708	-3,297
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	56	2,347	-2,292	71	2,435	-2,364
1.आ.2.3 अन्य निवेश	268	3,515	-3,247	354	3,951	-3,596
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1,183	11	1,173	1,553	15	1,538
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	807	143	664	643	412	231
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	18,099	1,868	16,231	17,970	1,791	16,179
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	18,070	1,668	16,402	17,903	1,587	16,317
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	17,484	1,260	16,224	17,322	1,199	16,123
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	586	408	178	581	387	194
1.इ.2 सामान्य सरकार	29	200	-171	67	204	-138
2 पूँजी खाता (2.1+2.2)	62	105	-43	84	167	-83
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	6	5	1	14	94	-81
2.2 पूँजी अंतरण	56	100	-44	70	72	-3
3 वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	171,430	159,620	11,811	158,900	153,757	5,143
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	13,840	7,432	6,408	16,654	10,235	6,420
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	13,097	4,492	8,605	15,461	5,671	9,790
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	12,489	4,458	8,031	14,708	5,636	9,072
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	9,096	4,458	4,638	11,058	5,636	5,422
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3,393	-	3,393	3,650	-	3,650
3.1.अ.2 ऋण लिखत	608	34	574	753	36	718
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	608	34	574	753	36	718
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	743	2,941	-2,198	1,193	4,563	-3,370
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	743	1,976	-1,234	1,193	2,441	-1,247
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	743	1,263	-520	1,193	1,683	-489
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	-	713	-713	-	758	-758
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	964	-964	0	2,123	-2,123
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	-	964	-964	-	2,123	-2,123
3.2 संविभाग निवेश	71,937	69,661	2,276	77,162	67,726	9,436
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	71,802	69,427	2,376	76,807	65,338	11,469
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	58,274	56,148	2,126	58,600	50,602	7,998
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	13,528	13,279	249	18,207	14,736	3,471
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	135	235	-100	355	2,388	-2,033
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	5,010	5,114	-104	6,425	5,687	739
3.4 अन्य निवेश	80,643	64,175	16,468	58,659	55,948	2,711
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाशियां	20,151	15,432	4,719	15,981	11,564	4,417
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	83	0	83	1,007	1	1,006
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाशियां)	20,068	15,432	4,636	14,974	11,563	3,411
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	27,951	25,618	2,333	26,172	29,862	-3,690
3.4.3अ भारत को ऋण	21,803	19,489	2,313	18,869	22,832	-3,963
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	6,148	6,129	19	7,303	7,030	273
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	41	951	-910	21	364	-344
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	24,568	20,025	4,543	10,708	9,241	1,468
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	7,933	2,149	5,784	5,777	4,917	860
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	-	-	-
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	13,237	-13,237	0	14,162	-14,162
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	13,237	-13,237	0	14,162	-14,162
4 कुल आस्तियां / देयताएं	171,430	159,620	11,811	158,900	153,757	5,143
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	76,692	68,882	7,810	81,302	67,117	14,184
4.2 ऋण लिखत	86,806	75,352	11,454	71,822	67,561	4,261
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	7,933	15,386	-7,453	5,777	19,079	-13,303
5 निवल भूल-चूक	1,279	-	1,279	-	431	-431

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(बिलियन ₹)

मद	जनवरी-मार्च 2018 (आं.सं)			जनवरी-मार्च 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	10,082	10,921	-840	11,640	11,966	-326
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	8,609	9,990	-1,381	10,008	10,986	-978
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	5,290	7,968	-2,678	6,157	8,639	-2,482
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	5,332	7,514	-2,182	6,102	8,063	-1,962
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-42	0	-42	56	0	56
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	455	-455	0	576	-576
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1अ.ख.13)	3,319	2,022	1,297	3,850	2,347	1,503
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	4	1	3	6	1	5
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	4	10	-6	3	25	-22
1.अ.ख.3 परिवहन	302	318	-16	363	383	-20
1.अ.ख.4 यात्रा	496	304	192	534	360	174
1.अ.ख.5 निर्माण	34	38	-3	53	44	9
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	41	24	17	51	42	8
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	108	75	33	78	44	35
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	14	110	-96	8	129	-120
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	1,324	110	1,214	1,569	143	1,426
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	639	607	32	725	783	-58
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	31	40	-9	32	46	-14
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	12	20	-8	11	20	-9
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	311	366	-55	417	327	90
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	308	811	-503	366	854	-488
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	73	40	33	82	42	40
1.आ.2 निवेश आय	183	762	-579	239	783	-544
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	86	384	-298	99	332	-232
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	4	151	-147	5	172	-167
1.आ.2.3 अन्य निवेश	17	226	-209	25	278	-253
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	76	1	75	109	1	108
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	52	9	43	45	29	16
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	1,165	120	1,044	1,266	126	1,140
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	1,165	107	1,055	1,262	112	1,150
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	1,125	81	1,044	1,221	85	1,136
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	38	26	11	41	27	14
1.इ.2 सामान्य सरकार	2	13	-11	5	14	-10
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	4	7	-3	6	12	-6
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	0	0	0	1	7	-6
2.2 पूंजी अंतरण	4	6	-3	5	5	-0
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	11,031	10,271	760	11,199	10,836	362
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	891	478	412	1,174	721	452
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	843	289	554	1,090	400	690
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	804	287	517	1,037	397	639
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	585	287	298	779	397	382
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	218	0	218	257	0	257
3.1.अ.2 ऋण लिखत	39	2	37	53	3	51
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	39	2	37	53	3	51
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	48	189	-141	84	322	-238
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	48	127	-79	84	172	-88
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	48	81	-33	84	119	-34
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	46	-46	0	53	-53
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	62	-62	0	150	-150
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	62	-62	0	150	-150
3.2 संविभाग निवेश	4,629	4,482	146	5,438	4,773	665
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	4,620	4,467	153	5,413	4,605	808
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	3,750	3,613	137	4,130	3,566	564
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	870	854	16	1,283	1,039	245
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	9	15	-6	25	168	-143
3.3 वित्तीय डेविटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	322	329	-7	453	401	52
3.4 अन्य निवेश	5,189	4,129	1,060	4,134	3,943	191
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमा राशियां	1,297	993	304	1,126	815	311
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	5	0	5	71	0	71
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमा राशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमा राशियां)	1,291	993	298	1,055	815	240
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	1,798	1,648	150	1,845	2,105	-260
3.4.3अ भारत को ऋण	1,403	1,254	149	1,330	1,609	-279
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	396	394	1	515	495	19
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	3	61	-59	1	26	-24
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	1,581	1,288	292	755	651	103
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	510	138	372	407	347	61
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	852	-852	0	998	-998
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	852	-852	0	998	-998
4. कुल आस्तियां / देयताएं	11,031	10,271	760	11,199	10,836	362
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	4,935	4,432	503	5,730	4,730	1,000
4.2 ऋण लिखत	5,585	4,848	737	5,062	4,762	300
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	510	990	-480	407	1,345	-938
5. निवल भूल-चूक	82	-	82	0	30	-30

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2018-19		2018				2019	
			मार्च		दिसंबर		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	169,964	399,199	157,373	378,957	166,594	386,203	169,964	399,199
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	111,122	382,105	103,734	363,190	109,875	369,544	111,122	382,105
1.2 अन्य पूंजी	58,841	17,094	53,640	15,767	56,719	16,659	58,841	17,094
2 संविभाग निवेश	4,699	260,009	3,577	272,151	2,666	245,849	4,699	260,009
2.1 इक्विटी	637	147,479	2,054	155,106	1,386	138,091	637	147,479
2.2 ऋण	4,062	112,530	1,524	117,045	1,280	107,759	4,062	112,530
3 अन्य निवेश	54,538	419,309	48,246	401,166	41,550	401,290	54,538	419,309
3.1 व्यापार ऋण	924	105,191	1,696	103,155	252	103,648	924	105,191
3.2 ऋण	9,884	168,143	8,235	159,820	6,553	160,454	9,884	168,143
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	25,158	130,644	20,790	126,456	17,211	125,997	25,158	130,644
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18,574	15,332	17,524	11,736	17,534	11,190	18,574	15,332
4 रिज़र्व्स	412,871	–	424,545	–	395,591	–	412,871	–
5 कुल आस्तियां/देयताएं	642,072	1,078,518	633,741	1,052,275	606,401	1,033,342	642,072	1,078,518
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-436,446		-418,533		-426,942		-436,446

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (मिलियन)				मूल्य (बिलियन ₹)			
	2018-19	2019			2018-19	2019		
		मार्च	अप्रैल	मई		मार्च	अप्रैल	मई
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	136.63	13.64	11.48	12.49	1,715,520.61	190,693.10	148,481.20	158,379.63
1.1 ग्राहक लेनदेन	133.30	13.35	11.23	12.22	1,184,368.12	125,551.00	93,080.66	104,886.16
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	3.31	0.29	0.25	0.26	172,513.75	23,178.34	19,372.66	19,087.66
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.027	0.003	0.002	0.003	358,638.74	41,963.75	36,027.89	34,405.81
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	3.62	0.28	0.25	0.31	1,165,510.38	103,147.77	95,078.03	108,987.82
2.1 सीबीएलओ	0.130	—	—	—	181,404.63	—	—	—
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.11	0.09	0.09	0.13	509,315.87	53,731.05	48,748.73	64,438.30
2.2.1 एकमुश्त	0.81	0.06	0.06	0.09	93,550.07	7,361.13	7,915.80	10,329.18
2.2.2 रिपो	0.216	0.017	0.016	0.022	271,249.89	18,540.59	16,857.34	24,166.31
2.3 विदेशी समाशोधन	0.09	0.02	0.02	0.02	144,515.90	27,829.33	23,975.59	29,942.82
3 पेपर समाशोधन	2.38	0.19	0.16	0.19	474,789.88	49,416.73	46,329.31	44,549.52
3.1 चेक ट्रंकेशन प्रणाली	1,123.76	99.76	89.79	92.11	82,460.65	7,658.15	7,268.12	7,170.78
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	1,111.67	99.16	89.36	91.77	81,535.92	7,610.47	7,235.33	7,136.88
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2.2 अन्य केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	—	—	—	—	—	—	—	—
4 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	12.09	0.60	0.44	0.34	924.73	47.68	32.79	33.91
4.1 ईसीएस नामे	7,113.25	727.32	731.85	683.81	258,745.44	28,878.55	23,801.05	24,834.16
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	0.93	0.02	0.03	0.03	12.60	0.09	0.09	0.09
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	5.36	0.25	0.52	0.29	132.35	10.48	11.87	7.77
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	2,318.89	242.39	203.44	217.68	227,936.08	25,470.01	20,546.69	21,277.74
4.5 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	1,752.91	190.18	185.04	183.33	15,902.57	1,762.89	1,691.97	1,804.56
5 कार्ड	16,046.26	1,462.26	1,384.27	1,397.34	45,121.45	4,000.60	3,974.05	4,139.95
5.1 क्रेडिट कार्ड	1,772.36	163.27	167.79	174.04	6,078.81	580.49	580.50	616.76
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	9.77	0.86	0.86	0.89	45.33	3.98	4.02	4.17
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	1,762.59	162.41	166.92	173.15	6,033.48	576.51	576.48	612.58
5.2 डेबिट कार्ड	14,273.90	1,298.99	1,216.48	1,223.30	39,042.64	3,420.10	3,393.55	3,523.19
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	9,859.61	891.42	808.91	815.71	33,107.89	2,889.99	2,843.96	2,946.67
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	4,414.28	407.57	407.57	407.59	5,934.75	530.11	549.58	576.52
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	4,604.34	427.24	420.97	419.00	2,128.76	185.99	185.54	182.97
6.1 एम-वॉलेट	4,139.28	384.89	380.62	367.45	1,836.55	159.90	159.75	157.27
6.2 पीपीआई कार्ड	465.00	42.35	40.35	51.54	291.34	26.09	25.79	25.70
6.3 पेपर वाउचर	0.05	0.00	0.00	0.00	0.87	—	—	—
7 मोबाइल बैंकिंग	6,200.32	872.93	881.23	841.74	29,584.07	4,401.53	4,020.18	4,850.08
8 कार्ड बकाया	971.72	971.72	932.77	873.85	—	—	—	—
8.1 क्रेडिट कार्ड	47.09	47.09	48.00	48.92	—	—	—	—
8.2 डेबिट कार्ड	924.63	924.63	884.78	824.93	—	—	—	—
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	221703	221703	227164	227227	—	—	—	—
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	3722229	3722229	3757621	3845111	—	—	—	—
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	29,027.83	2,730.50	2,638.61	2,605.07	2,910,848.56	292,600.42	242,760.11	269,289.51

टिप्पणी : पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

2.1: 5 नवंबर 2018 से सीसीआईएल ने सीबीएलओ को समाप्त कर दिया है।

2.2.3: 5 नवंबर 2018 से सिव्युरिटीज सेगमेंट के अंतर्गत त्रिपक्षीय रिपो की शुरुआत की गई है।

अवसरिक श्रृंखलाएं

सं. 44: लघु बचत

(बिलियन ₹)

योजना		2017-18	2018		2019	
			फरवरी	दिसंबर	जनवरी	फरवरी
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	728.98	59.21	104.15	85.67	98.39
	बकाया	8,039.71	7,919.97	8,806.98	8,893.96	8,991.91
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	583.32	46.20	85.79	63.58	71.30
	बकाया	5,273.10	5,197.72	5,934.32	5,997.90	6,069.20
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	171.45	15.11	29.15	23.18	23.60
	बकाया	1,092.10	1,066.94	1,301.85	1,325.03	1,348.63
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-1.62	-0.19	-0.30	-0.21	-0.19
	बकाया	31.38	30.32	29.17	28.96	28.77
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0.05	-0.68	-0.01	0.04	0.00
	बकाया	-0.43	-0.46	-0.12	-0.08	-0.08
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	16.25	5.27	10.36	9.66	9.28
	बकाया	1,816.91	1,808.01	1,897.59	1,907.25	1,916.53
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	122.64	10.39	12.32	11.90	11.84
	बकाया	417.18	405.90	520.72	532.62	544.46
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	196.33	15.00	23.17	25.08	24.51
	बकाया	992.92	973.90	1,167.28	1,192.36	1,216.87
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	598.18	590.68	676.62	689.20	701.79
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	45.97	45.59	56.17	57.34	58.24
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	61.40	60.36	68.60	68.88	69.10
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	287.37	277.27	365.89	376.94	387.74
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	78.68	1.30	11.10	-6.07	2.15
	बकाया	923.20	913.57	1,017.99	1,011.92	1,014.07
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.11
	बकाया	-0.37	-0.68	-0.37	-0.37	-0.26
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	79.43	7.90	15.00	16.23	17.32
	बकाया	2,066.76	2,059.53	2,158.15	2,175.69	2,192.57
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	-0.65	5.83	11.24	11.59	12.62
	बकाया	871.74	862.05	923.74	935.33	947.95
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-9.56	-0.01	0.05	0.09	0.03
	बकाया	-0.71	11.04	2.88	2.97	3.00
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-155.92	-12.80	-18.95	-16.55	-16.09
	बकाया	379.81	388.77	244.96	228.41	212.32
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	245.88	14.89	22.59	20.95	20.65
	बकाया	706.12	687.83	871.54	892.49	913.14
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	-0.29	0.00	0.07	0.15	0.12
	बकाया	-1.40	-1.45	-0.74	-0.59	-0.47
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-0.03	-0.01	0.00	0.00	-0.01
	बकाया	-0.64	-0.64	-0.81	-0.81	-0.82
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	111.84	111.93	116.58	117.89	117.45
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	66.23	5.11	3.36	5.86	9.77
	बकाया	699.85	662.72	714.51	720.37	730.14

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों पर प्राप्त डाटा निवल प्राप्तियां अर्थात् सकल भुगतानों और सकल प्राप्तियों का अंतर है।

स्रोत : महालेखाकार, डाक और तार।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2018				2019
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ बिलियन में)	53967.78	54556.81	56028.30	57581.03	59210.26
1. वाणिज्यिक बैंक	42.68	41.84	41.41	40.51	40.28
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.29	0.33	0.37	0.33	0.31
3. बीमाकृत कंपनियां	23.49	24.24	24.61	24.57	24.34
4. म्यूच्युअल फंड	1.00	1.13	1.41	0.64	0.35
5. सहकारी बैंक	2.57	2.59	2.51	2.38	2.29
6. वित्तीय संस्थाएं	0.90	0.93	0.97	1.01	1.05
7. कॉरपोरेट	0.91	1.09	1.01	1.05	0.97
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	4.35	3.84	3.65	3.60	3.22
9. भविष्य निधियां	5.88	5.79	5.71	5.54	5.47
10. भारतीय रिजर्व बैंक	11.62	11.63	11.76	13.81	15.27
11. अन्य	6.30	6.58	6.58	6.55	6.46
11.1 राज्य सरकार	1.91	1.97	1.99	1.97	2.00

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2018				2019
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ बिलियन में)	24288.29	24954.61	25668.33	26693.93	27772.29
1. वाणिज्यिक बैंक	35.79	35.02	34.66	34.00	33.87
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.51	0.75	0.58	0.60	0.58
3. बीमाकृत कंपनियां	34.13	34.24	33.74	33.90	33.04
4. म्यूच्युअल फंड	1.64	1.20	1.05	1.23	1.20
5. सहकारी बैंक	4.78	4.79	4.75	4.67	4.55
6. वित्तीय संस्थाएं	0.35	0.35	0.43	0.37	0.42
7. कॉरपोरेट	0.15	0.16	0.17	0.22	0.29
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.23	0.15	0.10	0.09	0.09
9. भविष्य निधियां	19.67	20.34	21.04	21.29	22.15
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	2.76	2.99	3.48	3.64	3.81
11.1 राज्य सरकार	0.05	0.06	0.07	0.07	0.11

खजाना बिल					
श्रेणी	2018				2019
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ बिलियन में)	3798.76	5280.07	5657.50	5298.26	4127.04
1. वाणिज्यिक बैंक	60.74	55.30	47.84	53.76	57.56
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.17	1.41	1.86	2.06	2.68
3. बीमाकृत कंपनियां	4.17	3.66	4.55	4.74	6.61
4. म्यूच्युअल फंड	2.27	7.03	10.69	5.65	2.78
5. सहकारी बैंक	2.42	1.29	1.20	1.21	2.48
6. वित्तीय संस्थाएं	3.55	2.36	1.67	1.88	2.49
7. कॉरपोरेट	2.45	1.88	6.67	1.86	2.23
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
9. भविष्य निधियां	0.11	0.21	0.01	0.02	0.08
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	22.12	26.87	25.50	28.72	23.10
11.1 राज्य सरकार	16.35	23.11	21.36	24.04	17.91

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्रामियां और संवितरण

(बिलियन ₹)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (स.अ.)	2018-19 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	30,002.99	32,852.10	37,606.11	42,659.69	48,579.90	53,611.81
1.1 गतिविधियां	17,142.21	18,720.62	22,012.87	25,379.05	29,324.08	32,025.64
1.1.1 राजस्व	13,944.26	14,830.18	16,682.50	18,784.17	22,525.73	24,390.87
1.1.2 पूंजी	2,785.08	3,322.62	4,120.69	5,012.13	5,857.77	6,745.79
1.1.3 ऋण	412.88	567.82	1,209.68	1,582.75	940.58	888.98
1.2 गैर गतिविधियां	12,427.83	13,667.69	15,108.10	16,726.46	18,542.53	20,762.79
1.2.1 राजस्व	11,413.65	12,695.20	13,797.27	15,552.39	17,684.36	19,839.32
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	5,342.30	5,845.42	6,480.91	7,244.48	8,166.36	8,851.50
1.2.2 पूंजी	990.37	946.87	1,273.06	1,157.75	844.41	909.08
1.2.3 ऋण	23.81	25.63	37.77	16.32	13.76	14.40
1.3 अन्य	432.95	463.79	485.14	554.17	713.29	823.38
2. कुल प्रामियां	30,013.72	31,897.37	37,780.49	42,884.32	47,718.59	52,780.35
2.1 राजस्व प्रामियां	22,114.75	23,876.93	27,483.74	31,322.01	35,923.82	41,185.41
2.1.1 कर प्रामियां	18,465.45	20,207.28	22,971.01	26,221.45	30,132.23	34,941.02
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	11,257.81	12,123.48	14,409.52	16,523.77	18,296.56	22,138.76
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	7,176.34	8,051.76	8,522.71	9,656.22	11,802.47	12,775.14
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	31.30	32.04	38.78	41.46	33.20	27.12
2.1.2 गैर-कर प्रामियां	3,649.30	3,669.65	4,512.72	5,100.56	5,791.59	6,244.38
2.1.2.1 ब्याज प्रामियां	401.62	396.22	357.79	332.20	316.10	368.35
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्रामियां	391.13	609.55	598.27	690.63	1,651.83	1,428.43
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	93.85	220.72	165.61	209.42	648.80	616.50
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	297.28	388.83	432.66	481.22	1,003.03	811.93
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	7,497.11	8,365.63	9,524.10	10,647.04	11,004.25	10,997.97
अक वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
अक.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.19	8,236.30	9,396.62	10,467.08	10,980.08	11,023.86
अक.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,358.58	-374.76	2,310.90	6,171.23	1,447.92	..
अक.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	1,081.30	-3,341.85	604.72	1,958.16	-1,448.47	..
अक.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	4,065.61	8,611.06	7,085.72	4,295.85	9,532.16	..
अक.2 बाह्य वित्तपोषण	72.92	129.33	127.48	179.97	24.18	-25.89
अख वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
अख.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.19	8,236.30	9,396.62	10,467.08	10,980.08	11,023.86
अख.1.1 बाजार उधार (निवल)	6,391.99	6,640.58	6,732.98	6,898.21	7,951.99	8,398.36
अख.1.2 लघु बचत (निवल)	-142.81	-565.80	-785.15	-1,050.38	-1,653.29	-1,434.61
अख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	312.90	343.39	352.61	456.88	406.13	474.19
अख.1.4 आरक्षित निधियां	34.63	51.09	-33.22	-64.36	6.70	31.14
अख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	255.45	275.45	134.70	177.92	168.45	159.10
अख.1.6 नकद शेष	-10.72	954.74	-174.38	-224.63	861.31	831.46
अख.1.7 अन्य	582.75	536.84	3,169.08	4,273.43	3,238.79	2,564.21
अख.2 बाह्य वित्तपोषण	72.92	129.33	127.48	179.97	24.18	-25.89
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	26.7	26.3	27.3	27.8	28.4	28.1
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्रामियां	26.7	25.6	27.4	27.9	27.9	27.7
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्रामियां	19.7	19.2	20.0	20.4	21.0	21.6
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्रामियां	16.4	16.2	16.7	17.1	17.6	18.3
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.7	6.7	6.9	6.9	6.4	5.8

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

...: उपलब्ध नहीं। आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मई 2019 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	1.40	26	12.29	22	5.22	8
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	4.70	23	2.75	6
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	0.16	31	1.73	27	1.00	24
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिजोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	-	-	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	0.58	6	2.79	6	-	-
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	5.75	21	7.45	20	1.25	3
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

- टिप्पणी :**
- राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
 - राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
 - प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
 - : नगण्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मई 2019 के दौरान			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	75.44	7.44	0.02	0
2	अरुणाचल प्रदेश	10.42	0.01	--	0
3	असम	38.01	0.47	--	30.00
4	बिहार	64.38	--	--	100.00
5	छत्तीसगढ़	39.03	--	0.01	60.00
6	गोवा	5.43	2.73	--	0
7	गुजरात	124.65	4.39	--	0
8	हरियाणा	18.91	10.96	--	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	0
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	--	--	--	0
12	कर्नाटक	35.02	--	--	65.00
13	केरल	19.59	--	--	0
14	मध्य प्रदेश	--	8.41	--	0
15	महाराष्ट्र	337.30	2.67	--	200.00
16	मणिपुर	3.43	0.91	--	0
17	मेघालय	5.57	0.27	0.09	0
18	मिज़ोरम	5.01	0.29	--	0
19	नगालैंड	13.49	0.29	--	0
20	उड़ीसा	121.97	13.21	0.77	173.95
21	पुदुचेरी	2.92	--	--	9.10
22	पंजाब	0.75	--	0.08	0
23	राजस्थान	--	--	1.29	37.92
24	तमिलनाडु	60.36	--	0.45	233.47
25	तेलंगाना	50.77	10.31	0.01	0
26	त्रिपुरा	3.00	0.05	--	8.00
27	उत्तरप्रदेश	--	--	1.80	0
28	उत्तराखंड	27.44	0.72	--	0
29	पश्चिम बंगाल	100.60	4.82	2.14	0
	कुल	1163.50	67.93	6.65	917.44

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य	2017-18		2018-19		2018-19						2019-20 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	मार्च		अप्रैल		मई		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	228.00	189.22	302.00	238.24	-	-12.19	50.00	34.84	20.00	14.17	70.00	49.00
2	अरुणाचल प्रदेश	8.88	7.03	7.19	6.93	3.19	2.93	2.11	2.11	-	-	2.11	2.11
3	असम	77.60	67.97	105.95	80.89	21.95	-3.11	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	100.00	89.08	143.00	109.03	43.00	23.84	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	81.00	81.00	129.00	129.00	39.00	39.00	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	18.00	14.00	23.50	18.50	4.50	3.50	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
7	गुजरात	240.00	157.85	369.71	274.57	82.00	65.60	33.00	33.00	20.00	20.00	53.00	53.00
8	हरियाणा	166.40	158.40	212.65	179.70	42.40	27.40	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00
9	हिमाचल प्रदेश	46.00	25.51	42.10	21.08	4.10	-2.90	4.00	4.00	2.00	2.00	6.00	6.00
10	जम्मू और कश्मीर	62.00	39.74	66.84	49.27	3.00	-4.81	8.00	2.61	3.00	3.00	11.00	5.61
11	झारखंड	60.00	48.07	55.09	40.23	10.09	3.67	-	-5.17	-	-	-	-5.17
12	कर्नाटक	220.98	173.48	396.00	313.83	70.00	10.83	-	-	-	-	-	-
13	केरल	205.00	162.03	195.00	147.84	5.00	-2.69	30.00	30.00	25.00	25.00	55.00	55.00
14	मध्य प्रदेश	150.00	131.25	204.96	149.71	32.00	0.85	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00
15	महाराष्ट्र	450.00	364.80	208.69	31.17	-	-94.57	25.00	25.00	35.00	35.00	60.00	60.00
16	मणिपुर	5.25	2.78	9.70	6.67	2.70	2.70	2.03	2.03	-	-	2.03	2.03
17	मेघालय	11.16	9.20	11.22	8.63	3.72	2.33	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	4.24	2.77	0.00	-1.23	-	-0.97	1.58	1.58	-	-	1.58	1.58
19	नगालैंड	11.35	7.66	8.22	3.55	1.72	-0.35	1.00	-1.60	-	-	1.00	-1.60
20	उड़ीसा	84.38	84.38	55.00	45.00	-	-	10.00	10.00	-	-	10.00	10.00
21	पुदुचेरी	8.25	4.88	8.25	4.75	1.75	-0.75	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	174.70	133.49	221.15	170.53	27.26	18.88	23.00	12.00	10.00	10.00	33.00	22.00
23	राजस्थान	249.14	167.77	331.78	201.86	23.22	-40.21	40.00	40.00	15.00	10.00	55.00	50.00
24	सिक्कीम	9.95	7.45	10.88	7.95	2.71	2.71	-	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	409.65	360.23	431.25	322.78	25.95	-3.03	30.00	30.00	40.00	40.00	70.00	70.00
26	तेलंगाना	246.00	218.28	267.40	221.83	20.22	11.51	15.00	4.16	25.00	20.83	40.00	25.00
27	त्रिपुरा	11.37	11.37	15.43	13.87	-	-1.56	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	416.00	371.78	460.00	333.07	60.00	4.06	-	-	-	-15.00	-	-15.00
29	उत्तराखंड	66.60	58.30	63.00	52.89	5.50	4.56	5.00	2.00	-	-	5.00	2.00
30	पश्चिम बंगाल	369.11	253.04	428.28	304.31	88.00	66.43	-	-20.00	-	-40.00	-	-60.00
	कुल	4191.00	3402.81	4783.23	3486.43	622.98	123.66	295.72	222.56	221.00	151.00	516.72	373.56

- : शून्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
- 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
- 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
- 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
- 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
- 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
- 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
- 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे- आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
- 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
- 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
- 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए हैं।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

2011-12 से जीडीपी डाटा 2011-12 के आधार पर हैं। वर्ष 2015-16 का डाटा 29 राज्यों से संबंधित हैं।

2015-16 से जीडीपी डाटा 28 फरवरी 2018 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम से संबंधित है।

जीडीपी के लिए 2016-17 (आरई) और 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 से लिए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिन के खज़ाना बिलों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते हैं।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा (<https://dbie.rbi.org.in>) पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2019	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित [@]) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर [@])	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2017-18	₹700 (सामान्य) ₹750 (डाक प्रभार सहित) ₹525 (रियायती) ₹575 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2017-18 और 2018-19 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 37, 2016	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नंस; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियाः

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपेयपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरी मंजिल, मुख्य भवन, मुम्बई - 400 001 को संबोधित होना चाहिए।
एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-86
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।